हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 मार्च, 2010

खण्ड–1, अंक–5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 11 मार्च, 2010

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(5) 19
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)50

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(5)58
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	(5) 59
खाद की अपर्याप्त सप्लाई संबंधी	
वक्तव्य–	
कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी	(5)59
वर्ष 2010–2011 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा	(5)63
बैठक का स्थगन	(5)75
वर्ष 2011–2011 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(6)77

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 11 मार्च, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1। चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the question hour.

Upgradation of Roadways Depot

***139. Shri Satpal Sangwan:** Will the Transport Minister be pleased to state—

(a) whether Haryana Roadways Charkhi Dadri Depot was downgraded to sub-depot by the department in the year 2001; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade this sub-depot to full fledge depot?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन):

(क) ही श्रीमान जी।

(ख) मामला विचाराधीन है।

Shri Satpal Sangwan: Speaker Sir, will the Transport Minister be pleased to state how that depot was downgraded and on what ground it was downgraded because at that time that depot was

plying nearly 120 buses with profit itself ?

श्री ओम प्रकाश जैनः अध्यक्ष महोदय, 2001 मे जो सरकार थी उसने यह दादरी डिपो तोडा था। इस बारे में जो रिकार्ड पर है उसके अनुसार 19.12.2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा एक रिव्यू बैठक के दोरान यह निर्णय लिया गया था कि दादरी डिपो को भिवानी डिपो का उप केन्द्र बना दिया जाए और झज्जर डिपो को पूर्ण डिपो का दर्जा दे दिया जाए। उक्त निर्णय परिवहन के हित के मद्देनजर रखते हुए लिया गया था क्योंकि 1996–97 से लेकर 2000–01 तक चरखी दादरी डिपो से हरियाणा राज्य परिवहन को बहुत अधिक हानि हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, 1996–97 से 2000–०1 के दौरान चरखी दादरी डिपो का घाटा इस प्रकार रहा है– 1996–97 में चरखी दादरी डिपो से हरियाणा राज्य परिवहन को 183. 99, 1997–98 में 300. 37, 1998 –99 में 505. 98, 1999 –2000 में 501.80, 2000 से 2001 में 513.49 लाख रुपये का घाटा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी अपने सदस्य को बताना चाहूँगा कि दादरी के अंदर डिपो की वाकई जरूरत है। मैं भी वहां पर गया था इसलिए मुझे पता है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि इस बारे में सरकार द्वारा पोजेटिव विचार किया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां पर डिपो बना दे।

श्री सतपाल सांगवानः सर, उस वक्त दादरी डिपो में 120 बसिज चला करती थी। मैं यह– क्वैश्चन देने से पहले वहां से इस बारे मे सारी इफोर्मेशन लेकर आया था इसलिए मेरी जहा तक इफोर्मेशन है

उसके मुताबिक मुझे पता है कि वहां पर इस समय कितनी बसिज हैं। सर, दस साल पहले उस डिपो से 120 बसिज चला करती थीं। अगर आज यह डिपो होता तो वहां पर 200 बसिज हो जातीं। दादरी डिपो में बसिज की बहुत कमी है। मेरे ख्याल में 50 परसैंट गांवों को आज भी बसिज कवर नहीं करती हैं। यही कारण है कि चरखी दादरी का डिपो तोड़ने के बाद हमें बहुत नुक्सान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज कितनी बसिज दादरी सब डिपो से चल रही हैं?

श्री ओ.पी.जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे मे इनको बाद में बता दूंगा।

श्री जगदीश नैय्यर: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार में हमारे होडल का जो डिपो था उसको भी इसी तरीके से तोड़ दिया गया था, क्या उसको फिर से डिपो बनाया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: जगदीश जी, मंत्री जी के लिए पूरे सूबे की जानकारी एक साथ देना पोसिबल नहीं है।

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या हरियाणा के शहरों के लिए भविष्य में ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है कि लेडीज के लिए स्पेशल बसे चलाई जाएं।

श्री अध्यक्षः भविष्य मे तो सब कुछ महिलाओं के लिए ही होगा, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। (हंसी)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं आपने सदन के कई सदस्यों की भावनाओं को उजागर कर दिया है। (हंसी)

To Open a New Co-Operative Bank

***20. Shri Krishan Lal Panwar:** Will the Co-oporation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new Co-operative Bank in Village Seenk, District Panipat; if so, the time by which the said bank is likely to be opened?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह): नहीं, श्रीमान जी।

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहकारी बैंक खोलने का क्या क्राइटेरिया है? गांव की जो कोऑपरेटिव सोसायटीज थीं सरकार ने उनको बंद करके कोऑपरेटिव अपैक्स बैंक के साथ अटैच कर दिया। मैं जानना चाहूंगा कि लोगों की दिक्कतो को देखते हुए क्या गांव मे सहकारी बेक खोले जाएंगे ताकि गांव के लोगों को कई–कई किलोमीटर दूर सुविधाओं के लिए न जाना पड़े?

श्री परमवीर सिंह. अध्यक्ष महोदय, सींक गांव के बैंक के बारे माननीय सदस्य ने जानना चाहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सहकारी समितियों के पुनर्गठन बारे मंत्री परिषद की बैठक में दिनांक

21.1.06 को निर्णय लिया गया था और इसमें यह पॉलिसी बनाई गई थी कि सहकारी बैंकों की जो शाखायें हैं वे अपेक्स बैंक के हैडक्वार्टर से सम्बद्ध होंगी। यह कैबिनेट डिसीजन है।

श्री कृष्ण लाल पंवार: स्पीकर सर, मैंने तो सिर्फ यह पूछा है कि इसका क्या क्राइटेरिया है क्योंकि मंत्री जी का जवाब न में आया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जब सीक गांव मे मुख्यमंत्री जी जनसभा करके आये थे तो इनके समक्ष लोगों ने इस बारे मे दरखास्त दी थी। उस समय लोगों ने दो मांगें रखीं थीं और दोनों मांगों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन देकर आए थे।

Mr. Speaker: No, It is not possible to remind him orally. पंवार साहब, मुख्यमंत्री जी के रोजाना कई जलसे होते हें। (विध्न) रोज 10–15 जलसे होते हैं, इतनी बात याद रख पाना संभव नहीं है। I won't allow it.

Accidents in Haryana Police

***93. Shri Krishan Pal Gurjar:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the year-wise number of accidents that occurred in the Haryana Police Department together with the yearwise details of the accidents that occurred during the period between the year, 2005 to January, 2010; and

(b) whether there is any risk cover for those who die in such accidents; if not, the reasons thereof?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):

(a) Year wise details of accidents in Haryana Police Deptt. from 2005 to January, 2010 are laid on the table of the house.

(b) All police officers/policeman who meet with accident are covered under Janta Personal Insurance Policy.

(a) Statement showing the details of accidents in Haryana Police Department during the year from 2005 to January, 2010

Year	No. of Accidents	No. of Policemen died	No. of Policemen injured
2005	32	30	4
2006	58	51	28
2007	40	35	11
2008	26	25	2
2009	46	39	11
January, 2010	4	4	-

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनता पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी कब शुरु हुई थी और कितनी अमाउंट की शुरू की थी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जनता पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी 2001 में शुरू हुई थी। श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी तो बहुत ही सीनियर और बड़े ही काबिल सदस्य हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इश्योरैंस पॉलिसी का अमाउंट नहीं बल्कि प्रीमियम का अमाउंट होता है और वह ईयर टू ईयर वैरी करता है। यह वैल्फेयर स्कीम पुलिस के इम्पलाईज के लिए हे। वर्ष 2009 में प्रति व्यक्ति इस स्कीम का प्रीमियम 31.90 रुपये है। पुलिस के कुल पर्सोनल 48407 हैं। यूनाईटिड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा यह बीमा किया जाता है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: स्पीकर सर, मंत्री जी ने प्रीमियम का पैसा तो बता दिया लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इस पॉलिसी में कितना रिस्क कवर होता हे, कितना एमाउंट मिलता है ओर इस प्रीमियम की राशि का भुगतान कोन करता है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रीमियम का एमाउंट पूछा था और वह मेंने इनको बता दिया कि प्रीमियम की राशि 31.90 रुपये है। It is a welfare measure. इसमें एक लाख का रिस्क कवर होता हे। इसके अलावा छः और रिलीफ हम उन सभी इम्पलाईज को देते हैं जो इम्पलाईज इसके लिए इंटाईटल हैं। वे रिलीफ हैं जीआईएस.. एक्स–ग्रेशिया ग्रान्ट, मंथली फाईनेंशियल असिस्टेंस, लीव इनकैशमैंट ओर डैथ–कम–ग्रेव्यूटी आदि।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मेंने मंत्री जी से यह पूछा है कि इस बीमे की राशि का प्रीमियम कौन भरता है? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि वर्ष 2001 में रिस्क कवर की राशि एक लाख रुपये थी ओर आज वर्ष 2010 में भी वही राशि है। आज महंगाई के जमाने मे एक लाख रुपये में तो साल की सब्जी भी नहीं आती। पुलिस कर्मचारियों को नाकों पर, चोराहो पर और पीसीआर. में पीछे बेठकर ड्यूटी देनी पडती हे ओर उस दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकेलिए रिस्क कवर की यह राशि बहुत कम हे। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि इस प्रीमियम की राशि को बढ़ाकर कम से कम दस लाख रुपये किया जाना। चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह प्रीमियम की 31.90 रुपये की राशि पुलिस कर्मचारियों की अप्रैल महीने की पे से डिडक्ट की जाती है। माननीय सदस्य ने कहा है कि इस राशि को बढ़ाया जाए, हम इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। यह एक अच्छा सुझाव है। (शोर एवं व्यवधान)

एक आवाज: स्पीकर सर, आप हमारी बात सुनें। (विघ्न)

Mr. Speaker: This is not the way.

आप एक सीनियर मैम्बर हें आप कम से कम चेयर की परमिशन लेकर तो बोल लें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, कुछ पुलिस कर्मचारियों की कभी किसी अपराधी का पीछा करते हुए और कभी ड्यूटी करते हुए मृत्यु हो जाती हे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इस प्रीमियम की राशि को सरकार द्वारा अदा किया जाना चाहिए।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I have noted the suggestion of the learned Member and we will seriously consider his valuable suggestion.

Shortage of Drinking Water

***138. Dr. Hari Chand Middha:** Will the Public Health Minister be pleased to state whether there is acute shortage of drinking water in Villages Jhanjh Kalan and Baroudi, District Jind; if so, the time by which the problem of drinking water in the above stated villages is likely to he solved?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, there is shortage of drinking water in some areas of both the villages. An augmentation water supply scheme is in progress at a cost of Rs. 100,63 Lacs for both the villages, which is likely to be commissioned by 31st March, 2010.

डॉ० हरिचन्द मिड्डाः अध्यक्ष महोदय, काफी समय से हमारे इलाके के लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान हें। में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उनकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब की बात बिलकुल ठीक है। इस गांव में पीने के पानी की समस्या थी। गांव के लोगो की यह मांग भी थी। डॉक्टर साहब से पहले भूतपूर्व वरिष्ठ मंत्री श्री मांगेराम गुप्ता जी ने भी इस बारे मे हमे लिखकर भेजा था और यह मांग रेज की थी। अब डॉक्टर साहब ने यह बात रेज की हे, इसलिए यह योजना मंजूर की गई है। यह एक करोड़ से ज्यादा की स्कीम है जो 31.03.2010 तक पूरी हो जायेगी। अगर उसके बाद भी कोई कमी रहती है तो डॉक्टर साहब हमें और सुझाव दे सकते हैं उनको भी हम दुरुस्त करवायेंगे। इसके अलावा मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जींद विधान सभा का जो क्षेत्र है वह सरकार की प्राथमिकता पर है। पिछली सरकार के समय में जींद विधानसभा हल्के के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1999 से फरवरी 2005 तक जन स्वास्थ्य के लिए केवल 65 लाख रुपये दिए गए थे जबकि इस समय इस क्षेत्र मे 216 लाख 2 हजार रुपये की स्कीमें चालू हैं। जींद विधानसभा के शहरी क्षेत्रो के लिए उन 6 सालों मे जब लोकदल ओर भाजपा की सरकार थी तो मात्र 37 लाख 90 हजार रुपये दिए गए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अजय जी, चिंतित हो जाते हैं, मैं तो डिवैल्पमैंट की बात कर रहा हूं। जींद के पक्षधर कौन हैं यह रिकार्ड पर आ जाने दीजिए। हमारी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने जींद विधान सभा क्षेत्र के लिए 1551 लाख 25 हजार रुपये की पीने के पानी की और सीवरेज की स्कीमें दी हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते। इनको कुछ पता ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, कल हमारे माननीय फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 'The approved norm of 40 liters per capita per day will be achieved 100% by March, 2010.' मैं यहां पर मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मेरे हल्के के खानक, ढाणी मोहू, टिटाणी गांवों मे लोग पीने के पानी की एक–एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है वे उसको किस तरह पूरा करेगें?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह पृथक प्रश्न है परन्तु माननीय सदस्या की चिन्ता जायज है। भिवानी, महेन्द्रगढ़, नारनौल, लोहारू और दादरी के कुछ इलाके ऐसे है जहां पीने के पानी की समस्या है क्योंकि टेल पर री वाटर कई बार उपलब्ध नहीं हो पाता। बहुत से एग्जिस्टंग सिस्टम भी इस समय पूरे नहीं चल पा रहे। जहां–जहां पर ये समस्याएं हैं हम वहां–वहां पर बहुत सा पैसा देकर कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाको में आखिरी छोर तक री वाटर पहुँचाकर पीने का पानी उपलब्ध करवा सके। माननीय सदस्या जी इस बारे मे स्पेसिफिक प्रश्न पूछें तो मैं उनको जवाब दे दूंगा।

चौ० परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम रो काबिल मत्री महोदय से कहना चाहूगा कि इस प्रश्न में जींद जिले के दो गांवो का जिक्र किया गया है लेकिन जींद जिले के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां आज 43 साल के बाद भी पीने का पानी नहीं है। जिसमे निडाणी, निडाणा, बढाणा, माणी, करेला और गढ़वाली के बहुत से इलाके हैं जहां खूब व्यवस्था के चलते हुए भी पीने के पानी की समस्या

है। करेला गांव मे करोड़ों रूपये की वाटर सप्लाई की स्कीम बनाई गई थी लेकिन वह स्कीम पिछले कई सालों से निल पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जींद जिले के जुलाना हल्के मे करीब 30 गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी आज भी नहीं है, क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है। अच्छा होता अगर माननीय सदस्य जुलाना विधान सभा का प्रश्न अलग से पूछ लेते तो मैं उसका जवाब बेहतर दे पाता। इस समय जुलाना विधान सभा के आकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं इसलिए ये सैपरेट प्रश्न पूछ ले तो हम इनको पूरी इन्फर्मेशन दे देंगें।

श्रीमती कविता जैन: अध्यक्ष महोदय, 12 वर्ष पूर्व हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या का प्रश्न सुन नहीं पा रहा क्योंकि अजय सिंह चौटाला जी बार–बार बीच में शोर मचाते हैं इसलिए इनको रोकिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये लोग बैठे बैठे कमैंट्री कर रहे हैं इसलिए इस बारे में आप अपनी रूलिंग दें।

Mr. Speaker: Please, no running commentary while sitting. (interuption & noise)

श्रीमती कविता जैनः माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 साल पहले जब प्रदेश में हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय सोनीपत शहर में पीने के पानी के लिए कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई थी जिसके तहत 75 प्रतिशत सोनीपत शहर मे पानी की सप्लाई दी जाती है। 12 वर्ष मे सोनीपत शहर की आबादी बहुत बढ़ गई है और आज के दिन जनता को एक-एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। सर्दियों में भी वहां पानी की कमी रहती है और लोग पानी के लिए जाम लगा देते हैं। क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सोनीपत शहर की पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं?

Mr. Speaker: Madam, it is not possible to reply. मंत्री जी के लिए यह बताना पॉसीबल नहीं है। इनके पास सारे हरियाणा की जानकारी अभी नहीं है। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, मेरे सारे सवाल लास्ट में लगे हुए हैं और अब मैं सप्लीमैंटरी पूछ रही हूं तो आप कह रहे हैं कि यह बताना पॉसीबल नहीं है। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब दे सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मंत्री जी उसी सप्लीमैंटरी का जवाब दे सकते हैं जो सवाल से रिलेटिड पूछी जाये। उस एरिया के आस-पास का सवाल पूछते तो शायद जवाब मिल जाता। मंत्री जी कम्प्यूटर तो हैं नहीं कि

उनके पास सारे सूबे की जानकारी हो और एक बटन दबाकर देख लें कि किस गांव में क्या हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान) आपको तो इस तरह जवाब देने का मौका नहीं मिला। यदि मौका मिलता तो आपको पता चलता कि किस तरह जवाब दिया जाता है। It is not possible. It is humanly impossible. मैडम जो सप्लीमैंटरी पूछ रही हें उसका कोई तुक ही नहीं हैं। कहां वह एरिया है और कहां यह एरिया है जिसकी मैडम सप्लीमैंटरी पूछ रही हैं।

Compensation to the Farmers

***64. Col. Raghbir Singh: Will** the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the farmers of villages Mai Kalan, Mai Khurd, Naurangawas Jatan, Rajputan and Dhani Gujran of Badhra constituency whose crops were damaged by hailstorm in March, 2009 have not received compensation as assured by the Government; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to grant compensation to those farmers togetherwith the time by which such compensation is likely to be granted?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री शिव चरण लाल शर्मा): जी हां, राहत राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा प्रभावित किसानों को 15.03.2010 तक बांट दी जाएगी।

कर्नल रघुबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि प्रति एकड़ के हिसाब से कितना मुआवजा दिया जायेगा? इसके साथ–साथ मंत्री जी को यह बताना भी चाहूंगा कि करीबन एक साल का समय ओलावृष्टि हुए हो

गया और एक साल से गरीब किसान सरकारी विभाग के दर–बदर चक्कर काट रहे हैं। आज मेरे सवाल पूछने के बाद स्थिति स्पष्ट हुई है कि 15 मार्च तक मुआवजा दिया जायेगा। इसलिए क्या मंत्री जी विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे कि इसमें इतना समय क्यों लगा?

श्री शिव चरण लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जिनकी फसल का नुक्सान 26 से 50 प्रतिशत तक हुआ है उनके लिए पहले गेहूं की फसल के लिए मुआवजा 1500 रूपये प्रति एकड़ रखा था जिसको अब बढ़ाकर 3000 रूपये कर दिया है और अन्य फसल के लिए पहले प्रति एकड़ 1250 रूपये मुआवजा रखा था जिसको अब बढ़ाकर 2000 रूपये कर दिया गया है। इसी तरह से जिनकी फसल का नुक्सान 51 से 75 प्रतिशत हुआ है उनके लिए पहले गेहूं की फसल के लिए मुआवजा 2250 रूपये प्रति एकड़ रखा था जिसको बढ़ाकर 4000 रूपये कर दिया गया है और अन्य फसलों के लिए 1875 रूपये प्रति एकड़ रखा गया था जिसको अब बढ़ाकर 3000 रूपये कर दिया गया है। इसी तरह से जिनकी फसल का नुक्सान 75 से 100 प्रतिशत हुआ हे उनके लिए पहले गेहूं की फसल के लिए मुआवजा 3000 रूपये रखा था जिसको अब बढ़ाकर 5000 रूपये प्रति एकड़ कर दिया गया है ओर अन्य फसलो के लिए पहले 2500 रूपये प्रति एकड़ रखा था जिसको अब बढ़ाकर 4000 रूपये कर दिया गया है।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मेरा गांव भी इस ओलावृष्टि से प्रभावित हुआ था लेकिन माननीय साथी ने उसका नाम

नहीं लिखा। शायद इनको मेरे गांव का नाम लिखने में तकलीफ होती होगी। लेकिन मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वहां पर 2000 रूपये सरसों की फसल के लिए और 3000 रूपये गेहूं की फसल के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से आधे से ज्यादा मुआवजा बंट भी चुका है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़के) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ 95 लाख 12 हजार रूपये का मुआवजा रिलीज कर दिया है और उसमें से कुछ मुआवजा बंट भी गया है। इसके अतिरिक्त जो बाकी मुआवजा बचा है वह भी मार्च और अप्रैल के महीने मे सम्पूर्ण तौर पर बंट जायेगा। इसके साथ–साथ मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा जिसकी माननीय कर्नल साहब ने चर्चा भी नहीं की है कि वर्ष 2008 का जो मुआवजा था उसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्तमंत्री जी ने विशेष तौर पर प्रावधान करके 68 करोड़ 82 लाख 35 हजार रूपये भिवानी के किसानो के लिए और 13 करोड़ 9 लाख 52 हजार रूपये हिसार के किसानों के लिए मंजूर किए हैं। इस प्रकार से 61 करोड़ 91 लाख 87 हजार रूपये का इन दोनो जिलो के किसानों के लिए इस 5 करोड़ रूपये के अलावा कल माननीय वित्त मंत्री महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार बजट में विशेष प्रावधान किया है जिसे हम तीन से पांच महीने के अन्दर–अन्दर किसानों में वितरित कर देंगे।

श्रीमती किरण चौधरी: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्स मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जैसा कि इन्होने बताया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी ऐग्री किया है कि 43 लाख रुपये का केरू ब्लॉक का जो हेलस्टॉर्म का मुआवजा रोका गया है क्या वह भी इसमें शामिल है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि 5 करोड़ 95 लाख 12 हजार रूपये मुआवजा पूरे भिवानी जिले का मुआवजा है जिसमें भिवानी जिले के मुख्तलिफ इलाके भी शामिल हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने वर्ष 2008 के मुआवजे के बारे में भी बताया जो कि लगभग 81 करोड़ 91 लाख रूपये है। माननीय सदस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जितना मुआवजा सारे भिवानी और हिसार जिले का पैंडिंग था वह भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।

डॉ० बिशन लाल सैनी: स्पीकर सर माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले समय का जितना मुआवजा पैंडिंग था वह इन्होंने सारे का सारा दे दिया है। स्पीकर सर, सितम्बर, 2008 के अंदर यमुना नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी जिसके कारण गुमथला, जठलाना जैसे यमुना के किनारे लगते सारे इलाके के गांवो के किसानों की जीरी की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उसकी खराबी की सरकारी तौर पर स्पैशल गिरदावरी भी करवाई गई थी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस इलाके के किसानो को भी उनका पैंडिंग मुआवजा दिया जायेगा?

Mr. Speaker: Saini Sahab, you just tell me that is it possible? Humanly it is not possible to reply.

Horticulture Scheme for Mewat District

***193. Shri Aftab Ahmed:** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) the details of different plans which are being executed by the Horticulture Department in Mewat District;

(b) the stage of execution of these schemes and the total area covered under these schemes; and

(c) what is the potential of the area for cultivation of additional vegetagle, medicinal plants, floriculture etc.?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह): श्रीमान जी, एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) उद्यान विभाग द्वारा जिला मेवात में निष्पादित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

(1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(2) सूक्ष्म सिंचाई योजना

(3) मेवात विकार। अभिकरण योजनाएं

(4) आधुनिक तकनीक का लोक प्रचार एवं विस्तार

(5) कृषि तकनीक प्रबंधन अभिकरण

(6) अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना

(7) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

(ख) इन योजनाओं की निष्पादित स्थिति तथा इन योजनाओ के अधीन कुल कवर किया गया क्षेत्र निम्न प्रकार से है।

क्र सं.	योजना का नाम	निष्पादित स्थिति	जनवरी, 2010 तक कुल कवर किया गया क्षेत्र (एकड़ों में)
1.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन. एच.एम)	चौथा वर्ष, 2006–07 से लागू	7863.5
2.	सूक्ष्म सिंचाई योजना (एम. आई)	चौथा वर्ष, 2006–07 से लागू	704
3.	मेवात विकास अभिकरण (एमडी.ए) योजनाएं	चौथा वर्ष, 2006–07 से लागू	2378

4	आधुनिक तकनीक का लोक प्रचार एवं विस्तार (पेल्ट)	चौथा वर्ष, 2006—07 से लागू	90
5.	कृषि तकनीक प्रबंधन अभिकरण (आत्मा)	दूसरा वर्ष 2008—09 स्पे लागू	24
6.	अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना	तीसरा वर्ष, 2007—08 से लागू	10
7.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	दूसरा वर्ष 2008—09 से लागू	625

(ग) जिला मेवात. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीप होने के कारण यहां पर बागवानी फसलों जैसे फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय पोधे एवं पौधे विकास की प्रबल सम्भावनाएं हैं। दिल्ली तथा देश के अन्य बड़े शहरों मैं इन उत्पादों के सहज विपणन की भी संभावना हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल भी आधुनिक सब्जी मण्डी तथा फूल नीलामी स्थलों के विकास के द्वारा इन उत्पादों के लिए विपणन तथा अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण की संभावनाएं तलाश रहा है।

सरदार परमवीर सिंह ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने मेवात के बारे में पूछा है कि होर्टीकल्चर के क्षेत्र में क्या—क्या स्कीमें

वहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसका साल विवरण हाऊस की टेबल पर प्लेस्ट स्टेटमैंट में दे दिया गया है। इसके मुताबिक सात स्कीमें हैं जो मेवात मे होर्टीकल्चर महकमे में चल. रही हैं। इसके अतिरिक्त उस स्टेटमैंट में यह भी बताया गया है कि ये स्कीमे कब से चल रही हैं। इसके अलावा इन्होंने इनके पौटेंशियल के बारे में भी पूछा है। इस बारे में में इनको यह बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण वहां होर्टीकल्वर के फल, फूल और सब्जियो के लिए काफी पोटेंशियल है। इसके अलावा वहां पर 2009–10 में एक सब्जी और फूल मण्डी भी सैंक्शन की गई है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इस प्रस्तावित सब्जी और फूल मण्डी के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इस मण्डी का निर्माण मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा करवाया जायेगा।

चौ० आफताब अहमदः स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे इलाके में पानी की बड़ी भारी कमी है इसलिए जो योजनायें सरकार द्वारा बागवानी महकमे के तहत यहां चलाई जा रही हैं उनका पर्याप्त प्रचार–प्रसार करते हुए उनको और प्रॉयरटी पर लेकर कम्पलीट किया जाये क्योंकि इन स्कीमो के तहत बहुत एरिया लिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का कोई ऐसा प्रोग्राम है जिससे बागवानी क्षेत्र में हमारे मेवात क्षेत्र में कम पानी से फल और सब्जियों की पैदावार हो सके? क्या मंत्री जी इसके लिए

अपने महकमे में कोई प्रावधान करवायेंगे कि इसको प्रॉयरटी पर लिया जाये?

सरदार परमवीर सिंहः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेवात में वाटर कम्युनिटी टैक्स की खरीद के लिए काफी लोगो को सबसिडीज दी गई है। इसके अलावा 704 एकड़ कृषि भूमि मे माईक्रो इरिगेशन स्कीम भी चल रही है। आर.के. वी.वाई. स्कीम में भी इम्पलीमैंट्स हैं और सारे पौधे वहाँ पर उपलब्ध करवाये जा रहे है। इसके अलावा जो 7 स्कीमें वर्ष 2006–07 से चलाई जा रही हैं उन पर 677.25 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। अगर माननीय सदस्य प्याइंट आउट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया हॉर्टीकल्चर में कवर किया जा सके। इसमें सब्सिडी काफी ज्यादा है। हम चाहेंगे कि पूरे राज्य मे ज्यादा से ज्यादा एरिया वेजिटेबल फार्मिंग में कवर हो और हमारे किसान उसका फायदा उठा सकें।

Utilization of Ventilator

***129. Smt. Sumita Singh:** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that Ventilator was purchased 4-5 years ago for the Government Hospital, Karnal; if so, the reasons as to why the said Ventilator has not been utilized so far?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): No Sir, However, 2 Nos. of Ventilators were purchased 7-8 years back. These Ventilators could not be utilized due to non availability of adequate number of trained anesthetics (doctors), as ventilators

require round the clock anesthetics and trained Intensive Care Unit (ICU) doctors.

श्रीमती सुमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि जब उनको मालूम है कि वही पर डॉक्टर ऑफ एनैस्थैटिक नहीं है तो वहाँ पर हम पहले मशीनरी क्यों खरीद लेते हैं? करनाल हॉस्पीटल मे एक बहुत ही खूबसूरत कमरा बना हुआ है जहाँ पर वेंटिलेटर ओर दो स्पेशल बैड लगे हुए हैं तथा बाहर से ताला लगा हुआ है। जब हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही उपलब्ध नहीं हैं तो मशीनरी क्यों खरीदते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगी कि वह कौन से अधिकारी हें जिन्होंने यह मशीनरी खरीदी? क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी क्योकि इससे सरकार का पैसा वेस्ट जाता है?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न उठाया है। सर, वाकई दो वेंटिलेटर हमारे करनाल हॉस्पीटल में वर्ष 2000–2002 के दोरान खरीदे गये थे। मुझे नहीं पता कि उस वक्त की सरकार की क्या मंशा थी क्योकि उस वक्त भी करनाल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। में इस बारे में बताना चाहूँगी कि अनैस्थिसीया के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पर नहीं थे लेकिन फिर भी मशीन खरीदी गई। मैं आश्वासन देना चाहूँगी कि हमारी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार, हरियाणा को हैल्थ के मामले में बहुत आगे ले जाना चाहती है और उसके लिए हमने नये मैडिकल कॉलेज भी खोले है ताकि ज्यादा

से ज्यादा डॉक्टर्स हमारे यही से निकल सके। यह बड़ा ही चिन्ता का विषय है कि इरा समय अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स कम है लेकिन हमारी सरकार ने इस बारे मे प्रयास किया है और हर महीने हम 10 तारीख को एस०सीज०, बी०सीज० केटेगरीज तथा स्पेशलिस्ट के इन्टरव्यू करते हैं ताकि इस समय हमारे पास जो स्पेशलिस्ट की कमी है उसको दूर किया जा सके।

श्रीमती सुमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले 5 साल के समय मे बहुत से डॉक्टर्स रखे गये हैं। यह भी सही है कि किसी स्पेशलिस्ट को जॉब के लिए जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता। मैं तो मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि जिन अधिकारियो ने यह मशीनरी खरीदी उनको यह पता था कि हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं हैं, उसके बावजूद भी मशीनरी खरीदी गई। क्या ऐसे अधिकारियो के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी ताकि भविष्य मे इस प्रकार की गलती न हो?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेलः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्या को बताना चाहूँगी कि हमारे पास जहाँ से भी इन्फोर्मेशन आ रही है कि मशीनरी उपलब्द है ओर जहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं वह उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास रहेगा, खास तौर से वैंटिलेटर के मामले मे वहीं से हम उस मशीनरी को उठा कर दूसरी जगह, जहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं वहाँ इसका उपयोग करेगे। पी०जी०आई०एम०एस०, रोहतक में वैंटिलेटर मशीन की कमी है। इनटैन्सिव केयर यूनिट मे इस तरह के वैंटिलेटर की जरूरत रहती है, इसलिए इस प्रकार की मशीनरी

को वहाँ पर शिफ्ट करेगे। हम इस बात की भी जाँच करवायेगे कि यह मशीनरी किस समय और कैसे खरीदी गई? इसी प्रकार से और भी जो मशीनरी स्पैशलिस्ट्स के अभाव मे यूज नहीं हो रही है हमारा यह प्रयास रहेगा कि उसको वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाये। हमने तकरीबन 1350 डॉक्टर्स की भर्ती की है जिसमें से 666 स्पेशलिस्ट हैं और यह हमारी सरकार का ऑन गोइंग प्रोसैस है।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, बहन जी यह सवाल नहीं है। सप्लीमैट्री यह है कि जिन अधिकारियो ने जानबूझकर यह मशीनरी खरीदी है और ऐक्सपर्ट नहीं थे, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेगे?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेलः अध्यक्ष महोदय, जिस दौरान इन वैंटीलेटर्ज की परचेजिंग हुई, उसकी हम पूरी जाँच करवायेगे और इस मामले में हर सम्भव कार्रवाई की जायेगी।

श्री राम पाल माजरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके घोषणा पत्र मे था कि डिस्ट्रिक्ट वाईज वैंटिलेटर लगवाएंगे। ये उनको उठाने की बजाए चलाने की बात करे। क्या यह सरकार हर जिले में वैंटिलेटर चलाने का काम करेगी ताकि जिस पेशंट को रैस्पीरेशन की जरूरत है, उसको बचाया जा सके?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त को यह पता होना चाहिए कि वैंटिलेटर मैडिकल कालेज के अन्दर उपलव्य होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलज के अन्दर नहीं होते हैं। अब यह इनकी बुद्धि की बात हे कि जहां जरूरत थी वहां पर तो लगाए नहीं,

दूसरी जगह लगा दिए। मैडिकल कालेज खाली छोड़ दिए। जिस तरह की बुद्धि है, इन्होने उसी तरह का काम किया है। We will put it in the right place.

श्री राम पाल माजरा: कैथल मे एक मिनी पी०जी०आई० होगा तब इसकी वहां पर जरूरत होगी।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो क्वैरी लगाई है, इस बारे मे मैं इनको बताना चाहूंगी कि हमारे पास इस समय एनेसथिस्टिस 74 हैं और हमारी रिक्यायरमैंट 134 की है। हमारी हरियाणा सरकार का प्रयास है कि हर सुविधा चाहे वह हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, चाहे सी०एच०सीज०, पी०एच०सीज० या सब–सैन्टर्ज में हो, हम देंगे। सर, विशेष तौर से जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्ज हैं, जनरल हास्पिटल्ज हैं उनमें हम सभी सुविधाएं दें, हम इस तरह का प्रयास कर रहे हें। जहां तक कैथल की बात की गई है, वहां हमारा मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। हम वहां पर भी पूरी की पूरी सुविधाएं देंगे। सर, मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस मानती हूं कि वहां पर स्पैशलिस्ट्स की कमी है और यह मैं आपको आश्वासन देती हूं कि वहां पर हम स्पैशलिस्ट को जरूर लगाएंगे।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहती हूं कि जो इस तरह की शिकायतें होती हैं क्या उन पर टाईम बाउन्ड मैनर में पूरी तरह से इंक्वायरी की जाएगी या नहीं? आज चार साल बीत गए हैं, क्या आगे भी इतना ही समय लगेगा?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को कहूंगी कि इस तरह की जो भी क्वैरीज और शिकायतें हैं उनके बारे में हमें लिखकर भिजवाए उन पर टाईम बाउन्ड इन्क्वायरी की जाएगी।

Repair and Construction of Roads

***85. Shri Sher Singh Barshami:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to State —

(a) the total kilometers of roads (State Highways and District roads) repaired in the areas falling under Ladwa Vidhan Sabha Constituency during the period from 1-4-2005 to date; and

(b) the total kilometers of new roads under construction/proposed to be constructed in the current and next financial year 2010-2011?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):

(a) Sir, 297.71 km of roads (State Highways and District roads) have been repaired in the area falling under Ladwa Vidhan Sabha constituency during the period from 01-04-2005 to date.

(b) Till date, 705 km of new roads have been constructed in the current financial year in Haryana State. The work plan of construction of new roads for the year 2010-11 is under consideration.

श्री शेर सिंह बडशामीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन सड़कों की रिपेयर की गई है

उनको क्या आधार मानकर रिपेयर किया गया है और जब वे सड़कें बनवाई गई क्या उनके लिए कोई समय सीमा रखी गई थी या सड़क बनाने वाले ठेकेदार से ऐग्रीमैंट किया था जब उनको बनवाया गया था?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, my learned member should know that the repair of roads is always need based. However, we have added a condition to all our contracts that for up to three years after construction of the roads, the responsibility for maintenance will be of the contractor, who will be constructing the roads.

श्री शेर सिंह बडशामी: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूछने का मतलब यही था कि किसी जगह तो सड़कों की रिपेयर इक्ट्ठी ही कर दी गई हैं और कई जगह सड़कों की ऐसी हालत हो गई है कि वे बिलकुल समाप्त हो गई हैं।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I agree. If Hon'ble Member is expressing concern, I appreciate his concern but he should give me details of those specific roads including point to point which are non-existent or where there is an urgent need for repair. I assure him on the floor of the House that I will personally see to it that those roads are repaired on priority basis. As I have already answered that earlier there was no provision regarding maintenance responsibility. Now, our Government lead by Ch. Bhupinder Singh Hooda, has ensured it. Hon'ble Chief Minister has directed us and we have added condition to all the contracts so that contractor does not run away. Up to three years now, the maintenance responsibility will be of the contractor who constructs the road, failing which he is liable to pay penalties. However, in

case of specific roads of his constituency he should write to me and I will see to it that these are repaired and if there is need for any action, we will take.

श्री राजपाल भूखडी. अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जगाधरी से पावनी जो रोड सहरवा के लिए आती है, उसको बनाते वक्त टाईम बाउंड किया गया था और इसमें यह कंडीशन भी रखी गई थी कि जिस कंट्रैक्टर ने उसको बनाया था वह पांच साल तक उसकी रिपेयर करेगा। वह सड़क टूट चुकी है मैं आदणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उस टाईम बाउंड के तहत ही उसकी रिपेयर करवायी जाएगी? मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे अधिकारियों को भी निर्देश दें कि उस सड़क को ठीक करवाया जाए।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I would request the Hon'ble Member to just now give it in writing to me. I will see to it and needful will be done.

Smt. Kiran Chaudhary: Speaker Sir, **I** would like to know from the Hon'ble Minister that how many contractors have been penalized and black listed. Secondly, I want to know whether the time period for contractors in the Pradhan Mantri Gramin Sarak Yojna is for three years or five years ?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, perhaps the learned Member has not heard correctly. The time-period is three years.

श्री शेर सिंह बडशामी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जबाव के पार्ट 'बी' मे दिया है कि हरियाणा में 705 किलोमीटर नयी सड़के

बनाने की योजना है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि वे इस बारे में जिलावाइज ब्यौरा दे दें कि किस जिले के अंदर कितनी सड़के बनाने की इनकी योजना है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, अगर मेरे काबिल दोस्त कुछ सुने तो मैं जवाब दूं। (विघ्न) सर, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने सवाल का जवाब पढ़ा नहीं है। नयी सडकें बनाने की हमारी योजना नहीं है बल्कि 705 किलोमीटर सड़कें बना दी गयी हैं। ये जवाब दोबारा से पद लें।

श्री शेर सिंह बडशामी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किस–किस जिले मे कितनी सड़के बनायी गयी हैं?

Smt. Kiran Chaudhary: Speaker Sir, (voices and interruptions)

Mr. Speaker: This is not the way. Please take your seat.

श्री शेर सिंह बडशामी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किस–किस जिले में कितने–कितने किलोमीटर सड़कें बनायी गयी हैं? अगर एक ही जिले में सारी सड़कें बना देंगे तो बाकी जिलों का क्या होगा? स्पीकर साहब, मंत्री जी को भी पता है कि किस जिले में कितनी सड़कें बनी हैं। सर, मैं यही जानना चाहता था।

श्री अध्यक्षः आपके जिले में बहुत सड़कें बनी हैं। Barshami ji, please take your seat. The Parliamentary Affairs Minister is on his legs.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो हमने सड़कें बनायी हैं वह किस–किस जिले के अंदर बनायी हैं। अगर ये इस बारे में सैपरेट नोटिस दे दें तो मैं उसका जबाव दे दूंगा। सर, इन्होंने कहा है कि मेरे हल्के लाडवा में कोई सडक नहीं बनायी है लेकिन मैं आपकी अनुमति से इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005–06 से लेकर 2009–10 तक चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स हों, चाहे रोड्स की वाईडनिग और स्ट्रैंग्थनिग हो, चाहे सी०सी० ब्लाक्स हों, चाहे एनुअल सरफेसिंग प्रीमिक्स हो और चाहे मेंटीनेंस हो, हमने पांच वर्षा के अंदर 5011 लाख रुपये इनकी कांस्टीच्यूएंसी में खर्च किए और जब इनका खुद का शासन था तब इनकी सरकार ने 2190 लाख रुपये खर्च किए थे। सर, डबल पैसा हमने खर्च किया है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐलनाबाद विधान सभा का जब उप चुनाव हो रहा था तो उस समय मुख्यमंत्री महोदय सुबह– सुबह कम्पेन के लिए गांवों के अंदर जा रहे थे

श्री अध्यक्षः आप अपनी सप्लीमैट्री पूछे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप चिंता मत करें मैं सड़क की बात ही करूंगा। जो सही सवाल है मैं उसी पर आ रहा हूं.....

श्री नरेश कुमार बादलीः अभय जी, 5 मार्च को हमारी सरकार को पूरे 5 साल हो गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः ....

Shri Randeep Singh Surjewala: This is not the way. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ये थ्रैटनिग लैंग्वेज यूज की है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। इनके यह बोलने का क्या मतलब हैं? (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)ः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सदस्य अभय चौटाला ऐसे नहीं बोल सकते। सदस्य ने जो अशोभनीय भाषा यहां बोली है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्षः श्री अभय चौटाला ने जो शब्द बोले हैं उन्हें रिकार्ड न किया जाए।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जब इलैक्शन कंपेन में ऐलनाबाद गए थे तो वहां लोगों.. (Interruptions)

Mr. Speaker: This is not the way. I won't allow it. Put the question in regard to road in a straight way. अभय चौटाला जी,

मैं आपको कमैट्री नहीं करने दूंगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के मे जब बाई इलैक्शन हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री जी कंपेन के लिए मेरे हल्के के माधोसिंहाना गांव में गए थे वहां इनसे लोग मिले और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप जिस रोड से आए हैं वह ऐलनाबाद सिरसा सड़क तो गड्डो से भरी पड़ी है, इस सड़क को क्या आप बनवाएंगे? ये वहां पर आश्वासन देकर आए थे कि इस सड़क को दोबारा से नये सिरे से बनवाने का काम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सड़क के लिए बजट में पैसा रखा गया है और क्या इसे बनाया जाएगा?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, it is a separate question. मैं निवेदन करूंगा कि ये लिखकर दें और इस बारे में आपको नोटिस दें तो इसका जवाब हम देंगे।

Veterinary Hospital at Safidon

***121. Shri Kali Ram Patwari:** Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state—

(a) whether there is any Veterinary Hospital in Safidon near Noorsar Pond; and

(b) whether any doctor is posted in the above stated hospital; if not, the reasons for not posting a doctor in this Hospital ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह):

(क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) श्रीमान् जी, सफीदों नगर में एक पशु चिकित्सालय कार्य कर रहा है तथा नूरसर तालाब इरा नगर का ही भाग है, सरकार की नीति अनुसार एक ही स्थान पर दो पशु संस्थाएँ नहीं खोली जा सकती।

श्री कली राम पटवारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां अस्पताल बना हुआ है और लोगों के अपने पैसे से बना हुआ है। जो पहले से वहां पशु अस्पताल है वह पश्चिम साइड मे पड़ता है और जो नूरसर तालाब है यह पूर्व में है। इनका फासला करीब 4 किलोमीटर का है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शहर में इतनी आबादी है उसके बीचो बीच क्या पशु जा सकते हैं? मैं सरकार से इस बारे में आश्वासन चाहूंगा कि वहां पर एक डॉक्टर नियुक्त किया जाए। (विध्न)

श्री अध्यक्षः मेरी आप सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि प्लीज–आप प्राइमरी स्कुल के बच्चो की तरह से बिहेव मत करें।

सरदार परमवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैं इस बारे में माननीय सदस्य को गवर्नमैंट की पॉलिसी से अवगत करवा चुका हूं कि म्यूनिसिपल लिमिट के तहत सफीदों टाउन में एक अस्पताल पहले से ही फंक्शन कर रहा है। सेम म्युनिसिपल लिमिट मे दूसरा अस्पताल नहीं खोला जा

सकता। जहां तक डॉक्टर की पोस्टिंग का सवाल है, वहां पहले रवे वी०एल०डी०ए० है।

श्री कली राम पटवारी: अध्यक्ष महोदय, वहां डॉक्टर की अत्यंत जरूरत है और पहले भी वहां डॉक्टर बैठा करता था। मैं सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि क्या वहां पर डॉक्टर नियुक्त किया जाएगी?

Mr. Speaker: No, no. This is not the question. ऐसे 50 हॉस्पिटल लोगों ने बना रखे हैं वहां पर डॉक्टर नहीं जा सकते। जब सरकार किसी हॉस्पिटल को खोलती है तो उसकी बिल्डिंग बनाती है, डॉक्टर की पोस्ट को सैंक्शन करती है, उरस्के बाद वहां पर डॉक्टर भेजा जाता है ऐसे किसी डॉक्टर को नहीं भेजा जा सकता।

Haryana Roadways Bus Service

***116. Shri Pardeep Chaudhary:** Will the Transport Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal to start Haryana Roadways bus Service from Nalaghat to Samlotha, Morni to Barisher and Morni to Tikartal; if so, the time by which it is likely to be started; and

(b) if not, the reasons thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन):

(क) जी नहीं, जेमान जी

(ख) इन मार्ग की सड़कों की स्थलकृति और आयाम को देखते हुए हरियाणा रोडवेज बसों को सुरक्षित चलाने की अनुमति नहीं देते।

श्री प्रदीप चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया है। वहां पर 10–10, 15–15 किलोमीटर लम्बी रोड्ज हैं और ये रोड्ज 10–15 सालो से बनी हुई हें। वहां पर पहाडी क्षेत्र हैं। चुनाव के समय वही पर लोगो को आश्वासन दे दिया जाता है कि आपके एरिया मे बसे चलने वाली हैं। चुनाव हो जाते हैं और वहां पर फिर कोई बस नहीं चलाई जाती हे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या वहां पर मिनी बसिज का प्रावधान किया जाएगा?

श्री ओम प्रकाश जैन: अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग ने नालाधाट से समलोथा तक हरियाणा रोडवेज की बस सेवा आरम्भ करने के लिए एक सर्वे किया था। उस सर्वे में यह पाया गया कि गांव काजड के निकट बिजली की तारे बहुत नीची हैं ओर गांव डुह के नजदीक वर्षा के पानी से सड़क टूटी हुई है। बर। पुल के किनारे को छूती हुई निकलती है। यह सड़क बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हे। गांव डुह को पार करने के बाद मुह मे एक कोहनी नुमा मोड़ है। वहां पर भी हरियाणा रोडवेज की बस लम्बी होने के कारण उसका मुड़ना मुश्किल हो जाता है। इन सबको देखते हुए यहां पर बस सेवा शुरू नहीं की जा सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम रो माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारी सरकार भी चाहती

है कि वहां पर बस सुविधा होनी चाहिए। जहां तक माननीय सदस्य ने मिनी बरन की बात की है तो हम किसी प्राईवेट पार्टी से बात करके कोशिश करेंगे कि वहां पर मिनी बस की सेवा शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल साथी ने जो सवाल किया है यह बात ठीक है कि वहां के लोगो को आने–जाने की काफी दिक्कत है, लेकिन हरियाणा रोडवेज की बसिज बड़ी होने के कारण वहां पर न तो वे मुड़ सकती हैं और न ठीक तरह से जा सकती हैं। हम कोशिश करके शिवालिक डिवलेपमैंट बोर्ड के साथ बातचीत करके वहां पर पांच मिनी बसिज चलवायेगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अपने जवाब मे कहा कि किसी व्यक्ति से बात करके हम बसिज चला देंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा ...... (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दे दिया है and that is over. सदन को आश्वासन दे दिया है फिर ये माननीय सदस्य ऐसी बात क्यो कर रहे हैं।

Mr. Speaker: Minister is replying. (interruptions) The Minister is speaking. आप बेठिए। मंत्री जी बोल रहे थे आप बीच में खड़े हो गए।

चौ० मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में आदरणीय चौटाला साहब ने नूंह को मेवात डिस्ट्रिक्ट बना दिया था।

श्री अध्यक्ष: इस समय मोरनी क्षेत्र की बात करो। आप मेवात के क्षेत्र की बात न करें।

चौ० मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker: No, no. Emphatically no. (interruptions). This is not the way. Nothing is to be recorded. (interruptions) I will not allow you. You are irrelevantly speaking.

Water Suply Facilities

***110. Rameshwar Dayal:** Will the Public Health Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that 60% villages of Bawal Assembly Constituency have not been provided drinking water facilities by Public Health Engineering Department; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the department to provide water supply in all the villages through Water Works in next financial year?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):

(a) No, Sir. All villages have been provided with piped drinking water supply facilities.

(b) Question does not arise.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि बावल विधान सभा के कुल 172 गांव हैं जिनमें से 43 गांव 5 कैनाल बेस्ट वाटर स्कीम्स में कवर होते हैं और 129 गांव 22 ट्यूबवैल बेस्ट वाटर स्कीम्स में कवर होते हैं। अध्यक्ष

महोदय, मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बावल पीने के पानी के लिए और इरीगेशन वाटर के लिए डिफीकल्ट एरिया रहा है। यह डिफिकल्टी वहां आज से नहीं बल्कि जब से हरियाणा बना है तब से लगातार चल रही है। जैसे –जैसे औद्योगिक क्रांति का संचार हुआ है, दिल्ली से प्रोक्सीमिटी होने के बाद बहुत ज्यादा मजदूर और काम करने वाले लोग वहां आ गए हैं, इसलिए पानी पर प्रैशर और ज्यादा बढ़ा है। 54 गांव अभी भी ऐसे हैं जो आइडैंटीफाई किए गए हैं कि वहां पानी 40 एल०पी०सी०डी० से भी कम है। बहुत से विधानसभा क्षेत्र ऐसे हें जिनकी मैंने चर्चा की है कि वे डिफीकल्ट एरियाज हैं और वहां पीने के पानी की प्रोब्लम है। झज्जर का कुछ इलाका, रिवाड़ी का थोड़ा पोर्शन, महेन्द्रगढ़ का पूरा जिला, दादरी और लोहारू के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पीने के पानी की समस्या हे और बावल उनमें से एक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल राजोरियाः स्पीकर सर, आप हमारी बात तो सुनें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः रामेश्वर दास जी, मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं। वहां के जो डिफीकल्ट ऐरियाज हैं वह हमारी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने खुद बावल विधान सभा क्षेत्र का रिव्यू लिया था। 54 गांव ऐसे हैं जहां 40 एल०पी०सी०डी० से पानी कम है। इन 54 गांवों में से 13 गांव ऐसे हैं जहां पर 255 लाख 4 हजार रुपये की लागत से विशेष ऑगमैटेशन स्कीमें हमने चालू की हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इन स्कीमो की चर्चा सदन

मे करना चाहूंगा। मैं इस बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा क्योंकि यह इनकी जिज्ञासा भी है और सदन को जानने का अधिकार भी है। मामडिया और असामपुर में 9 लाख 15 हजार रुपये का काम अलाट किया गया है और अभी काम चालू हो जाएगा। बीढावास में 6 लाख 70 हजार रुपये के ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० के काम चालू किए गए हैं। भडोरे और डामलवास के अंदर 10 लाख 25 हजार रुपये की लागत से काम चालू कर रखे हैं। लगभग 60 परसैंट काम पूरे हो गए हैं। खिजूरी मे नाबार्ड की एक बहुत बड़ी स्कीम हम लेकर आए हैं। यह गांव बहुत बड़ा है और साथ में पड़ोस का इलाका भी कवर हो जाएगा। इस स्कीम पर 193 लाख 79 हजार रुपये लागत आनी थी लेकिन थोड़ा सा एक्सपैंडीचर इस पर फालतू हो गया है। इसका 80 से 85 परसैंट काम पूरा हो गया है। परागपुर के अंदर सुलखा और परागपुर के लिए 11 लाख 70 हजार रुपये की लागत से काम शुरू किए गए हैं। मेलावास के अंदर बवानगुजर और मेलावास के लिए 10 लाख त्त हजार रुपये की लागत से काम शुरू कर दिए गए हैं। पवार और नांगल तेजू दोनों गांवों के लिए 11 लाख 20 हजार रुपये की लागत से काम मंजूर किए गए हैं। जयसिंहपुर खेड़ा में भारगी और जयसिंहपुर के लिए 11 लाख 65 हजार रुपये की लागत से काम शुरू किए हैं। माखडिया के अंदर सहवासपुर, ढ़ाणी सेतो, राजपुरा और माखडिया चारों गांवों के लिए लगभग 106 लाख रुपये की लागत से काम शुरू कर दिए गए हैं। यह स्कीम पूरी होने के नजदीक लग गई है। कुंडल के अंदर 7 लाख 95 हजार रुपये की लागत से काम शुरू किए हुए हैं। बसडूडा में 10 लाख 25 हजार रुपये की लागत से काम शुरू किए गए हैं। कमालपुर के अंदर

10 लाख रुपये की लागत से काम शुरू कर दिए गए हैं। चूड़ियावास में 10 लाख 40 हजार रुपये की लागत से काम शुरू हो गए हैं। खडौरा और रायसावास दोनों गांवों के लिए 13 लाख रुपये की लागत से काम शुरू कर दिए गए हैं। इससे ये गांव 40 एल०पी०सी०डी० से ऊपर आ जाएंगें।

Mr. Speaker: Now the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Data of Power Thefts

***73. Shri Ashok Kumar Arora:** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the district-wise data of power thefts in the State for the year 2005 to january, 2010 togetherwith the amount of penalty imposed and recovered; and

(b) the number of cases, district-wise, pending with the various courts and the amount involved in these cases?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप): सूचना के संचय मे शामिल स्रोत तथा प्रयास इस सूचना से प्राप्त लाभ के अनुरूप नहीं हैं।

Shortage of Staff

***146. Shri Charanjeet Singh Rori:** Will the Health Minister to pleased to state whether it is a fact that there is shortage of staff, essential medicines and lack of sanitation in the

Hospitals of villge Rori, Kalanwali and Baragurha of the Kalanwali Constituency, if so, the reasons thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल): श्रीमान जी, कालांवाली निर्वाचन क्षेत्र के रोड़ी, कालांवाली तथा बडागुढा गांवो के अस्पतालों में अमले की कुछ कमी है और इस सम्बन्ध मे कारणों सहित स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी जाती है।

यद्यपि, इन अस्पतालों में जरूरी दवाइयो और सफाई की कोई कमी नहीं है।

अमले की विवरण की सूची

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडागुढ़ा

क्रम संख्या	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	0	
2.	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1	शीघ्र भर लिये जाएंगे।
3.	दन्तक सर्जन	1	1	0	
4.	स्टाफ नर्स	5	4	1	पदो को मरने

					के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा हुआ है।
5.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	10	10	0	
6.	बहुउद्देशीय सुपरवाईजर कार्यकर्ता (महिला)	2	2	0	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया जा चुका है।
7.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)	15	0	15	
8.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाईजर (पुरुष)	3	3	0	
9.	ओषधाकारक	2	2	0	
10.	प्रयोगशाला	1	0	1	हरियाणा कर्मचारी चयन

	तकनीशियन				आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया जा चुका है।
11	प्रयोगशाला तकनीशियन मलेरिया	2	0	2	मांग–पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा हुआ हे।
12.	आशुटंकक	1	0	1	पदों को मरने के लिए मांग–पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा हुआ है।
13.	खण्ड विस्तार शिक्षक	1	0	1	रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान समाप्त हुए 8 पदों को रिस्टोर करने के लिए

					प्रस्ताव–पत्र सरकार को भेजा हुआ है।
14.	लिपिक	1	1	0	
15.	कम्प्यूटर क्लर्क	1	0	1	सेवा नियम संशोधन की प्रक्रिया मे
16.	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0	
17.	ड्राईवर	1	1	0	
18.	स्वीपर	1	1	0	
	कुल	53	30	23	

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोड़ी

क्रम संख्या	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1.	चिकित्सा अधिकारी	2	2	0	
2.	दन्तक सर्जन	1	1	0	

3.	ओषधाकारक	1	1	0	
4.	स्टाफ नर्स	1	0	1	पदों को भरने के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा हुआ है।
5.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	8	6	2	पदों को भरने के लिए मांग–पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा हुआ है।
6.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाईजर (महिला)	1	1	0	
7.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)	1	0	1	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया जा चुका

					है।
8.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाईजर (पुरुष)	1	1	0	
9.	सफाई कर्मचारी	1	0	1	शीघ्र भर लिये जाएंगे।
10.	चतुर्थ श्रेणी	1	1	0	
	कुल	18	13	5	

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालांवली

क्रम संख्या	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1.	चिकित्सा अधिकारी	1	1	0	
2.	एल०एम०ओ०	1	1	0	
3.	दन्तक सर्जन	1	1	0	
4.	दन्तक मेकेनिक	1	1	0	
5.	ओषधाकारक	1	1	0	
6.	स्टाफ नर्स	1	1	0	

7.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	11	7	4	पदो को भरने के लिए मांग–पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा हुआ है।
8.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाईजर (महिला)	1	1	0	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया जा चुका है।
9.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)	2	1	1	
10.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाईजर (पुरुष)	1	1	0	
11.	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	0	1	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार

					लिया जा चुका है।
12.	सफाई कर्मचारी	1	0	1	शीघ्र भर लिये जाएंगे।
13.	चतुर्थ श्रेणी	1	1	0	
	कुल	24	17	7	

Solid Waste Management Scheme

***150. Smt. Kavita Jain:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start the solid waste management scheme in Sonepat City; and

(b) if so, the draft of the above said scheme togetherwith the time by which this scheme is likely to be started; and if not, the reasons thereof?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप):

(क) ही, श्रीमान जी।

(ख) नगरपरिषद, सोनीपत ने सोनीपत शहर की ठोस कचरा प्रबन्धन योजना के लिए 14 एकड़ 4 कनाल भूमि गांव सांदल कलां, सोनीपत मे चिन्हित की है. जिसके लिए सरकार ने भू–अधिग्रहण अधिनियम, 1394 की धारा–4 व 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की है।

गांव सांदल कलां, सोनीपत के निवासियों ने उपरोक्त वर्णित अधिसूचनाओं को निरस्त करने हेतु माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। क्योकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इस योजना के प्रारम्भ करने की तिथि की प्रतिबद्धता इस स्थिति में नहीं की जा सकती।

HERC Regulation

***111. Smt. Sampat Singh:** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the details of HERC Regulations No. HERC/04/2004, dated 16-7-2004 on Standards of Performance of disribution Licensee togetherwith the time when the above said regulation was implemented by the Discoms;

(b) the total number of persons who applied for compensation under this Regulation and amount received as compensation;

(c) the format of complaint book maintained by power utilities for the consumers and weather these complaint books are checked by any senior officials/officers of the Discoms; and

(d) the number of such compaint book which were not found properly maintained when the complaint books are checked by officials/officers of the Discoms togetherwith the action taken against erring official and number thereof ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप): श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत हे।

विवरण

(ए) हर्क के रेगुलेशन नं० हर्क/04/2004, दिनांक 17–07–2004 का विवरण अनुबन्ध– 1 पर प्रस्तुत हे। रेगुलेशनों के प्रावधानो के अनुसार ये रेगूलेशन 1 फरवरी, 2005 से लागू हुई थी।

(बी) शून्य।

(सी) शिकायत पुस्तिका का फारमेट अनुबंध– 11 पर प्रस्तुत है। शिकायत पुस्तिका की नियमित रूप से वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का दौरा करते समय जांच की जाती हैं।

(डी) शून्य।

हरियाणा सरकार गजट (अतिरिक्त) जुलाई 16, 2004

(ए०एस०ए०आर० 25, 1926 साका)

अनुबन्ध– 1

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग, पंचकूला

अधिसूचना

दिनांक 16 जुलाई, 2004

अधिनियम संख्या ह०बि०नि०आ/04/2004

वितरण लाईसैन्सधारी के लिए कार्यकुशलता के मानदण्ड

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 2003 की 36) की धारा 181 की उपधारा 2 (जेड ए) एवं 2 (जेड बी) के साथ पठित धारा 57 एवं 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों तथा इस संबंध में सभी अन्य अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग इन अधिनियमों के माध्यम से वितरण लाइसैंन्सधारी के लिए कार्यकुशलता के मानदण्डों का उल्लेख करता है।

भाग– 1

सामान्य

1 लघु शीर्षक, प्रारम्भ एवं व्याख्या

(1) इन अधिनियमों को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 2004 (वितरण लाइसेन्सधारी के लिए कार्यकुशलता के मानदण्डो) के नाम से पुकारा जाए।

(2) ये अधिनियम हरियाणा राज्य में विद्युत के वितरण एवं परचून आपूर्ति में कार्यरत सभी लाइसेन्सधारियों पर लाग होंगे।

(3) इन अधिनियमों का सम्पूर्ण हरियाणा राज्य मे विस्तार होगा।

(4) ये अधिनियम हरियाणा राज्य गजट में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

(5) पंजाब सामान्य धाराएं अधिनियम, 1898(1898 का अधिनियम 1) जो हरियाणा राज्य को लाग हे, इन अधिनियमो की व्याख्या के लिए लागू होगा।

2. परिभाषाएं

2.1 इन अधिनियमों में जब तक सन्दर्भ अन्यथा हो

(क) अधिनियम से अभिप्राय हे विद्युत अधिनियम, 2003।

(ख) आपूर्ति का क्षेत्र से अभिप्राय है वह क्षेत्र जिसके अन्दर एक लाइसेन्सधारी को उसके लाइसेन्सधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया हे।

(ग) आयोग से अभिप्राय है हरियाणा विद्युत नियामक आयोग।

(घ) उपभोक्ता से अभिप्राय हे, कोई व्यक्ति जिसे एक लाईसैन्सधारी या सरकार या उस अधिनियम या अन्य नियमों जो थोड़े समय के लिए लागू हो उसके द्वारा जनता का विद्युत आपूर्ति के व्यापार में किसी व्यक्ति द्वारा उसके निजी प्रयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति की जाती हो तथा इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल हे। जिसके परिसर लाईसेन्सधारी सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति जैसा भी मामला हो, के कार्यो के साथ थोड़े समय के लिए बिजली प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़े हों।

(ड) अतिरिक्त उच्च टेंशन/अतिरिक्त उच्च वोल्टेज से अभिप्राय हे सामान्य स्थितियों के अन्तर्गत 33000 वोल्टस से अधिक वोल्टेज।

(च) उच्च टैन्शन/उच्च वोल्टेज से अभिप्राय है 400 वोल्ट से अधिक परन्तु 33000 वोल्ट्स से 400 अधिक नहीं।

(छ) लाइसेन्सधारी से अभिप्राय हे वितरण तथा/या परचून आपूर्ति लाइसेन्सधारी।

(ज) कम टेन्शन/कम वोल्टेज रवे अभिप्राय है सामान्य स्थितियो में 400 वोल्ट्स से कम वोल्टेज।

(ञ) कम भार की अवधि से अभिप्राय हे एक अवधि जिसके दोरान मांग आपूर्ति से अधिक हो तथा फालतू मांग को पूरा करने के लिए कोई स्पेयर/रिजर्व क्षमता उपलब्ध नहीं हो तथा एस०एल०डी०सी० ने लाईसैन्सधारी को निर्देश दिए हों कि भार को कम किया जाए या ओवरलोडिंग से बचा जाए। इस अवधि के दोरान लाईसेन्सधारी को उचित लोड शेडिंग पर कायम रहना चाहिए या कोई अन्य साधन अपनाने चाहिए ताकि जैसा कि नियमन मे उल्लिखित हे। उससे अधिक समय के लिए एक ही उपभोक्ता का नुकसान न हो। इसके अन्तर्गत ग्रिड के असफल होने की अवधि शामिल नहीं हे।

(ट) अनुसूची (शेडयूल्ड) आउटेज की अवधि से अभिप्राय हे इस अवधि जिसके दोरान एक उत्पादन इकाई विद्युत केन्द्र या सम्प्रेषण प्रणाली का भाग खराब होने पर या वितरण प्रणाली आवश्यक मरम्मतो

एवं एक योजनाबद्ध तरीके से बचाव अनुरक्षण करने पर केपेसिटर की कमी करनी पडे।

(ठ) इसमें प्रयोग में लाई गई सभी अभिव्यक्तियां जो इसमे विशेष रूप से परिभाषित नहीं की गई परन्तु अधिनियम में परिभाषित की गई है उनका अर्थ अधिनियम मे उनको दर्शाया गया हे, वही होगा। एतद् द्वारा यहां प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्तियां एतद् परन्तु जो इन अधिनियमो या ऐक्ट में विशिष्ठ रूप से परिभाषित नहीं की गई है परन्तु हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित की गई हैं उनका अर्थ वही होगा जो उपरोक्त अधिनियम में दिया गया हे, शर्ते कि हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 में ऐसी परिभाषाएं विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के विरुद्ध न हो।

अध्याय–2

कार्यकुशलता के मानदण्ड

कार्यकुशलता का गारन्दीशुदा एवं समग्र मानदण्ड

3.1 निर्दिष्ट कार्यकुशलता के मानदण्ड के सन्दर्भ में सेवाओं की गुणवत्ता निरन्तरता एवं विश्वसनीयता। वह होगा जो एक लाइसेन्सधारी अपने कर्त्तव्यों को निभाने में लाइसेन्सधारी के रूप मे प्राप्त करेगा। वही सेवा का न्यूनतम मानदण्ड होगा।

3.2 अनुसूची में निर्दिष्ट कार्यकुशलता के मानदण्ड कार्यकुशलता के उन गारन्टीशुदा मानदण्डों से संबंध रखते हें जिसके

लिए ऐसे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध उल्लंघन की तिथि पर कोई बकाया नहीं है वे लाईसैंसधारी द्वारा कार्यकुशलता के मानदण्डो को प्राप्त करने में असफल होने पर अनुसूची में व्यवस्थित तरीके में मुआवजा के लिए पात्र हे।

33 कृषि श्रेणी (कृषि) पम्पसेट के अन्तर्गत इच्छुक आवेदनों के मामले में लाइसेन्सधारी की बाध्यता एक वित्तीय वर्ष के लिए कृषि सम्बन्धी कनेक्शन जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निश्चित लक्ष्य के अन्दर आने वाले कनेक्शनों की संख्या तक सीमित होगी। एक आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य वर्ष के शुरू होने से कम से कम 2 महीने पूर्व निर्धारित करके जनता को सूचित किए जाने चाहिए। यदि आवेदकों का मामला वर्ष के लिए निश्चित कृषि पम्प सैट कनेक्शनो के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता तो आवेदकों के आवेदनो की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर लाईसैन्सधारी आवेदकों को लिखित मे सूचित करेगा।

34 अनुसूची–2 कार्यकुशलता के उन समग्र मानदण्डों से संबंधित हे जो लाइसैंसधारी के रूप में लाइसेन्सधारी अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में प्राप्त करने की अपेक्षा करने वाली कार्यकुशलता के स्तर को दर्शाता हैं।

4. संशोधन का अधिकार

आयोग अनुसूची 1,2,3 की विषय सूची सहित इन अधिनियमों के किसी प्रावधानों को किसी समय जोड भिन्न, परिवर्तन संशोधन या बदल सकता हे।

5. छूट

5.1 इन अधिनियमों में उल्लिखित कार्यकुशलता के मानदण्ड आकस्मिक उत्पन्न मजबूरन स्थितियो जैसे युद्ध, उपद्रव, मारकाट, दंगे, बाढ, तूफान, आसमानी बिजली गिरने, भूकम्प या लाइसेन्सधारी के नियंत्रण से परे किसी कारण उत्पन्न स्थिति तथा हड़ताल, तालाबन्दी, लाइसेन्सधारी की संस्थापनाओं एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाली आगजनी के दौरान स्थगित करेंगे।

5.2.1 आयोग सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा जो लाइसेन्सधारी या प्रभावित उपभोक्ता समूह की सुनवाई करने के बाद इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए हों यदि आयोग सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसी चूक लाइसेन्सधारी की ओर से न होकर अन्य कारणों से हुई है तथा लाइसेन्सधारी के नियंत्रण से परे है तथा आगे लाइसेन्सधारी ने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रयत्न किए हैं तो लाइसेन्सधारी को कार्यकुशलता के किसी मानदण्ड में किसी चूक के लिए उपभोक्ताओं की क्षति पूर्ति के दायित्व से मुक्ता कर सकता है।

अध्याय–3

मुआवजा

6. मुआवजा

6.1 यदि लाइसेन्सधारी अनुसूची मे निर्दिष्ट कार्यकुशलता के मानदण्डो को पूरा करने में असफल होता हे तो लाइसेन्सधारी को प्रभावित ऐसे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध उल्लंघन की तिथि पर कोई बकाया नहीं हो उनको अनुसूची–1 में कार्यकुशलता के मानदण्डों के सम्मुख दर्शाए गए मुआवजे का भुगतान करना होगा।

6.2 लाइसेन्सधारी एक उपभोक्ता की प्रत्येक शिकायत को पंजीकृत करेगा। लाइसेन्सधारी स्वतः उत्तरदायिनी मशीन के माध्यम से उपभोक्ता की प्रत्येक शिकायत के पंजीकरण को कम्प्यूट्रीकृत करेगा या किसी अन्य साधनो के द्वारा से ऐसा करके उपभोक्ता को शिकायत संख्या स्वतः सूचित करेगा।

6.3 सभी उपभोक्ताओं को उचित सेवाएं देने तथा मानदण्डो के उल्लंघन से संबंधित किसी विवाद से बचने के लिए लाइसेन्सधारी कार्यकुशलता मानदण्डो से संबंधित उपभोक्ता अनुसार रिकार्ड रखेगा।

6.4 मुआवजे की सभी भुगतान विद्युत आपूर्ति के लिए वर्तमान चालू तथा या भावी बिलो के विरुद्ध समंजन करके किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां दावेदार निगम का उपभोक्ता होने की समाप्ति की स्थिति में मुआवजा नकद/मांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि मुआवजा कार्यकुशलता के गारन्टीशुदा मानदण्डों की उल्लंघना की तिथि से 90 दिन के अन्दर किया जाएगा। यदि मुआवजा बिजली की आपूति के वर्तमान चालू

तथा/या भावी बिलों में समंजन योग्य नहीं हो तो उसे नकद/डिंमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुआवजा कार्यकुशलता को गारन्दीशुदा मानदण्डो की उल्लंघन तिथि से 90 दिन के अन्दर दिया गया है।

7 मुआवजे के भुगतान के लिए तरीका

7.1 मुआवजे के लिए दावा निम्न तरीके से निपटाया जाएगा।

72 स्वतः

इस भुगतान के तरीके के अनुसार लाइसेन्सधारी को एक विशेष मानदण्ड की अनुपालना करने पर प्रभावित उपभोक्ता को स्वतः आगामी बिलो के क्रम में मुआवजा धनराशि का भुगतान करना होगा।

7.3 दावा जो किया जाना है

भुगतान के इस तरीके में आवश्यक है कि उपभोक्ता लाइसेन्सधारी के ध्यान में लाये कि मानदण्ड की उल्लंघना हुई है तथा तदनुसार वह लाइसेन्सधारी से मुआवजे की राशि का दावा करेगा। लाइसेन्सधारी एक निर्णय लेगा तथा यदि उत्तरदायी पाया गया तो उपभोक्ता को कार्यकुशलता के एक गारन्टी शुदा मानदण्डों की उल्लंघना की तिथि से 90 दिनों के अन्दर मुआवजे का भुगतान करेगा।

अध्याय–4

सूचना देना, आदेश जारी करना

8. कार्यकुशलता के मानदण्डों पर सूचना

8.1 प्रत्येक लाइसेन्सधारी निम्नलिखित सूचना अनुसूची– 3 मे प्रस्तुत प्रोफोर्मा मे आयोग को भेजेगा।

(क) इन अधिनियमो की अनुसूची 1 एवं 2 के अन्तर्गत आने वाले मुद्दों के संबंध में प्राप्त कार्यकुशलता का स्तर त्रेमासिक प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) इन अधिनियमों के अन्तर्गत भुगतान किए गए मुआवजों की संख्या तथा प्रत्येक मामले में मुआवजे की धनराशि त्रेमासिक प्रस्तुत की जाएगी।

8.2 आयोग जैसा उचित समझे उस तरीके में कम से कम वर्ष में एक बार उपरोक्त सूचना के प्रकाशन के लिए व्यवस्था करेगा।

8.3 विश्वसनीयता सकेतिका

(क) 1998 के इलेक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियर्स संस्थान (आई०ई०ई०ई०) स्टेण्डर्डज 1366 द्वारा निम्नलिखित विश्वसनीयता/आउटेज इन्डिसिज निर्धारित की गई है, 2004–05 से आगे लाईसैन्सधारी निम्नलिखित निर्दिष्ट फार्मूला एवं तरीके के अनुसार

इन इन्डिसिज के मूल्य की रिपोर्ट की गणना तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगाः—

(1) प्रणाली औसत बाधा फ्रिक्वैंन्सी इण्डैक्स (एस०ए०आई०एफ०आई०)

(2) प्रणाली औसत बाधा अवधि इन्डैक्स (एस०ए०आई०डी०आई०)

(3) क्षणिक औसत बाधा फ्रिक्वैन्सी इण्डैक्स (एस०ए०आई०एफ०आई०)

(ख) वितरण प्रणाली विश्वसनीयता इडिसिज की गणना का तरीकाः—

वितरण लाईसैंसधारी के लिए स्टेकिंग द्वारा समग्र रूप में प्रत्येक मास आपूर्ति क्षेत्र में सभी 11 के०वी० फीडरों के लिए इन्डिसिज की गणना की जाएगी इसमें कृषि संबंधी भारों की प्रमुखता वाली शामिल नहीं होगी तथा तब उस मास में प्रत्येक फीडर के लिए सभी बाधाओं की अवधि तथा संख्यात को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इन्डिसिज को निम्नलिखित फार्मूला प्रयोग में लाते हुए गणना की जाएगी।

$$\sum^{n} (A_i{}^{*}N_i)$$

1. एस०ए०आई०एफ०आई० $\underline{\quad i = 1}$

N_t

A_i = प्रत्येक मास के लिए 1 फीडर पर आई रुकावटो (प्रत्येक 5 मिनटों से अधिक) की कुल संख्या

N_i = प्रत्येक रुकावट के कारण फीडर सहित सम्बद्ध भार

N_t = वितरण लाइसैन्सधारी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के०वी० के कुल सम्बद्ध भार

n_i = आपूर्ति की लाइसेन्स प्रदत्त क्षेत्र में 1 के०वी० फीडरो की संख्या (प्रमुख रूप से कृषि भारों की सेवारत्त को शामिल न करके)

n

$\Sigma \ (B_i{}^{*}N_i)$

2. एस०ए०आई०एफ०आई० $\underline{\quad i = 1}$

N_t

जहां

B_i = एक मास के लिए ith फीडर पर आई सभी रुकावटो की कुल अवधि

n

$\Sigma \ (C_i{}^{*}N_i)$

3. एस०ए०आई०एफ०आई० $\underline{\quad i = 1 \quad}$

N_t

C_i = मास के लिए ith फीडर पर क्षणिक रुकावटों (प्रत्येक 5 मिनटों से कम या बराबर) की कुल संख्या

नोटः फीडरों को ग्रामीण एवं शहरी में पृथक किया जाए तथा प्रत्येक मास के लिए इन्डिसिज का मूल्य पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाए। टी०आर० के कारण भार बाधाएं, विजलकट शट डाऊन इन्डिसिज की गणना करते समय हिसाब से नहीं लिया जाएगा।

(1) लाईसैन्सधारी इन इन्डिसिज की कृषि संबंधी भारों की प्रमुखता वाले फीडरो के लिए पृथक मूल्य की गणना करेगा। इन्डिसिज की गणना के लिए तरीका वही होगा जो अन्य फीडरों के मामले में है।

(2) लाईसैन्सधारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आयोग इन इन्डिसिज के लिए वार्षिक लक्ष्य स्तर अधिसूचित करेगा।

9. आदेशों तथा अभ्यास निर्देशों का जारी करना

ऐक्ट एवं इन अधिनियमों के प्रावधानो के शर्त पर आयोग समय–समय पर अनुगम किए जाने वाले नियमों एवं तरीको के क्रियान्वय से संबंधित आदेशों अभ्यास निर्देश जारी करेगा।

10. मुश्किलों को दूर करने का अधिकार–

10.1 इन अधिनियमो के प्रावधानो को कार्यारूप देने में यदि कोई मुश्किल सम्मुख आती हे तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐक्ट के प्रावधानों के प्रतिकूलन होने वाली कुछ भी करने जो मुश्किलों को दूर करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक या त्वरित है, के निर्देश दे सकता है।

10.2 इन अधिनियमों के क्रियान्वयन में आने वाली किसी मुश्किल को दूर करने के लिए लाईसैन्सधारी आयोग को एक आवेदन पत्र उचित आदेश देने के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

11 क्रियान्वयन/ ट्रान्जीशन अवधि

आयोग द्वारा पहले ही स्वीकृत दस्तावेजों के साथ सेवा देने के लिए अधिकतम समय सीमा दर्शाने वाला मानदण्ड मेल खाता हे। उसको क्रियान्वयन के लाईसैन्सधारी को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। लाईसैन्सधारी को इस अधिनियम की अधिसूचना की तिथि से आवश्यक संरचना उत्पन्न करने के लिए 6 मास की अवधि की अनुज्ञा दी जाएगी प्रणाली को पूर्णरूपेण सही तथा क्रियान्वयन योग्य बनाने के लिए प्रथम फरवरी, 2005 से मोक अभ्यास किया जाएगा। इन अधिनियमों के प्रावधानो के संदर्भ मे उपभोक्ता को मेट्रिक मुआवजा का भुगतान शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रथम अगस्त, 2005 तथा ग्रामीण उपभोक्ताओ के लिए प्रथम अगस्त, 2006 से शुरू होगा।

12. सेविंग्ज (छूट देना)

इन अधिनियमों में उपभोक्ता के अधिकारों एवं अवसरों को उपभोक्ता सुरक्षा एक्ट, 1988 (1986 का ऐक्ट 68) सहित कोई अन्य कानून के अन्तर्गत प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची– 1

कार्यकुशलता के गारन्टीशुदा मानदण्ड

क्र. सं.	सेवा की प्रकृति		मानदण्ड (सेवा के अधिकतम समय सीमा दर्शाते हुए)		प्रभावित उपभोक्ता को देय योग्य मुआवजे की धनराशि	भुगतान का तरीका
1.	सामान्य फ्यूज बन्द	शहरो एवं कस्बों में	4 घण्टो के अन्दर	शिकायत मिलने के 2 घंटे के अन्दर। यदि शिकायतकर्ता ने पूछा हो तो शिकायतकर्ता	प्रत्येक फाल्ट मामले में 100 रुपए	स्वतः
		ग्रामीण क्षेत्रों में	8 घण्टो के अन्दर		प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता	स्वतः

				को आपूर्ति बहाल करने मे लगने वाले सम्भावित समय के बारे में सूचित किया जाएगा।	को 100 रुपये	
2.	लाइन ब्रेकडाऊन	शहरों एवं कस्बों में	8 घण्टों के अन्दर (यदि पोल टूटा हो तो 12 घण्टों में)			
		ग्रामीण क्षेत्रों में	16 घण्टो के अन्दर (यदि पोल टूटा हो तो 24 घण्टों में)			
3.	वितरण ट्रांसफार्मर फेल	शहरो एवं कस्बों में	24 घण्टो के		प्रत्येक सम्भावित	स्वतः

	हो जाना		अन्दर		उपभोक्ता को प्रतिदिन 100 रुपए या उसका भाग अधिकतम 3000 रुपए की शर्त पर	
		ग्रामीण क्षेत्रों में	48 घण्टो के अन्दर			
4.	प्रमुख विद्युत फेल हो जाना जिसमें विद्युत ट्रांसफार्मर उपकरण शामिल हैं	शहरो एवं कस्बों में	7 दिनों के अन्दर			
		ग्रामीण क्षेत्रों	24			

		में	घण्टों के अन्दर विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाएं।			
5	लोड शैडिंग अवधि	लगातार 4 दिनों के लिए 4 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं	सामान्य आपूर्ति 72 घंटों मे बहाल की जानी है		प्रत्येक सम्भावित उपभोक्ता को प्रतिदिन 100 रुपए या उसका भाग अधिकतम 3000 रुपए की	स्वतः

					शर्त पर	
6.	निर्धारित आऊटेजिज की अवधि	एक समय पर अधिकतम	किसी भी दिन 8 घंटो से अधिक नहीं	उपभोक्ता को 24 घंटे पूर्व सूचना दी जाए	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को 200 रुपए	स्वतः
		आपूर्ति बहाल करना	किसी भी दिन 6 बजे सायं तक			
7.	वोलटेज भिन्नातए = +/−6% एलटी = +6% एचवी= +10% एवं − 9%	जहां कोई विस्तार कार्य शामिल न हो	शहरों एवं कस्बो में 4 घंटे के अन्दर तथा	शिकायत प्राप्ति के 2 घंटे के अन्दर	डिफाल्ट के प्रत्येक मामले में 100 रुपए	स्वतः
			ग्रामीण क्षेत्र 8 घण्टो के	शिकायतकर्ता को शिकायत निवारण मे		

	ईएचवी = + 10% एवं –12. 5%		अन्दर	लगने वाले सम्भावित समय के बारे में सूचित किया जाएगा।		
		जहां एलटी वितरण प्रणाली का अपग्रेडेशन की आवश्यकता है	60 दिनों के अन्दर		प्रत्येक सम्भावित उपभोक्ता को प्रतिदिन 100 रुपए या उसका भाग अधिकतम 3000 रुपए की शर्त पर	
		जहां उच्च टेन्शन/ईएचटी	180 दिनों के			

		वितरण प्रणाली का अप ग्रेडेशन की आवश्यकता है	अन्दर			
		आपूर्ति वोल्टेज की 2ः से अधिक न्यूट्रल तथा न्यूट्रल वोल्टेज का खोलना	4 घण्टों के अन्दर		डिफाल्ट के प्रत्येक मामले में 100 रुपए	
8	मीटर शिकायत से	सही होने को निरीक्षण तथा चौक करना	मीटर टैस्टिंग फिस की प्राप्ति के 7 के अन्दर		देरी के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपए अधिकतम 3000 रुपए की शर्त पर	स्वतः
		धीमे / तीव्र मीटरों का	चौकिंग पर ऐसा पाये जाने के 7 दिनों के			

		बदलना	अन्दर		
		रुके हुए की क्रीपिंग को बदलना	चौकिंग पर ऐसा पाये जाने के 7 दिनो के अन्दर		
		यदि उपभोक्ता का कसूर न हो तो जले हुए मीटर को बदलना	शिकायत प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर	डिफाल्ट प्रत्येक मामले में 200 रुपये मे	स्वतः
		अन्य सभी मामलों मे जले हुए मीटरो का बदलना		उपभोक्ता द्वारा प्रभारो के भुगतान के 24 घण्टो के अन्दर	
9.	नये कनैक्शन/अतिरिक्त भार/अस्थाई कनैक्शन के	जहां नेटवर्क से आपूर्ति करने का औचित्य बनता	निर्धारित प्रभारों सिहत सभी तरह सो प्रर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति	एक्ट भाग 44 तथा अधिकतम	स्वतः

	लिए आवेदन पत्र	है वहां आपूर्ति जारी करना	के एक मास के अन्दर	3000 रुपए की शर्त पर डिफाल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपए	
		कनेक्शन देने के लिए वितरण नेटवर्क विस्तार/नये उपकेन्द्र की स्थापना की आवश्यकता है वहां बिजली की आपूर्ति जारी करना	विस्तार/ सथापना के बाद बाद शीघ्र या आयोग द्वारा जैसा निर्दिष्ट किया गया हो उस अवधि के अन्दर	एक्ट के भाग 44 की शर्त पर एलटी के मामले में 200 रुपए प्रतिदिन एचटी एवं इएचटी के मामले	दावा किया जाना है

				में 500 रुपए प्रतिदिन तथा नये उपकेन्द्र की स्थापना में डिफाल्ट के मामले में 1000 रुपए प्रतिदिन	
		कृषि पम्प सैटों	वरिष्ठता प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के अन्दर (नये कनैक्शनों की संख्या वर्ष के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य पर सीमित होंगे)	एक्ट के भाग 44 तथा अधिकतम 30 दिनों रुपए की शर्त पर डिफाल्ट के	स्वतः

				प्रतिदिन के लिए 100 रुपए	
10.	मालिकाना का ट्रांसफर करना, श्रेणी का बदल जाना		सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति के 7 दिनो के अन्दर	अधिकतम 3000 रुपए की शर्त पर डिफाल्ट के प्रतिदिन के लिए 100 रुपए	स्वतः
11.	एलटी सिगल फेश से एल थ्री फेश का कन्वर्शन, एलटी से एचटी तथा विपरीत (वाइस वरसा) कन्वर्शन		प्रभारो के भुगतान की तिथि से 30 दिनों के अन्दर	अधिकतम 3000 रुपए की शर्त पर डिफाल्ट के प्रतिदिन	स्वत

				के लिए 100 रुपए	
12.	उपभोक्ता की बिलों से संबंधित शिकायतों का निपटान करना	यदि कोई अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता नहीं है	शिकायत प्राप्ति के 24 घण्टो के अन्दर	अधिकतम 3000 रुपए की शर्त पर डिफाल्ट के प्रतिदिन के लिए 100 रुपए	
		यदि अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है	शिकायत प्राप्ति के 7 दिनो के अन्दर के अन्दर		
13.	कनैक्शन कटने के बाद आपूर्ति को पुनः कनैक्शन देना	शहरों तथा कस्बों में	उपभोक्ता भुगतान प्राप्ति के 6 घण्टो के अन्दर	अधिकतम 3000 रुपए की शर्त पर डिफाल्ट के प्रतिदिन के लिए	स्वतः
		ग्रामीण क्षेत्रों में	उपभोक्ता के भुगतान की प्राप्ति के 12 घण्टों के अन्दर		

				100 रुपए	
14.	अग्रिम उपभोक्ता डिपोजिट/उपयोग प्रतिभूति मीटर प्रतिभूति का वापस भुगतान (रिफंड) करना		अनुरोध की प्राप्ति 30 दिन के अन्दर	अधिकतम 3000 रुपए की शर्त पर डिफाल्ट के प्रतिदिन के लिए 100 रुपए	दावा किया जाना है
15	अनापति प्रमाण पत्र करना		अनुरोध कि प्राप्ति के अगले दिने सायं 5 बजे तक	अधिकतम 3000 रुपए की शर्त पर डिफाल्ट के प्रतिदिन के लिए 100	दावा किया जाना जाना है

				रुपए	
16	मोटर/ सर्विस कनैक्शन की शिफ्टिंग	मोटर/ सर्विस कनैक्शन की शिफ्टिंग	निर्धारित प्रभारों सहित अनुरोध प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर	अधिकतम 3000 रुपए की शर्त पर डिफाल्ट के प्रतिदिन के 100 रुपए	स्वतः
	लाइन/उपकरण	एलटी/एचटी लाइनों की शिफ्टिंग	निर्धारित प्रभारों के साथ अनुरोध प्राप्ति के बाद 45 दिनों के अन्दर		दावा किया जाना है
		ट्रांसफार्मर संरचना की शिफ्टिंग	अनुरोध प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर		

अनुसूची– 2

कार्यकुशलता के समग्र मानदण्ड

क्र. सं	सेवा की प्रकृति		मानदण्ड (सेवा देने के लिए समय सीमा दर्शाते हुए)	कार्यकुशलता का समग्र मानदण्ड
1.	सामान्य फ्यूज बन्द	शहरो एवं कस्बो मे	4 घण्टों के अन्दर	99%

		ग्रामीण क्षेत्रो मे	8 घण्टों के अन्दर	
2.	लाइन ब्रेकडाऊन	शहरो एवं कस्बों मे	8 घंटो के अन्दर (यदि पोल टूटा हुआ हो तो 12 घण्टो में)	95%
		ग्रामीण क्षेत्रो में	16 घंटो के अन्दर (यदि पोल टूटा हुआ हो तो 24 घण्टो मे)	
3.	वितरण ट्रांसफार्मर असफल होने पर	शहरो एवं कस्बो में	24 घण्टो के अन्दर	95%
		ग्रामीण क्षेत्रों में	48 घण्टो के अन्दर	
4.	विद्युत ट्रांसफार्मर /उपकरण इत्यादि सहित वृहद विद्युत असफल होने	शहरो एवं कस्बो में	7 दिनो के अन्दर प्रभावित क्षेत्र को बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 24 घंटों के	95%

	पर		अन्दर वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाने हैं ।	
		ग्रामीण क्षेत्रों मे		
5.	लोड शेडिंग की अवधि	4 दिनो के लिए निरन्तर प्रतिदिन 4 घंटो से अधिक नहीं	72 घंटों के अन्दर–अन्दर सामान्य आपूति बहाल की जानी है ।	95%
6.	निर्धारित आऊटेजिज की अवधि	एक समय पर अधिकतम	किसी भी दिन 8 घंटो से अधिक नहीं	99%
		आपूर्ति बहाल करना	किसी भी दिन 6 बजे सायं तक	
7.	वोल्टेज भिन्नताएं	जहां नेटवर्क का कोई विस्तार आवश्यक न हो	शहरो एवं कस्बा में 4 घंटे के अन्दर तथा ग्रामीण क्षेत्रो में 8 घण्टों के	95%

			अन्दर	
		जहां एलटी वितरण प्रणाली का अपग्रेडेशन की आवश्यकता है	60 दिनो के अन्दर	90%
		जहां उच्च टेन्शन/ईएचटी वितरण प्रणाली की अपग्रेडेशन की आवश्यकता है	180 दिनो के अन्दर	85%
		आपूर्ति वोल्टेज से अधिक न्यूट्रल तथा	4 घण्टों के अन्दर	99%

		न्यूट्रल वोल्टेज का खोलना		
8.	मीटर शिकायत से	सही होने को निरीक्षण तथा चेक करना	मीटर टैस्टिंग फीस की प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर	95%
		धीमे/तीव्र मीटरो का बदलना	चौकिंग मे ऐसा हुआ पाये के 7 दिनों के अन्दर	
		रुके हुए की क्रीपिंग को बदलना	शिकायत मिलने के 7 दिनों के अन्दर	
		उपभोक्ता का कसूर न हो तो जले हुए मीटर को बदलना	शिकायत प्राप्ति के 7 दिनो के अन्दर	
		अन्य सभी मामलो में	उपभोक्ता द्वारा प्रभारो के	

		जले हुए मीटरों का बदलना	भुगतान के 24 घण्टों के अन्दर	
9.	नये कनैक्शन/ अतिरिक्त भार / अस्थाई कनैक्शन के लिए आवेदन पत्र	जहा वर्तमान नेटवर्क से सेवा देने का औचित्य है वहां आपूर्ति जारी कर दी जाती है	निर्धारित प्रभारी सहित सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति के एक मास के अन्दर	95%
		कनैक्शन देने के लिए वितरण नैटवर्क विस्तार/ नये उप केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता है वहां	विस्तार/स्थापना या ऐसी अवधि जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई हे के पश्चात शीघ्र	95%

		बिजली की आपूर्ति जारी करना		
		कृषि पम्प सेटों	वरिष्ठता प्राप्त करने के बाद 30 दिनो के अन्दर (नये कनैक्शनों की संख्या वर्ष के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य पर सीमित होंगे)	80%
10	मालिकाना का ट्रांसफर करना, श्रेणी का बदल जाना		सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्रों की प्राप्ति के 7 दिनो के अन्दर	99%
11.	एलटी सिंगल फेश से एल थी फेश का कन्वर्शन, एलटी से एचटी तथा विपरीत (वाईस वरसा) कन्वर्शन		प्रभारो के भुगतान की तिथि से 30 दिनों के अन्दर	99%

12.	उपभोक्ता को बिलों से संबंधित शिकायतो का निपटान करना	यदि अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता नहीं है	शिकायत प्राप्ति के 24 घण्टों के अन्दर	99%
		यदि अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है	शिकायत प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर	99%
13.	कनैक्शन कटने के बाद आपूर्ति को पुनः कनैक्शन देना	शहरों तथा कस्बों में	उपभोक्ता के भुगतान प्राप्ति के 6 घण्टों के अन्दर	99%
		ग्रामीण क्षेत्रा मे	उपभोक्ता के भुगतान प्राप्ति के 12 घण्टों के अन्दर	99%
14.	अग्रिम उपभोक्ता डिपाजिटस/उपभोग प्रतिभूति मीटर प्रतिभूति का वापस भुगतान (रिफंड) करना		उपभोक्ता से प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के पश्चात 30 दिनों के	

			अन्दर	
15.	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना		प्रार्थना की प्राप्ति के अगले दिन सायं 5 बजे तक	99%
16.	मीटर / सर्विस कनैक्शन / लाईनों उपकरणों की शिफ्टिंग	मीटर / सर्विस कनैक्शन शिफ्टिंग	निर्धारित प्रभारों सहित प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के पश्चात 15 दिनो के अन्दर–अन्दर	95%
		एलटी / एचटी लाइनों की शिफ्टिंग	निर्धारित प्रभारों सहित प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के पश्चात 45 दिनो के अन्दर	
		ट्रांसफार्मर संरचना की शिफ्टिंग	निर्धारित प्रभारो सहित प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के पश्चात 60 दिनो के अन्दर–अन्दर	

17.	वितरण ट्रांसफार्मर असफल होने पर	शहरी क्षेत्र में		50% वार्षिक से अधिक नहीं होगा
		ग्रामीण क्षेत्र में		10% वार्षिक से अधिक नहीं होगा
18.	दोषयुक्त मोटरों (एम.एन.आर., जले हुए, कम चलने वाले इत्यादि)			मीटर वाली संस्थापनाओं की 1ः से अधिक नहीं
19.	बिलिंग त्रुटियां			बिल जारी किए उपभोक्ताओं का ०.1ः से अधिक नहीं
20.	आपूर्ति प्याइंट पर वोल्टेज भिन्नताएं			वोल्टेज भिन्नताएं निम्न प्रकार से निर्धारित सीमाओं मे

				रहेंगी । ए) एलटी सिस्टम +6% से –6% के बीच बी) एचटी सिस्टम +6% से –9% के बीच सी) ईएचटी सिस्टम +10% से 12.5% के बीच
21.	विश्वसनीयता इन्डिसज	निम्न उल्लिखित विश्वसनीयता इन्डिसिज शहरी एवं ग्रामीण फीडरों के लिए पृथक रूप से पूर्ण किए जाएंगे ए) 11 केवी फीडों मे बाधाओं		आयोग बाद मे पृथक रूप से मानदण्ड निर्धारित

		की औसत संख्या बी) 11 केवी फीडों मे बाधाओं की औसत अवधि सी) प्रति उपभोक्ता बाधाओं की औसत संख्या डी) प्रति उपभोक्ता बाधाओं की औसत अवधि	करेगा ।

अनुसूची– 3

कार्यकुशलता के समग्र मानदण्ड

लाइसैन्सधारी

लाइसेन्सधारी का नाम .... मास के लिए रिपोर्ट

सर्विस की कुल संख्या

वितरण ट्रांसफार्मरो की कुल संख्या

क्र. सं	सेवा की प्रकृति	प्राप्त शिकायतों की संख्या	कार्यवाही की गई शिकाय	अटैंडिंग प्रतिशतता	समग्र कार्यकुशलता के मानदण्ड

				तों की संख्या		
1.	सामान्य फ्यूज बन्द	शहरो एवं कस्बो मे				99%
		ग्रामीण क्षेत्रो में				
2.	लाइन ब्रेकडाऊन	शहरो एवं कस्बो मे				95%
		ग्रामीण क्षेत्रो में				
3.	वितरण ट्रांसफार्मरों की असफल	शहरो एवं कस्बो मे				95%
		ग्रामीण क्षेत्रो में				
4.	विद्युत ट्रांसफार्मर, उपकरण इत्यादि सहित बृहद विद्युत फेल होना	शहरो एवं कस्बो मे				95%
		ग्रामीण क्षेत्रो में				

5.	लोड शेडिंग की अवधि	4 दिनों के लिए निरन्तर प्रतिदिन 4 घंटों से अधिक नहीं				95%
6.	निर्धारित आऊटेजिज की अवधि	एक समय पर अधिकतम				99%
		आपूर्ति का बहाल करना				
7.	वोल्टेज भिन्नताएं	जहां नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता नहीं है				95%
		जहां एल टी वितरण				90%

		प्रणाली प्रणाली का अपग्रेडेशन की आवश्यकता है				
		जहां एच टी/ईएच टी वितरण प्रणाली की अपग्रेडेशन आवश्यकता है				85%
		आपूर्ति वोल्टेज की 2% से अधिक न्यूट्रल तथा न्यूट्रल वोल्टेज				99%

		की ओपनिंग				
8.	मीटर शिकायतें	सही होने का निरीक्षण तथा चेक करना				95%
		कम/अधिक चलने वाले मीटरो को बदलना				
		रुके हुए की क्रीपिंग को बदलना				
		यदि उपभोक्ता का कसूर न हो तो जले हुए				

		मीटर को बदलना				
		अन्य सभी मामलो में जले हुए मीटरों को बदलना				
9.	नये कनैक्शन/ अतिरिक्त भार/ अस्थाई कनैक्शन के लिए आवेदन पत्र	कनैक्शन देने के लिए वितरण नेटवर्क विस्तार / नये उपकेन्द्र की स्थापना की आवश्यकता है वहां बिजली				95%

		आपूर्ति जारी करना				95%
		कृषि पम्प सैटों				80%
10.	मालिकाना का ट्रांसफर करना, श्रेणी का बदल जाना					99%
11.	एलटी सिंगल फेश से एल थ्री फेश का कन्वर्शन, एलटी से एचटी तथा विपरीत (वाईस वरसा) कन्वर्शन					99%
12.	उपभोक्ता बिलों संबंधित शिकायतों का निपटान करना	यदि अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता नहीं है				99%
		यदि अतिरिक्त सूचना की आवश्यकत				99%

		ा है				
13.	कनैक्शन कटने के बाद आपूर्ति को पुनः कनेक्शन देना	शहरो तथा कस्बो मे				99%
		ग्रामीण क्षेत्रो में				99%
14.	अग्रिम उपभोक्ता प्रतिभूति मीटर भुगतान (रिफंड)	डिपोजिटस/उपभोग प्रतिभूति का वापस करना				
15.	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना					99%
16.	मीटर/सर्विस कनैक्शन/लाइनो/उपकरणों की शिफ्टिंग करना	मीटर/सर्विस कनेक्शन की शिफ्टिंग				95%

		एलटी / एचटी लाइनों की शिफ्टिंग				
		ट्रांसफार्मर संरचना की शिफ्टिंग				
17.	वितरण ट्रांसफार्मरो का फेल होना	शहरो तथा कस्बों मे				5% वार्षिक से अधिक नहीं होंगे
		ग्रामीण क्षेत्रो में				10% वार्षिक से अधिक नहीं होंगे
18.	दोषयुक्त मीटरो (एम. एन. आर., जले हुए. कम चलने वाले इत्यादि)					मीटर लगी संस्थापनाओं की 1% से अधिक

						नहीं होगा
19.	बिलिंग त्रुटियां					बिल जारी किए उपभोक्ताओ का 0.1% से अधिक नहीं
20.	आपूर्ति प्याइंट पर वोल्टेज भिन्नताएं					वोल्टेज भिन्नताएं निम्न निर्धारित सीमा के अन्दर–अन्दर होगी। ए) एलटी सिस्टम +6% से 6% के बीच बी)

						एचटी सिस्टम +6% से –9% के बीच सी) ईएचटी सिस्टम +10% से 12.5% के बीच
21.	विश्वसनीयता इन्डिसिज	निम्न उल्लिखित विश्वसनीयता इन्डिसिज शहरी एवं ग्रामीण फीडरों के लिए पृथक रूप से पूर्ण किए जाएंगे ए) 11 केवी फीडों में बाधाओं की औसत संख्या बी) 11 केवी फीडों में बाधाओं की औसत अवधि सी) प्रति उपभोक्ता बाधाओं की औसत संख्या डी) प्रति उपभोक्ता बाधाओं की औसत अवधि				आयोग बाद मे पृथक रूप से मानदण्ड निर्धारित करेगा ।

अनुबंध–3

शिकायत पुस्तिकाओं का फारमेट

क्र सं०	शिकायत का नाम	पता	शिकायती का टेलीफोन नं.	शिकायत की प्रवृति	उप मंडल का नाम	शिकायत दर्ज करने तिथि व समय	प्राप्तकर्ता	अग्रेषितकर्ता	तिथि एवं समय	निपटान की तिथि व समय	शिकायत की कार्यवाही में लिया गया समय

Number of Posts Lying Vacant in the State

***13. Shri Ram Pal Majra: Will** the Education Minister be pleased to state the category-wise details of total number of posts ofJ.B.T. teachers, C&V. Masters, Lecturers, Headmasters and Principals lying vacant in the State?

शिक्षामंत्री (श्रीमती गीता भुक्कलमातनहेल) श्रीमान जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

अध्यापकों के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार से है –

क्रमांक	पद का नाम	कुल रिक्त पद	सामान्य	अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति	भूतपूर्व सेनिक /आश्रित	विकलांग
1	प्राचार्य	295						--
	सीधी भर्ती	116	70	24		11	07	04
	पदोन्नति	179						--
2	मुख्याध्यापक	569						--

	सीधी भर्ती	04		04		-	--	--
	पदोन्नति	565		-		-		
3.	प्राध्यापक	3028				--	-	--
	सीधी भर्ती	1518	941	304		152	76	45
	पदोन्नति	1510	1510			--		
					बी०सी०ए०	बी०सी०बी०		
4	मास्टर	9142	-			--		
	सीधी भर्ती	4085	2043	817	654	449		122
	पदोन्नति	5057	4046	1011				--
5	सी०एंड०वी० अध्यापक	6649			-			
	सीधी भर्ती	5280	2640	1050	840	570	158	22
	पदोन्नति	1369	689	260	210	150	42	18
8	जे०बी०टी० अध्यापक	11129	4820	2127	1640	1160	733	649

Shortage of Drinking Water

***159. Shri Jagdish Nayar:** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is shortage of drinking water in the Villages, Banchari, Saundah, Hodal City, Dhadak, Boshka and Garhi Patti Hodal of Hodal Constituency; if so, the steps being taken by the Government for the proper arrangements of drinking water in the said villages?

लोकनिर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) नहीं श्रीमान, गांव ढाडक को छोड़ कर, जिसकी पेयजल आपूर्ति में सुधार करने के लिए 12.50 लाख रुपए की लागत से बूस्टिंग स्टेशन बनाने की एक योजना पर अगले वित्त वर्ष में कार्य शुरू किया जाएगा।

Mutation and Registration of Sale Deeds etc.

***32. Shri Anil Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) Whether it is a fact that building site plans, mutation and registration of sale deeds are not being sanctioned for the last four years in Ambala Cantt. Municipal Council; and

(b) If so, the reasons thereof togetherwith the time by which the aforesaid process is likely to be started again?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त 32(क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

Shortage of Drinking Water

***166. Shri Ghanshyam Saraf:** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is shortage of drinking water in the villages of Bhiwani Constituency; if so, the steps being taken to meet out the shortage of drinking water?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): जी हां श्रीमान्, भिवानी निर्वाचन क्षेत्र के 26 गांवों में से 3 गांवों, नामतः बामला, फूलपुरा ओर नौरंगाबाद में पीने के पानी की कमी है। इन तीन गांवों के लिए 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की एक बढ़ोतरी योजना प्रगति पर है, जिसके 31 दिसम्बर, 2010 तक पूरा होने की संभावना है।

Plying of Buses

***51. Smt. Kiran Choudhry:** Will the Transport Minister be pleased to state whether Haryana Roadways is plying buses to all the villages of Tosham Constituency regularly; if so, the details thereof?

पविहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन): हरियाणा रोडवेज तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के 74 गांवों मे नियमित बस सेवा प्रदान कर रहा हे, इसकी विस्तृत जानकारी अनुछेद में दी गई है।

अनुच्छेद

तोशाम विधान सभा क्षेत्र में आने वाले निम्नलिखित गांवों में हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा बस सेवा उपलब्ध करवाई जा रही हे, जिनकी सूची इस प्रकार है

क्र. सं.	गांव का नाम	राज्य परिवहन सेवा	ट्रिप
1	ढांणी मिरान	एच० आर०, भिवानी	10
2.	मिरान	एच० आर०, भिवानी	10
3.	ढाणी दरियापुर	एच० आर०, भिवानी	8
4.	चनाना	एच० आर०, हिसार	8
5.	दरियापुर	एच० आर०, हिसार	2
6.	छपार जोगीयान	एच० आर०, हिसार	2
7.	गारनपुरा कलां	एच० आर०, हिसार	2
8.	गारनपुरा खुर्द	एच० आर०, हिसार	2
9.	छपार रागडान	एच० आर०, भिवानी	10
10.	झुली	एच० आर०, भिवानी	8
11.	सिडाण	एच० आर०, भिवानी	8
12.	भेरा	एच० आर०, भिवानी	8

13.	देवावास	एच० आर०, भिवानी	8
14.	ईसरवाल	एच० आर०, भिवानी	14
15.	कतवार	एच० आर०, भिवानी	14
16.	खावा	एच० आर०, भिवानी	4
17.	मंडाण	एच० आर०, भिवानी	8
18.	जेनावास	एच० आर०, भिवानी	.4
19.	भारीवास	एच० आर०, भिवानी	10
18.	पटौदी खुर्द	एच० आर०, भिवानी	14
21.	थिलोड	एच० आर०, भिवानी	14
22.	सरल	एच० आर०, भिवानी	10
23.	झावरी	एच० आर०, भिवानी	20
24.	खरकडी माखवान	एच० आर०, भिवानी	20
25.	आलमपुर	एच० आर०. भिवानी	10
26	सुंगरपुर	एच० आर०, भिवानी	10
27.	रांडवा	एच० आर०, भिवानी	4

28.	बुसान	एच० आर०. भिवानी	6
29	साहलेवाला	एच० आर०, भिवाना	4
30.	रोडा	एच० आर०, भिवानी	14
31	हसान	एच० आर०, भिवानी	16
32.	देवराला	एच० आर०, भिवानी	10
33.	खापड्वास	एच० आर०, भिवानी	10
34.	धारवाणवास	एच० आर० भिवानी	4
35.	खारियावास	एच० आर०. भिवानी	4
36.	कैरू	एच० आर०, भिवानी	14
37.	बिजलानावास	एच० आर०, भिवानी	2
38.	नन्दीवाली	एच० आर०, भिवानी	2
39.	लाडीयावाली	एच० आर०, भिवानी	2
40.	ढाबढाणी	एच० आर०, भिवानी	2
41.	पोहकरवास	एच० आर०, भिवानी	20
42.	जुई कलां	एच० आर०, भिवानी	20

43.	लालावास	एच० आर०, भिवानी	2
44.	बाबरवास	एच० आर०, भिवानी	10
45.	चन्दावास	एच० आर०, भिवानी	10
46.	झुण्डावास	एच० आर०, भिवानी	10
47.	जुई खुर्द	एच० आर०, भिवानी	20
48.	ललहाना	एच० आर०, भिवानी	20
49.	गोलागढ	एच० आर०. भिवानी	20
50.	लेघाभानान	एच० आर०, भिवानी	10
51.	जीतवाणवास	एच० आर०, भिवानी	10
52.	शीमली	एच० आर०, भिवानी	4
53.	मनसरवास	एच० आर०, भिवानी	4
54.	दुल्हेडी	एच० आर०, भिवानी	10
55.	खरकडी सोहान	एच० आर०, भिवानी	10
56.	तोशाम	एच० आर०, भिवानी	60
57.	अलखपुरा	एच० आर०, भिवानी	12

58.	सागवान	एच० आर०, भिवानी	20
59.	बीरण	एच० आर०, भिवानी	20
60.	लेघां हेतवाण	एच० आर०, भिवानी	10
61.	हेतमपुरा	एच० आर०, भिवानी	10
62.	टिटाणी	एच० आर०, भिवानी	10
63.	भाखड़ा	एच० आर०, भिवानी	2
64.	गोलपुरा	एच० आर०, भिवानी	2
65.	खानक	एच० आर०, भिवानी	20
66.	खानक	एच० आर०, हिसार	
67.	किरावड	एच० आर०, भिवानी	22
68.	किरावड	एच० आर०, हिसार	
69.	भुरटाना	एच० आर०, हिसार	22
70.	लोहानी	एच० आर०, भिवानी	30
71.	लक्ष्मणपुरा	एच० आर०, भिवानी	24
72.	ढाणी पूनिया	एच० आर०, भिवानी	10

73.	बापोडा	एच० आर०, भिवानी	20
74.	पटौदी खुर्द	एच० आर०, भिवानी	14

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Bus Services from Palwal Sub-Depot

17. Shri Subhash Coudhary: Will the Transport Minister be pleased to state—

(a) whether the Government and private buses are plying regularly on the all sanctioned routes in the Palwal Sub-Depot;

(b) if not, the names of the routes on which the public is facing inconvenience; and

(c) the reasons for as to why the full status of depot has not been given to Palwal Sub-Depot?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन):

(क) पलवल जिले में हरियाणा राज्य परिवहन तथा निजी सहकारी परिवहन समितियों की बसें नियमित बस सेवा उपलव्य करवा रही हैं।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

(ग) पलवल उपकेन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे पूर्ण डिपो बनाने के लिये सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

Amount Released by H.R.D.F.

11. Shri Ram Pal Majra: Will the Chief Minister be pleased to state the Blockwise and Districtwise details of the amount released by the Haryana Rural Development Fund (H.R.D.F.) for the development works during the period from March, 2005 till to-date?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): श्रीमान जी, वांछित सूचना अनुबन्ध ' क्य पर रखी है।

अनुबन्ध 'क

एच०आर०डी०एफ० बोर्ड द्वारा जारी की गई राशि का ब्यौरा

(जिलावार खण्डवार)

अवधि 11. 3. 2005 से 28 .2. 2010 तक

जिला	खण्ड	11/03/2005 To 28/02/2010
अम्बाला	अम्बाला–I	981.61
	अम्बाला–II	704.81
	बराडा	648.45
	नारायणगढ़	294.01
	साहा	511.00

	शहजादपुर	289.95
अम्बाला कुल		3429.84
भिवानी	बादड़ा	1253.50
	बवानीखेड़ा	635.19
	बहल	239.72
	भिवानी	1928.04
	दादरी–।	1325.84
	दादरी–।।	1504.19
	केरू	561.15
	लोहारू	550.61
	सिवानी	330.28
	तोशाम	996.98
भिवानी कुल		9325.52
फरीदाबाद	बल्लभगढ	1106.60
	फरीदाबाद	1058.86

	हसनपुर	265.44
	हथीन	0.00
	होडल	524.10
	पलवल	739.91
फरीदाबाद कुल		3694.91
फतेहाबाद	भट्टुकलां	409.27
	भूना	449.46
	फतेहाबाद	713.08
	जाखल	224.63
	रतिया	478.73
	टोहाना	459.02
	उकलाना	15.31
	अग्रोहा	0.00
फतेहाबाद कुल		2749.50
गुड़गांव.	फारूखनगर	232.21

	फिरोजपुर झिरका	8.05
	गुड़गांव	775.58
	नगीना	0.00
	नूह	0.00
	पटौदी	387.99
	पुन्हाना	0.00
	सोहना	423.45
	तावडू	0.00
गुड़गांब कुल		1827.27
हिसार	आदमपुर	490.70
	अग्रोहा (हिसार)	347.79
	बरवाला (हिसार)	870.39
	भट्टूकलां	12.32
	भूना	0.00
	हांसी–।	982.78

	हांसी–।।	838.11
	हिसार–।	810.81
	हिसार–।।	571.94
	नारनौंद	817.57
	सिवानी	0.00
	उकलाना	842.20
हिसार कुल		6584.61
झज्जर	बहादुरगढ	4399.43
	बेरी	3525.00
	झज्जर	3639.36
	मातनहेल	2804.63
	साल्हावास	2440.98
झज्जर कुल		16809.40
जीन्द	अलेवा	479.82
	जीन्द	1258.52

	जुलाना	627.15
	नरवाना	1926.45
	पिल्लूखेड़ा	482.79
	सफीदों	747.42
	उचाना	1350.54
जीन्द कुल		6872.69
कैथल	गुहला	539.70
	कैथल	2727.81
	कलायत	770.16
	पुण्डरी	1016.42
	राजोन्द	1306.50
	सिवन	354.27
कैथल कुल		6714.87
करनाल	असन्ध	802.09
	घरौच्छा (भाग)	274.79

	इन्द्री	546.66
	करनाल	618.11
	नीलोखेडी	601.85
	निसिंग एट चिडाओ	585.22
करनाल कुल		3428.71
कुरुक्षेत्र	बाबैन	176.09
	लाडवा	305.87
	पिहोवा	923.52
	शाहबाद	657.23
	थानेसर	863.22
कुरुक्षेत्र कुल		2925.93
मेवात	फिरोजपुर झिरका	469.10
	हथीन	275.17
	नगीना	233.47
	नूह	619.72

	पुन्हाना	487.40
	तावडू	163.25
मेवात कुल		2275.11
महेन्द्रगढ़	अटेली नांगल	306.55
	कनीना	454.72
	महेन्द्रगढ़	992.01
	नांगल चौधरी	260.31
	नारनौल	147.94
महेन्द्रगढ़ कुल		2161.53
पलवल	हसनपुर	66.46
	हथीन	143.58
	होडल	77.53
	पलवल	326.22
पलवल कुल		613.79
पंचकूला	बरवाला	247.88

	मोरनी	86.55
	पिंजौर	298.34
	रायपुर धनी	160.93
पंचकूला कुल		793.71
पानीपत	बाणेली	429.75
	इसराना	1123.32
	मतलौडा	944.58
	पानीपत	1147.35
	समालखा	503.52
पानीपत कुल		4148.51
रेवाड़ी	बावल	668.41
	जाटूसाना	1178.59
	खोल एट रिवाड़ी	708.02
	नाहर	1701.32
	रिवाड़ी	1352.05

रिवाड़ी कुल		5608.39
रोहतक	बहादुरगढ	0.00
	झज्जर	0.00
	कलानौर	1895.35
	लाखन माजरा	2002.81
	महम	2450.72
	रोहतक	6961.79
	सांपला	2499.32
रोहतक कुल		15809.99
सिरसा	बडागुढा	260.11
	डबवाली	308.94
	ऐलनाबाद	557.19
	नाथूसरी चौपटा	555.44
	ओढा	132.90
	रानिया	551.72

	सिरसा	649.10
सिरसा कुल		3015.40
सोनीपत	गन्नोर	1862.88
	गोहाना	2030.59
	कथूरा	1280.81
	खरखौदा	1702.57
	मुण्डलाना	2169.74
	राई	1514.11
	सोनीपत	2323.30
सोनीपत कुल		12883.99
यमुनानगर	बिलासपुर	463.09
	छछरौली	662.80
	जगाधरी	930.19
	मुस्तफाबाद	380.45
	रादौर	232.65

	सढौरा	190.83
यमुनानगर कुल		2860.00
कुल जोड		114533.69
यानि रुपए		1145.34

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Improve The Condition of Gaushalas

20. Shri Ghanshyam Saraf: Will the Animal Husbandry and Dairying Minister he pleased to state the steps being taken by the Government to improve the miserable condition of the Gaushalas in Haryana State together with the full details of the steps taken?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह): श्रीमान जी, राज्य में ज्यादातर गौशालाए आत्म निर्भर हैं और आगे सुधार के लिए सरकार ने निम्नलिखित पग उठाए हैंः–

1 सरकार राज्य मे पंजीकृत गौशालाओ को 2.50 रुपये प्रति यूनिट रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करवा रही है।

2. सरकार ने जिन गौशालाओं में 2000 या अधिक पशु संख्या हैं, के प्रांगण में पशु संस्था खोलने का निर्णय लिया है। वर्ष 2007–08 में गोशालाओ के प्रांगण में इस प्रकार 13 पशु हस्पताल और पशु ओषधालय खोले जा चुके हैं।

3. सरकार ने राज्य मे पशुओं के कल्याण के लिए, जिनमें गौशालाए भी शामिल हैं, वर्ष 2009 में पशु कल्याण बोर्ड हरियाणा का गठन किया हे।

4. सरकार प्राकृतिक आपदाओं के दोरान पंजीकृत गोशालाओ को अनुदान राशि प्रदान करती है।

5. गोशालाओं के पशुओं को बीमारी की रोकथाम (टीकाकरण), बीमार पशुओं का ईलाज तथा प्रजनन सम्बन्धी सुविधाएं निरन्तर उपलब्ध करवाई जाती हैं।

6. गौशालाओं के आपात्कालीन केसों को 24 घण्टे ईलाज की सुविधा प्रदान की जाती है।

7. गौशालाओ को नस्ल सुधार हेतु प्रजनन उद्देश्य के लिये निम्न रियायती दर पर उत्तम नस्ल के सांड उपलब्ध करवाये जाते हैं।

8. गौशालाओं के घरद्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं।

9. सरकार नियमित तौर पर भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड या अन्य केन्द्रीय संगठनों से अनुदान के रूप में राशि जारी करवाने के लिए जरूरतमन्द गौशालाओं की सिफारिश करती है।

Land for Cremation Ground

18. Shri Subhash Chaudhary: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) the total land that has been received in donation for old cremation ground of Palwal City;

(b) whether some land out of the above said land has got registered in revenue record in the name of Municipal Council, Palwal;

(c) if so, the date on which the land referred to in part (b) above has got registered in the name of Municipal Council, Palwal in the revenue record togetherwith the total area of said land;

(d) whether some of the land has also been given for the park of HUDA out of the above said land of cremation ground; and

(e) if so, the date on which the land referred to in part (d) above has been given togetherwith the total area of the said land?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप):

(क) चकबन्दी रिकार्ड के अनुसार (खसरा नं० 440) पलवल शहर में शमशान घाट के नाम पर कुल भूमि 41 कनाल 2 मरले है। राजस्व रिकार्ड में दान का कोई सन्दर्भ नहीं है।

(ख) व (ग) नगर पालिका अधिनियम, 1973 के नियम 51 के अनुसार, सभी शामलात भूमि नगरपरिषद को निहित है और

इन्तकाल संख्या 15112 दिनांक 8.8.2008 के द्वारा कथित भूमि का इन्तकाल नगरपरिषद, पलवल के नाम है।

(घ) व (ड) इसमें से 24 कनाल 4 मरला भूमि (खसरा नं० 440/72) में से इन्तकाल संख्या 17015, दिनांक 24.3.2009 के द्वारा प्रस्ताव संख्या 51, दिनांक 28.12.2008 के माध्यम से हरियाणा शहरी विकारा प्राधिकरण के नाम स्थानांतरण की जा चुकी है।

Construction of Over Bridge

12. Shri Ram Pal Majra: Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an over bridge in Kaithal from Jind to Ambala road which is presently connected through by-pass; if so, the time by which this over bridge is likely to be constructed together-with the amount released for this purpose?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): हां, श्रीमान् जी, इस उपरी पुल के निर्माण की समय अवधि अभी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) द्वारा निविदा प्राप्ति तथा कार्य के अवार्ड होने पर निर्भर हैं।

Upgradation of School

21. Shri Ghanshyam Saraf: Will the Education Minister be pleased to state the time by which the Middle School of Rajgarh is likely to be upgraded to High School?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल):

(क) श्रीमान् जी, यह विद्यालय पहले ही स्त्तरोन्नत किया जा चुका है।

Old Kadimi Tank in Palwal

19. Shri Subhash Choudhary: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether the Old Kadimi Tank in Palwal City is being filled up by earth by HUDA, if so, the reasons thereof; and

(b) Whether any stay has been granted by the Hon'ble High Court in May, 2009 in favour of the Shamshan Sudhar Samiti; if so, the reasons for continuing the filling of earth work in the tank by HUDA despite stay orders?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) जी हां। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी नीति निर्धारित की गई है कि जिन पुराने कस्बों में शहरी सम्पदाओं का विकास किया जा रहा है, वहां पर पार्को पर विकास कार्य व रख–रखाव हुडा द्वारा किया जाएगा। इसी के अन्तर्गत पलवल में पुराना कदीमी तालाब का विकास हरियाणा शहरी विकास प्रधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(ख) शमशान सुधार समिति द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 6041/2009 दायर की गई है जिसके अन्तर्गत दिनांक 22.4.2009 को माननीय उच्च न्यायालय ने कब्जे बारे यथा–स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। नगर समिति, पलवल द्वारा इस भूमि को हुडा के पक्ष में इन्तकाल करने की अनुमति दिनांक 24.3.2009 को राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की गई व 5.314 एकड़ भूमि का कब्जा हुडा को दिया गया था। मार्च, 2009 में संविदात्मक अभिकरण को आबंटित किए गए कार्य के विरुद्ध, उस द्वारा मिट्टी की भराई का कार्य किया जा रहा है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कालिंग अटैंशन मोशन जो कि हरियाणा के उद्योगो को इकोनोमिक पैकेज देने के बारे में था ताकि वे पड़ौसी राज्यों में एक्साईज फ्री उद्योगों के साथ कम्पीट कर सकें, उसका क्या फेट है? अध्यक्ष महोदय, हरियाणा से उद्योग पलायन करके पड़ौसी राज्यों में करों में रियायत मिलने की वजह से जा रहे हैं।

Mr. Speaker: It is under consideration.

श्री अशोक कुमार अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के पांच विधायक

लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा कर गलत तरीके से कांग्रेस में आ गये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: You can't discuss that. I will not allow it. That is being considered by me. That is in my Court. You cannot put up the case. (शोर एवं व्यवधान)

Shri Ashok Kumar Aro ra: Speaker Sir, (Noises & Interruptions).

Mr. Speaker: Arora ji please take your seat. (Noises & Interruptions)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

खाद की अपर्याप्त सप्लाई संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No.3 from Shri Ram Pal Majra, M.L.A. regarding inadequate supply of fertilizer. I admit it. Shri Ram Pal Majra, M.L.A. may read his Notice.

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान खाद की अपर्याप्त सप्लाई के एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने कहा है कि राज्य के किसानों में बड़ा रोष व्याप्त है। खाद की सप्लाई पर्याप्त नहीं है तथा राज्य के किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार इसका समय पर प्रबंध करने में असफल हो गई है।

खाद की अपर्याप्ता के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होने की संभावना है।

अतः मैं सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने के लिए आग्रह करता हूं।

वक्तव्य–

कृषि मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्ण संबंधी

Mr. Speaker: Now, the Agriculture Minister will make his statement.

Agriculture Minister (Sardar Pa ramvi r Singh): The requirement of fertilizers is assessed by Government of India in the Zonal Conference in consultation with State Governments and Fertilizer Companies for every crop season.

The assessment of requirement, availability and consumption of major fertilizers during Kharif, 2009 and Rabi 2009-10 seasons is given asunder:—

Consumption of Fertilizers

Kharif Season

(in Iakh MTs)

Fertilizer	Kharif, 2008			Kharif, 2009		
	Requiremen	Availabilit	Consumptio	Requireme	Availabilit	Consumptio

	t	y	n	nt	y	n
UREA	8.75	8.91	7.45	8.50	7.71	7.21
DAP	2.00	4.40	2.92	3.00	4.37	2.70
MOP	0.21	0.29	0.26	0.27	0.32	0.29
NPK	0.24	0.16	0.12	0.25	0.17	0.10

Rabi Season						
Fertilizer	Rabi, 2008-09			Rabi, 2009-10 (upto 9-3-2010)		
	Requirement	Availability	Consumption	Requirement	Availability	Consumption
UREA	11.15	11.10	10.44	11.15	10.15	9.99
DAP	4.00	4.08	3.67	4.00	4.12	4.08
MOP	0.25	0.20	0.14	0.25	0.61	0.59
NPK	0.42	0.19	0.16	0.20	0.30	0.26

Important Facts

(1) During the corresponding period in the last Rabi 2008-09 season, a quantity of 9.55 lakh MT Urea and 3.63 lakh MT DAP fertilizer was consumed up to 09/03/2009 (against a total consumption of 10.44 lakh MT Urea and 3.67 lakh DAP upto 31/03/2009) whereas 10.15 lakh MT Urea and

4.12 lakh DAP fertilizer have already been made available so far to the farmers during the current Rabi 2009-10 season.

(2) There has been more availability of fertilizers (Urea, DAP, MOP & NPK) than the consumption.

(3) That adequate steps were taken to ensure that sufficient stock of DAP fertilizer always remained available in the cooperative channel with Hafed, it being the nodal agency of the State Government. That Hafed procured DAP fertilizer from the Central designated agencies by making advance payment of MRP. There has been low availability of DAP fertilizer in the private sector because the importers/manufacturers supplied DAP to the private traders in smaller quantities. However, UREA, MOP& NPK fertilizers remained available in abundance in private sector.

(4) The availability and distribution of fertilizers is monitored by the State Government during the peak consumption period on day-to-day and raketo-rake basis and wherever temporary local shortage is felt, the fertilizer is shifted from the surplus areas to the deficit areas in public interest. There have been no reports of non-availability of any of the fertilizers in any part of the State.

Constraints experienced -

(1) Non-availability of timely and adequate number of railway wagons to the fertilizer suppliers for transportation to Haryana from ports/ manufacturing units.

(2) Adverse weather conditions like dense fog, low visibility etc. forced the railways to suspend the movement of

railway rakes which ultimately resulted in late receipts at times.

(3) Haryana has only one Urea manufacturing unit at Panipat with an annual production capacity of 5.11 lakh MT urea. However, the annual requirement of the State is about 20 lakh MT Urea. Therefore, the State has to depend on the supplies allocated by Government of India from other parts of the country which are far away.

(4) Haryana being surrounded by various States on all sides, there remains an apprehension from the farmers and traders of adjoining States to take the fertilizer out of the State. Hence, a lot of efforts are put in to contain the pilferage of fertilizer by strict monitoring on the inter-State borders and to identify the genuine buyers of fertilizers.

Steps taken for Kharif 2010 & Rabi 2010-11

(a) Kharif, 2010

(1) The requirement of fertilizers for Kharif, 2010 has been assessed to be as under-

(a) 08.50 lakh MT Urea

(b) 03.20 lakh MT DAP

(c) 0.30 lakh MT MOP

(d) 0.25 lakh MT NPK

(2) A quantity of 2.00 lakh MT Urea and 3.00 lakh

MT DAP fertilizer will be procured by Hafed, the State Nodal Agency, through the Central designated agencies like M/s Indian Potash Limited and IFFCO by depositing advance MRP for the said quantities.

(3) HLRDC and HAIC have also like-wise been advised to procure 50,000 MT Urea fertilizer each in lean consumption period.

(4) Hafed, HLRDC & HAIC have been involved in the distribution of fertilizers on a bigger scale with the objective that the Government agencies can shift the stock to an area of deficit in case of any eventuality in public interest whereas the private players are reluctant in shifting the stocks in case of any temporary shortage.

(b) Rabi,2010-11

(1) The requirement of fertilizers for Rabi, 2010-11 has been assessed to be as under-

(a) 11.15 lakh MT Urea

(b) 04.00 lakh MT DAP

(c) 00.25 lakh MT MOP

(d) 00.20 lakh MT NPK

(2) A quantity of 3.00 lakh MT Urea and 1.50 lakh MT DAP fertilizer will be procured by Hafed, the State nodal agency, through the Central designated agencies like M/s Indian Potash Limited and IFFCO by depositing advance MRP for the said quantities.

(3) HLRDC and HAIC have also been advised to procure 50,000 MT Urea fertilizer each in lean consumption period.

(4) Hafed, HLRDC & HAIC have been involved in the distribution of fertilizers on a bigger scale with the objective that the Government agencies can shift the stock to an area of deficit in case of any eventuality in public interest whereas the private players are reluctant in shifting the stocks in case of any temporary shortage.

(5) Hafed has already placed orders for 4.50 lakh MT DAP and 0.40 lakh MT Urea with Central designated agencies and an advance to the tune of Rs. 31 crore for 35,000 MT DAP has been deposited.

Hence, the State Government has taken a series of steps to ensure that sufficient quantity of fertilizers is made available to the farmers in the State and there is no apprehension of loss to the crops of the farmers on this front. The State is expecting a very good Rabi crop if the weather holds good.

स्पीकर सर, मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि आज के दिन प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और न ही आज खाद की ज्यादा डिमाण्ड है फिर भी अगर किसानों को कहीं पर खाद की जरूरत होगी तो हम उसे उपलब्ध करवा देंगे, इसका सरकार ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। स्पीकर सर, इसके अलावा जहां तक भविष्य की डिमाण्ड का सम्बंध है मैं माननीय सदस्य और पूरे सदन को इस बारे में आश्वस्त करना

चाहूंगा हरियाणा सरकार ने आगे की फसल की जरूरत के हिसाब से भी खाद के पर्याप्त स्टॉक का इंतजाम कर रखा है। इसलिए हम अपने किसान भाईयों को उनकी किसी भी फसल के लिए खाद की कमी नहीं आने देंगे।

श्री रामपाल माजराः स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदय ने अपने रिप्लाई में स्वयं स्वीकार किया है कि रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से खाद की आपूर्ति में कुछ कमी पेश आ गई थी। स्पीकर सर, मैं यह समझता हूं कि सरकार द्वारा खाद की यह आर्टीफिशियल शॉर्टेज जानबूझकर क्रिएट की गई और किसानों को राशन कार्ड पर खाद की सप्लाई की गई। इन्होंने अपने जवाब में दिखाया है कि वर्ष 2009– 10 में हमारे यहां पर यूरिया खाद की खरीफ की फसल मे 8.50 लाख मीट्रिक टन की डिमाण्ड थी जिसके अगेंस्ट 7. 71 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद की सप्लाई की गई और 7. 21 लाख मीट्रिक टन डिस्ट्रीव्यूट किया गया। स्पीकर सर, इसी प्रकार से रबी की फसल के समय यूरिया की डिमाण्ड थी 11.15 लाख मीट्रिक टन, सप्लाई हुई 10. 15 लाख मीट्रिक टन और डिस्ट्रीब्यूशन हुई 9.99 लाख मीट्रिक टन। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि इस तरीके से जो डिमाण्ड और सप्लाई में वक्तन–फक्तन दोनों में गैप रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने माना है कि चाहे वह ट्रास्पोर्टेशन की वजह से रहा हो और चाहे रेलवे की वजह से गैप रहा है। क्या उस वक्त सरकार ने राशन

कार्ड पर खाद सप्लाई करके लोगों को यह दिखाया कि इसकी बहुत शॉर्टेज है जिसकी वजह से होर्डर्स ओर ट्रेडर्स ने इसका बहुत लाभ उठाया और किसानो को नुकसान हुआ?

Mr Speaker: Please put the question. (Interruptions) यह तो आपने कथा कह दी है।

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, यह कथा नहीं है। क्या इस बात को सप्लाई में दिखाया गया है और क्या इरा बारे में ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए कोई कदम उठाये थे?

श्री अध्यक्षः माजरा जी, इसके बाद आप एक सवाल और पूछ सकेगे।

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, सवाल तो मै पांच पूछ सकता हूँ।

श्री अध्यक्षः पाँच नहीं केवल एक और सवाल पूछ सकते हैं।

सरदार परमवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि डिमांड थी। यह तो डिपार्टमैंट की रिक्वायरमैट थी। जहाँ पर भी डिमांड थी वहाँ पर डिमांड बिलकुल पूरी हुई है। दूसरी बात में इन्होने रेलवे का जिक्र किया है। यह मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उस वक्त फॉग बहुत ज्यादा पड़ रही थी जिसकी वजह से रेलवे ने कई जगह अपनी ट्रेनों की मूवमैंट को सस्टेंड

किया था। हमने इसके लिए बकायदा पुख्ता इंतजाम किये थे। अगर एक आउटलेट पर खाद की कमी हो गई थी तो भी वही पर फौरन खाद की सप्लाई की और खाद की शॉर्टेज नहीं रहने दी। (शोर एवं व्यवधान) तीसरी बात इन्होने राशनिंग के बारे में कही है। स्पीकर सर, जो जैनूअन किसान थे उनको खाद मिली है। (शोर एवं व्यवधान) कई बार ऐसा होता है कि जो नॉन फार्मर लोग हैं वे भी खाद ले जाते हैं ओर इकट्ठा करके ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। कई बार तो लोग बॉर्डर पार करके दूसरी स्टेट्स में भी खाद ले जाते हैं।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रीब्यूटर्स के खाद के स्टॉक, वजन और क्वालिटी को चौक करने के लिए सैम्पल भरे जाते हैं। यदि सैम्पल दोषपूर्ण मिल जाये तो फर्टिलाईजर्स ऑर्डर पर भारत सरकार के नियमों के तहत कार्यवाही होती है। कई बार तो लैब मे ही मिलजुलकर उसको पास करवा लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इन्होने कितनी जगहो पर खाद की वेट या क्वालिटी के सैम्पल भरे, कितने लोगों पर मुकदमें दर्ज किये और कितने लोगों को सजा दिलवाई है? साथ ही साथ मंत्री जी यह भी बताएं कि भविष्य में इस तरह की दिक्कत न हो उसके लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

सरदार परमवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और हाउस को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह

किसान हितैषी सरकार है और इसके लिये किसानो का हित सर्वोपरि है। हमारी ऐजेन्सियों ने खाद के बिलकुल पूरे इन्तजाम कर रखे हैं। माननीय सदस्य स्टॉक सैम्पल के चौक वाली जो बात कह रहे हैं यह एक सेपरेट प्रश्न है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया है। जो स्टॉक सैम्पल फेल हुए हैं क्या उनके ऊपर कोई कार्यवाई करने का प्रावधान मंत्री जी करेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

वर्ष 2010–2011 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker: Now, general discussion on Budget Estimates for the year 2010- 2011 will take place. Dr. Raghuvir Singh Kadian may speak. डा० कादियान को बोलनो से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि Dr. Kadian Ji will be given half-an-hour and one person from the Opposition Party will be given half-an-hour. All other Members will be given 10 minutes each क्योंकि बहुत सारे नये सदस्य चुनकर आये हैं इसलिए नये सदस्यों को टाईम देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। (व्यवधान) 10 minutes to each will be given. (interruptions) Vij Sahib, your Party will also be given more time मैंने देख लिया है। As per number I will consider it. मैं सभी सदस्यों से एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा कि वे जो भी बोलें वह बजट पर ही बोले एक दूसरे के खिलाफ न बोले।

डा. रघुवीर सिंह (बेरी): ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने मुझे बजट की डिस्कशन पर एज एन ओपनर बोलने की अपोरच्यूनिटी दी है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। स्पीकर सर, कल इस अगस्त हाउस के पटल पर माननीय वित्तमंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने 2010–11 का जो बजट पेश किया है, वह एक बहुत ही बेहतरीन और प्रोग्रैसिव बजट है। इस बजट मे किसान, मजदूर, व्यापारी, शहरो और गांवों को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। इस बात के लिए में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ओर हमारे काबिल वित्तमंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी को बहुत बहुत मुबारिकबाद देता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने एक बेहतरीन बजट हरियाणा को दिया है। (इस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।) डिप्टी स्पीकर सर, इस बजट को तैयार करने में फाईनांस कमिश्नर एवं सैक्रेटरी, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उनको भी मैं मुबारिकबाद देना चाहता हूं। Hon'ble Deputy Speaker Sir, as you know, I have held the different constitutional capacity posts in the past. And you are well aware that the Speaker never speaks, he always listens. Now, I have found this opportunity to speak on the Budget. The people have given me the opportunity as a Member of this august House and in that I will certainly highlight the achievements and planning of the Budget. I am not an economist. मैं कभी इकोनामिक्स का विधार्थी भी नहीं रहा और न

ही मुझे इसमें कोई महारत हासिल है। अगर हम बजट की पूरी किताब पढ़ने लग जाएं तो साल भर लग जाएगा। Hon'ble Deputy Speaker Sir, certainly I take this opportunity to highlight and appreciate the super planning and steps which are taken by the Government led by Ch. Bhupinder Singh Hooda. जैसा हम सब जानते हैं कि टैक्स कलैक्शन, टैक्स की कम्पाइलेशन, उसकी एलोकेशन और उसकी अडजैस्टमैंट एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। सर, कैप्टन साहब ने उसको आसान बनाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो सदन में पेश किया, इसके लिए मैं कैप्टन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऑनरेबल मैम्बर्ज, किसी बजट की दशा या दिशा का अवलोकन और एनालिसीज करने के लिए कुछ स्टैप्स उठाने जरूरी हैं। सर, स्टेट इकोनामी के बारे में जो बजट में दर्शाया गया है। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। The State GSDP at current price is affected to growth by 18.4%. The contribution of primary sector in GSDP is 19.8%, secondary sector, it is 20.8% and tertiary sector it is 51.4%. ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, यह सदन इस बात के लिए गर्व करता है कि हरियाणा प्रदेश गोवा के बाद पर–कैपिटा–इन्क्रम में हाईएस्ट है। यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है क्योंकि यह किसी भी प्रदेश की माली हालत का, विकास का, उसके आगे बढ़ने और डिवैल्पमैंट के रास्ते दिखाने का काम करती है। पर कैपिटा इन्कम पूरे देश में सबसे ज्यादा होने के लिए मैं कप्तान साहब को मुबारिकवाद देता हूं। बजट किस कंडीशन और डायरैक्शन में ले जाएगा उसमें बजट ऐस्टीमेट्स का भी रोल है। Total receipts

(net of Public Debt) in Budget Estimates 2010-2011 are projected at Rs.30085.98 crores of which Revenue Receipts are Rs. 24,540.83 crore, while Capital Receipts (net of Public Debt) are Rs.5545.15 crore. The Total Expenditure (excluding Repayments) under the Budget Estimates 2010-11 is projected at Rs.33,600.84 crore, of which Revenue Expenditure is Rs.28,482.64 crore, while the Capital Expenditure is shown as Rs. 5,118.20 crore. The Revenue Deficit has been projected at Rs.3941.81 crore for 2010-2011. The fiscal deficit is estimated to be 3.59% of GSDP in 2010-11 which is in the prescribed limit of 4%. This shows the planning and management of any budget that the budget is upto the mark and जो बजट की प्लानिंग और दिशा है उसको यह शो करता है कि प्रदेश ठीक दिशा में जा रहा है। डिप्टी स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ स्टेट ऐनुअल प्लान जो है उसकी भी दिशा और दशा जानने के लिए मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि the State Government has revised the annual plan 2009-10 from the budgeted outlay from Rs.10,000 crore to Rs.10,400 crore and allocated Rs.10,500 crore for the annual plan from 2010-11. In addition to it, an outlay of Rs.1363.58 crore for the Centrally Sponsored Schemes and other development plan schemes has also been included on Plan Side. Hence, the composite Plan outlay in Budget Estimates 2010-11 is Rs.11863.58 crore. डिप्टी स्पीकर सर, मैं स्टेट आउट ले प्लान का भी जिक्र करना चाहूंगा। जनाब ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे और हम जब उन सामने वाली बेचों पर बैठते थे तो इन्होंने जो अपना पहला बजट वर्ष 2000—01 का पेश किया उसमे इनके बजट का

जो स्टेट आउट–ले प्लान था वह 1800 करोड़ रुपये का था और जो 2004–05 का स्टेट आउट–ले प्लान था वह 2250 करोड़ रुपये का था। 1800 करोड़ रुपये से 2250 करोड़ रुपये यानी 24 परसैंट की इंक्रीज करने पर उस समय बडी मेजें थपशपायी गयी थीं कि 24 परसैंट की इंक्रीज हो गयी है। डाउनफाल कितना रहा वह एक अलग बात है लेकिन यह स्टेट आउट–ले प्लान चार साल तक 1800 करोड़ रुपये से 1950 करोड़ रुपये तक ही घूमता रहा। वर्ष 2004–05 में जब बजट पेश हुआ उसमें 2250 करोड़ रुपये का प्लान आउट–ले किया गया। डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह बात इसलिए मैंशन करना चाहता हूं कि वर्ष 2005 में when the welfare Government headed by Ch. Bhupinder Singh Hooda came in power उस समय हमें जो प्लान आउट–ले मिला था वह 2250 करोड़ रुपये मिला था और उसके बाद पांच साल मे जो 11 हजार 663 करोड़ रुपये का जो आउट ले प्लान किया है उसके लिए कौन सी नीति, कौन सी नियत, किस ढंग की प्लानिंग, किस ढंग का मेनेजमैंट किया होगा यह तो एक अंदरखाते की बात है। आज जो कप्तान साहब ने बजट पेश किया वह पांच सालों मे सिक्सथ टाईम ज्यादा है। डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा 1966 में बना था। 1966 के बाद तकरीबन 44 साल के बाद जो 11663 करोड़ रुपये का प्लान आया है इसके लिए मै हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत–बहुत मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि इन्होने उस प्लान को 6 टाइम्स इन्क्रीज कर दिया। इस मौके पर मैं अपने पडौसी

राज्य जिसे हम बड़ा भाई भी कहते हैं, का जिक्र भी अवश्य करना चाहूंगा। जब हमारा ऐनुअल आउट–ले प्लान 2250 करोड़ रुपये का होता था तब पंजाब का तकरीबन 385० करोड़ रुपये का ऐनुअल आउट–ले प्लान था अर्थात हमारे से डेढ़ गुना ज्यादा था। आज जब हम पंजाब का और हमारे हरियाणा प्रदेश का ऐनुअल आउट–ले प्लान देखते हैं तो आज हमारे 11663 के मुकाबले में पंजाब का तकरीबन 9000 करोड़ रुपये के आसपास आउट– ले प्लान है। जब डिवीजन हुआ था तो हमारे असैट्स का बंटावारा 60–40 की रेश्यो में हुआ था। उस समय हमारे प्रदेश की माली हालत भी अच्छी नहीं थी चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी रहे हों, डिस्किमिनेशन कारण रहा हो या अन्य कारण रहे हों, लेकिन उस स्थिति से ऊपर उठकर आज अगर हमने पंजाब को इस मामले मे क्रॉस किया है तो यह इस बात का द्योतक है कि हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नंबर– 1 की दिशा में बढ़ रहा है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यह बात वर्ष 2007–08 मे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी जब पानीपत के पलाई ओवर का उदघाटन करने आये थे, उस समय उन्होने अपनी स्पीच में कही थी। वे हिंदुस्तान के बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। वे मैनेजमैंट को भी जानते हैं, प्लानिंग को भी जानते हैं, फिस्कल डैफिसिट और टैंकर कंप्लायंस और ऐलोकेशन को भी समझते हैं। उन्होने उस समय कहा था कि मुझे इस बात का फख्र है। हरियाणा प्रदेश ने इतनी तरक्की की है। यह बात उन्होने इस छोटे से प्रदेश के बारे में कही कि इस प्रदेश का जो फिस्कल आउट–ले

प्लान है, जो प्लानिंग है ओर जो फाइनैंशियल मैनेजमैंट है वह पूरे देश मे नंबर वन पर है। यह बात उन्होंने स्टेज के ऊपर लाखों लोगो के बीच में कही थी। उसके बाद श्री मौंटेक सिंह आहलूवालिया जो कि हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लैवल के अर्थशास्त्री हैं और जाने–माने फाइनैंशियल मैनेजमैंट के ऐक्सपर्ट हैं उन्होंने भी ये बात कही थी।

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः वे इतने ज्यादा ऐक्सपर्ट हें तभी तो मंहगाई इतनी हो गई है। (विघ्न) इतने ऐक्सपर्ट होने के बावजूद भी मंहगाई पर काबू नहीं कर पा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः गुर्जर साहब, आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीरसिंहः उपाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान का फाईनैंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन जो है उन्होंने भी इस बात को दर्ज करवाया है कि हरियाणा सरकार का जो फाइनैंशियल मैनेजमैंट है उसके हिसाब से यह प्रदेश सरटैनली आगे जाएगा। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को और वित्त मंत्री जी को पुनः बहुत–बहुत मुबारिकबाद देना चाहता हूं। Hon'ble Deputy Speaker Sir, from the perusal of the budget speech of Captain sahib, मैंने पाया कि उसमें उन्होंने बहुत सी चीजे प्वायंट आउट की। To save the time of the House, Sir, मैं उन बातो में नहीं जाऊंगा। It is pertinent to

mention some of them. बजट की जो हाईलाइट्स हैं उसकी प्लानिंग और स्टैप्स के बारे में यहां पर चर्चा हो, प्रदेश किस दशा और दिशा में जा रहा है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने कुछ नयी पहल की है, उनकी चर्चा मैं करूं तो बजट स्पीच के पेज नंबर 4 से लेकर 9 तक व पैरा 6,9,10,11, 12 और 13 मे न्यू इनिशिएटिव के बारे में चर्चा की गई है कि हरियाणा सरकार और वित्त विभाग क्या न्यू एनिशिएटिव लेने जा रहा है। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा– Policy for engaging the voluntary and NGO sectors as development partners of the State leading to reduction of delivery costs proper identification of the beneficiaries flexibility of the approach and greater community participation. Policy on project or facility private sector participation in improvement of the physical and social infrastructure to set up Haryana infrastructure development board to provide and institutional frame work for conceptualization, financing, implementation, maintenance and operation of PPP project and other major infrastructure projects in the State. East-West and North-South Expressway Corridors running through the State in PPP mode with purpose of opening of interior areas of Haryana for economic growth and development to set up joint venture company with the Government of Haryana. To launch Rajiv Gandhi Urban Development Mission, Haryana with an out-lay of 2500 crore of rupees over the next years. It will concentrate and affordable urban housing slum development, Water Supply, Drainage, Sewerage and Solid Waste Mangement. To introduce Mahatma Gandhi Swavlamban Pension Scheme for the members of dairy cooperatives and cane grower's

cooperatives, wherein each member will contribute Rs. 200 per month. The Society/Federation/State Government will co-contribute Rs. 100 per month, and the Government of India will co-contribute Rs. 1000 per annum. Assure a retirement for the members of the age of 60 years. The State Government has launched an Economic Stimulus Package. यह एक नई पहल है इसलिए इसको हमे एप्रिशिएट करना चाहिए। Under Economic Stimulus Package an amount of Rs. 332.56 crore has been released so far during the year 2009-10 and provision of Rs. 713.79 crore has been made for the year 2010-11. ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, मैं चर्चा करूं कि डिफरेंट हैडज में जो एलोकेशज और जो एडजैस्टमैंट वित्त विभाग की तरफ से दिखाई गई हैं वे एप्रिशिएब्ल हैं। किसी प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर उस प्रदेश की डिवलैपमैंट की दिशा को तय करता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जितनी एलोकेशज होंगी, उतना ही प्रदेश का विकास होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे पॉवर, रोड्ज और ट्रान्सपोर्ट पर जितना ज्यादा बजट एलोकेट किया जाएगा उतना ही उस प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। जब इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्वैस्टर आयेगा, अगर इन्वेस्टर आयेगा तो वहां इण्डस्ट्रियल ग्रोथ होगी, डिवलैपमेंट होगी और पर–कैपिटा–इन्कम बढेगी। स्टेट की ग्रोथ और डिवलैपमैंट चहुमुखी विकास की तरफ जायेगी। मैं पावर का जिक्र करना चाहूंगा। It is written on page Nos. 9 and 10 of the Budget Estimates under the heading of 'Power' that the average daily power availability in the State has increased

from 578 lack units in 2004-2005 to 907 lakh units this year. From 2005-2010, 1117.8 MW own generation capacity added in the State. More power generation projects are in the pipeline and availability of power will be doubled by 2011-12. Pre-project work started on first phase of 2800 MW Nuclear Power Plant to be set up at Village Gorakhpur in District Fatehabad. Under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojna, 91,347 connections released this year to BPL families, and Rs. 4,642.71 crore has been allocated in the Budget for this Sector. डिप्टी स्पीकर सर, किसी प्रदेश की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और वित्त विभाग का एक विजन इस बात से साफ झलकता है। स्टेट पावर डैफिशिएंसी की वजह से पहले फैक्ट्रीज ओर इण्डस्ट्रीज पलायन कर रही थी उसका कारण चाहे ली एण्ड आर्डर रहा हो. चाहे पावर रहा हो या कोई और कारण रहे हों, उस समय माननीय मुख्यमत्री द्वारा यह बात सोची गई कि हरियाणा प्रदेश को पावर सफीशिएंट बनाया जाए। खेदड के पावर प्लांट की बात हो, झाड़ली पावर प्लांट की बात हो या यमुनानगर पावर प्लांट की बात हो, 5000 मेगावाट के नए प्रोजैक्टस आज हरियाणा प्रदेश मे चल पड़े हैं या अंडर प्रोसैस हैं। फैब्रीकेशन के प्रोजैक्ट भी इसमें शामिल हैं। इसको एक बहुत बडा विजनरी स्टैप किसी सरकार का, किसी व्यक्ति विशेष का और मुख्यमंत्री का हम कहेगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा जी इस बात के लिए मुबारिकवाद के पात्र हैं कि 5000 मेगावाट बिजली का हरियाणा में अधिक उत्पादन होगा ओर हरियाणा प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सैल्फ सफीशिएंट बन जाएगा। जहां तक बिजली के बजट

मे एलोकेशन की बात है Rs.4,642.71 crore has been allocated in the Budget for this Sector. यह पिछले बजट से 11.4 परसैंट इन्क्रीज है जो कि कसीडरेबल इन्क्रीज है। यह इन्क्रीज किसी प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, विकास को आगे बढ़ाने मे द्योतक है। यह सरकार की नीति और नियत को दर्शाता है। पावर में 11. 4 परसैंट का जो इन्क्रीज हुआ है यह कसीडरेबल है और सराहनीय है।

It is also written in the Budget Estimates under the heading of 'Water Supply and Sanitation' on page Nos. 10 and 11 that the approved norm of 40 litres per capita per day to be achieved in 100% villages in Haryana by end of March, 2010. The Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Augmentation Project covering 503 villages in Mewat will be completed by end of March, 2010. Further augmentation under the project will commence next year. Sewerage connection charges in the State waived for a period of one year from November, 2009. Projects for 100% coverage of Water Supply and Sewerage facilities for 15 towns being undertaken under economic stimulus package at a cost of about Rs.956 crores. And Rs. 1,297.69 crores has been allocated in the Budget for the Water Suply and Sanitation and it has been increased upto 3.28%.

It is also written on page 12 of the Budget Estimates that 3903 Kms. length of roads improved in the current financial year and 4100 kms length will be taken up in 2010-11. 16 roads over-bridges open to traffic and 13 more ROBs are under construction. And Rs.1,938.95 crore has been allocated in the Budget for this Sector.

अध्यक्ष महोदय, इरीगेशन किसान की जीवन रेखा है। इरीगेशन के लिए NCR Water Supply Channel to be completed by June, 2010. Kaushalya Dam on Ghaggar River and Shahabad Dadupur Nalvi Project to be completed next year. Detailed project report being prepared for construction of Mewat Canal. 500 New lined water courses to be taken up for construction next year. The Budget allocation for this Sector is of Rs.1,616.49 crore. This is a considerable increase i.e. 4.09%.

It is written on page 15 of the Budget Estimates under the heading 'Transport' that for safe and efficient passenger transport services to each and every village in the State, a comprehensive passenger transport policy is being formulated. A city bus service is proposed to be set up under PPP mode in Gurgaon. Multi-Modal Hubs/ Modern Bus Stands to be set up under PPP mode at 20 locations in the State. The Budget of Rs.1,142.10 crore has been allocated for this Sector. किसान किसी भी प्रदेश की रीढ की हड्डी होता है। उसकी बहबूदी के लिए और खुशहाली के लिए किसी बजट मे किसानों के लिए किया गया प्रावधान इस बात का द्योतक है कि सरकार किसान के प्रति कितना सोचती है। चाहे किसानों की लैंड एक्वीजिशन के रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे उनके लोन वेविंग की बात हो, चाहे उनके बिजली के 1600 करोड़ रुपये माफ करने की बात हो सब तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। Food-Grain production was a record 161.66 lakh tons during 2008-09. Target of 167.14 lakh tons likely to be achieved this year. Basic cane price of early, mid & late maturing varieties of sugarcane fixed at Rs.185/-,

Rs. 180/- and Rs.175 per quintal for crushing season 2009-2010.

Mr. Deputy Speaker: Kadian Sahib, please conclude.

डॉ० रघुवीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर ओपनर हूं। स्पीकर साहब ने 35–40 मिनट का समय दिया हुआ है। मुझे अभी बोलते हुए 12 मिनट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्षः नहीं, नहीं, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया हे।

डॉ० रघुवीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, ओपनर के लिए ओपन टाईम होता है।

श्री उपाध्यक्षः डाक्टर साहब, आपको बोलते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं।

Dr. Raghuvir Singh: Deputy Speaker Sir, Haryana Cooperative Societies Act, 1984 has been amended, so Cooperative loans not to be recovered as arrears of land revenue. For this Head, Rs.1073.62 crore has been given and similar budget has been allocated for Health and Social Welfare. इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए तकरीबन 7722 करोड़ रुपया प्लान आऊट ले में रखा है। इसी तरह से सोशल वैलफेयर के लिए बजट मे सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं, महिलाओं, विकलांगो आदि की पैंशन के लिए 2167.15 करोड़ रुपये का

प्रावधान किया है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। ये सारी बातें इस बात को शो करती हें कि आज हरियाणा सरकार की नीति और नीयत इस प्रदेश को किस ढंग से नम्बर एक पर ले जाने की कोशिश मे है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सदन की जानकारी के लिए कुछ पिछली रिजिम्स के कपैरिजन में कुछ डाटा सदन के पटल पर रखना चाहूँगा। To adjust the prosperity and planning of a State, I draw the kind attention of this august House towards the comparative position of economy/ fiscal matter in the State. वर्ष 2000 से 2006 के दौरान प्लान और नॉन प्लान का टोटल एक्सपैंडीचर 71890 करोड़ रुपये का था और हमारी सरकार के समय मे वर्ष 2005 से 2010 के दौरान यह 120739 करोड़ रुपये हुआ जोकि तकरीबन 90 प्रतिशत की इन्क्रीज है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं पावर सैक्टर की बात करूं तो वर्ष 2000 से 2005 के दौरान पावर सैक्टर में प्लान और नॉन प्लान में टोटल एक्सपैंडीचर 6678 करोड़ रुपये का हुआ था और हमारी सरकार के समय में 2005 से 2010 के दौरान यह 17408 करोड़ रुपये हुआ जो कि तकरीबन 300 प्रतिशत की इन्क्रीज है। इसी तरह से एजुकेशन के अंदर वर्ष 2000 से 2005 के दौरान प्लान और नॉन प्लान में टोटल एक्सपैंडीचर 7627 करोड़ रुपये का हुआ था और हमारी सरकार के समय में 2005 से 2010 के दौरान यह 16152 करोड़ रुपये हुआ जो कि तकरीबन 125 प्रतिशत की इन्क्रीज है। इसी तरह से सिंचाई के अंदर वर्ष 2000 से 2005 के दौरान प्लान और नॉन प्लान मे टोटल एक्सपैंडीचर 2883 करोड़

रुपये का हुआ था और हमारी सरकार के समय में 2005 से 2010 के दौरान यह 7090 करोड़ रुपये हुआ जो कि तकरीबन 150 प्रतिशत की इन्क्रीज है। इसी तरह से हैल्थ के अंदर वर्ष 2000 से 2005 के दौरान प्लान और नॉन प्लान में टोटल एक्सपैंडीचर 1707 करोड़ रुपये का हुआ था और हमारी सरकार के समय में 2005 से 2010 के दौरान यह 3364 करोड़ रुपये हुआ जो कि तकरीबन 100 प्रतिशत की इन्क्रीज है। इसी तरह से सोशल सैक्टर के अंदर वर्ष 2000 से 2005 के दौरान प्लान और नॉन प्लान में टोटल एक्सपैंडीचर 2671 करोड़ रुपये का हुआ था और हमारी सरकार के समय में 2005 से 2010 के दौरान यह 6341 करोड़ रुपये हुआ जो कि तकरीबन 150 प्रतिशत की इन्क्रीज है। इसी तरह से वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन के अंदर वर्ष 2000 से 2005 के दौरान प्लान और नॉन प्लान में टोटल एक्सपैंडीचर 2163 करोड़ रुपये का हुआ था और हमारी सरकार के समय में 2005 से 2010 के दौरान यह 5817 करोड़ रुपये हुआ जो कि तकरीबन 175 प्रतिशत की इन्क्रीज है। इसी तरह से पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड आर.) के अंदर वर्ष 2000 से 2005 के दौरान प्लान और नॉन प्लान में टोटल एक्सपैंडीचर 1941 करोड़ रुपये का हुआ था और हमारी सरकार के समय मे 2005 से 2010 के दौरान यह 6134 करोड़ रुपये हुआ जो कि तकरीबन 225 प्रतिशत की इन्क्रीज है। It is a tremendous increase which shows the ensuing development in all spheres of every section of the society in the State. मै सरटेनली मैशन करना चाहूँगा कि on plan side, equally better performance by

our Government. प्लान साईड में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छी परफोरमैस पिछले पांच साल में की है। वर्ष 2000 से 2005 के दोरान प्लान एक्सपैंडीचर 9235 करोड़ रुपये का हुआ था और हमारी सरकार के समय मे वर्ष 2005 से 2010 के दौरान 30489 करोड़ रुपये का हुआ जो कि तकरीबन 300 प्रतिशत की इन्क्रीज है। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 से 2005 के दौरान एक्चूवल प्लान एक्सपैंडीचर 88 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ था और हमारी सरकार के समय में वर्ष 2005–2010 में 110 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ है meaning thereby the utilization of the budget or the expenditure plan, actual plan shows the efficiency and good governance of any Government. उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष के साथी कहते हैं कि हरियाणा सरकार कर्जे ले रही है और उसके नीचे दबी हुई है। मैं यह बात जरूर मैंशन करना चाहूंगा कि वर्ष 2000 से 2005 के दौरान 26073 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने कर्जा लिया और 2005– 2010 मैं 19991 करोड़ रुपये का कर्जा लिया गया। मैं यह बात रिकार्ड के आधार पर कह रहा हूं कि वर्ष 2005–10 के दोरान 19991 करोड़ रुपये के कर्जे लिए गए और यह भी just to keep the pace with the progress of the development. I would like to bring the correct, complete and upto-date information before this august House that our Government has never gone into overdraft with the RBI, whereas the previous Government frequently went into overdraft. The cash balance in Haryana Government account in RBI as on 25.2.20I 0 is Rs.1778.74 crores. आज भी हमारे 1778 करोड़ रुपये आरबीआई. के पास

जमा है। इसके साथ– साथ जो प्रगतिशील बजट वित्त मंत्री महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन में तैयार करके पेश किया गया है उसके लिए वित्तमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोनों ही मुबारकवाद और बधाई के पात्र हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यह बजट पूरे हरियाणा प्रदेश को तीव्र गति से चहुंमुखी प्रगति के पथ पर लेकर जायेगा। बजट हाईलाईट्स के साथ मैं जिक्र करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और सरकार की नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है। डिप्टी स्पीकर सर, अब्राहम लिंकन जो एक बहुत बड़े नेता होने के साथ एक महान डैमोक्रेट थे, उन्होंने 160 साल पहले डैमोक्रेसी की डैफीनेशन करते हुए यह कहा था कि `Government of the people, by the people and for the people'. डिप्टी स्पीकर सर, डैमोक्रेसी की इस डैफीनेशन को माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने letter and spirit में साफ नियत और नीति के साथ लाग किया और उसी का यह असर है कि आज के संदर्भ में हरियाणा प्रदेश पूरे देश में आगे बढ़ रहा है। डिप्टी स्पीकर सर, इस सरकार ने राजनीति के मायने बदलने की भी कोशिश की। डिप्टी स्पीकर सर, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि हरियाणा प्रदेश में पहले यह रिवाज था कि जब कभी प्रदेश के नेताओं द्वारा प्रदेश में कहीं पर रेलिया की जाती थी तो लोगों से स्टेजों पर मालाएं डलवाई जाती थी। उस समय इस प्रकार से गरीब जनता की खून–पसीने की कमाई को लुटा जाता था लेकिन पिछले पांच साल के दौरान एक भी ऐसा मौका नहीं आया होगा जब हमारे

माननीय मुख्यमंत्री ने किसी रैली में स्टेज पर किसी से एक पैसे की भी माला डलवाई हो। यह बात मैं इस सदन मे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह सब राजनीति के मायने बदलने के लिए किया है। डिप्टी स्पीकर सर, इसके अलावा पहले यह भी होता था कि प्रदेश में राजनीतिक रैलियां को कामयाब करने के लिए कुछ विशेष पार्टियों द्वारा प्रदेश की गरीब जनता के व्हीकल्स को इम्पाऊंड कर लिया जाता था। डिप्टी स्पीकर सर, यह बात भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले पांच सालों के दौरान ऐसा एक भी अवसर नहीं आया जब किसी रैली के दौरान कोई व्हीकल इम्पाऊंड किया गया हो। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बदले की राजनीति को भी विराम दिया है। पिछले पांच सालों के दौरान किसी भी आम कार्यकर्ता पर एक भी केस राजनीतिक बदले की भावना से रजिस्टर्ड नहीं किया गया। यह सब कुछ सरकार की साफ नीति और नियत को दर्शाता है। डिप्टी स्पीकर सर, ये कुछ स्टैप्स हैं जिन की वजह से हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के प्रति मजबूत हुआ है और इसी मजबूत विश्वास के परिणामस्वरूप हरियाणा प्रदेश मे पुनः चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। डिप्टी स्पीकर सर, जो गुण, स्वभाव और संस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हैं वे बहुत कम राजनेताओ में मिलते हैं. Certainly, I will mention that this Budget will lead the State as No.1 State in the Nation. डिप्टी

स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री महोदय को बड़ी नजदीकी से जानता हूं। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ सदन में एक बात कह सकता हूं। वैसे तो यह किसी को नहीं पता कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। यहां पर श्री ओम प्रकाश चौटाला जी भी बैठे हैं जो कभी यहां बैठकर कहा करते थे कि जब तक जिऊंगा तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा। वे हालात कब और कैसे बदल गये यह तो सभी जानते हैं लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेगे। डिप्टी स्पीकर सर, आखिर मे में यह कहना चाहूंगा कि अगर मैं हल्के की समस्याओ से सरकार को अवगत नहीं कराऊंगा तो मैं अपने फर्ज से कोताही बरतूंगा। डिप्टी स्पीकर सर, जहां तक मेरे बेरी हल्के की बात है मैं यह कहना चाहूंगा कि वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की पूरे हरियाणा प्रदेश के विकास पर समान रूप से नजर है फिर भी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे बेरी हल्के को सब डिवीजन बनाया है इसके लिए मैं अपनी ओर से और बेरी हल्के की समस्त जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। यह जो सब डिविजन बना है इसके साथ ही साथ जो टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग का प्लान ऑफ एक्शन है उसको भी जल्द फाईनल करवाया जाये। वहाँ पर एच.एस. आई. आईडीसी. और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का सैक्टर भी कटवाया जाये। बेरी पहले एक कौने में था लेकिन अब यह महम से गुड़गाँव वाया झज्जर फरूखनगर जो नया नैशनल हाईवे मंजूर हुआ है, उस पर

आ गया है इसलिए वहाँ पर लघु सचिवालय के निर्माण का कार्य भी जल्द शुरू किया जाये। इसी प्रकार से वही पर एक कम्यूनिटी सैन्टर का निर्माण भी करवाया जाये। चूंकि बेरी नैशनल हाईवे पर आ गया है इसलिए वहाँ पर ट्चूरिज्य कम्पलैक्स के निर्माण का प्रावधान भी करवाया जाये। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ गवर्नमैंट गर्ल्ज कॉलेज और पॉलिटैक्निक की भी बहुत जरूरत है इसलिए उनका भी प्रावधान किया जाये। मेरे बेरी हल्के मे 53 गाँव हैं लेकिन कुछ गाँव नामतः दहकोरा, रोहद, आसंडा, भापडौदा, खरहर, छारा, रिवाडीखेड़ा, मातन, छुडानी, खरमाण, सिलौठी, डाबोदा, दुल्हेडा, छोछी, बरहाणा, सिवाना और चिमनी ये 17 गाँव हैं जहाँ पर सिंचाई के पानी की किल्लत है। इस पानी की किल्लत को दूर करने के लिए छारा माईनर, रिवाड़ीखेड़ा माईनर, आसंडा माईनर और भदानी माईनर हैं। अगर इन माईनरों की रिमॉडलिंग करके एक्सटैन्शन की जाये तो इन लोगों की नहरी पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। इसी तरह से इन 17 गाँवों में पीने के पानी की भी समस्या है। जहाँ तक रोड्स की बात है तो लिंक रोड डीघल से छोछी, दिमाणा से भम्भेवा, खरमाण से रिवाडीखेडा, दहकौरा से नयाबास, मिलकपुर से दूबलधन, बेरी दूबलधन रोड से बाबा टूटा का मन्दिर, बेरी–सेरिया से पतलिया मन्दिर और बेरी–दुजाना रोड से निराचिया मन्दिर, इन सड़कों के बनने की भी लोगों को बहुत उम्मीद है। बरहाणा, धौड, रिवाड़ीखेड़ा, भापड़ौदा, सिलौठी, बिसान और मिलकपुर आदि कुछ गाँवों मे स्वास्थ्य विभाग की डिस्पैंसरीज नहीं हैं। अतः वही पर

डिस्पैंसरीज खुलवाने की कृपा करें ताकि लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, छारा और एमपी. माजरा दो ऐसे बड़े गाँव हैं जहाँ पर किलाबंदी और कसोलिडेशन का काम नहीं हुआ है जिससे वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। अगर यहाँ पर किलाबंदी या चकबंदी हो जाये तो लोग बहुत राहत महसूस करेगे। वैसे तो पूरे हल्के का ड्रेनेज सिस्टम ठीक है लेकिन धौड, सेरिया, गोच्छी, अच्छेज और पहाडीपुर इन पांच गाँवों में पानी निकासी की दिक्कत है। अतः यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया जाये ताकि लोगों की फसलों को डूबने से बचाया जा सके। मांगावास, रोहद, सिलोठी, मिलकपुर ओर रिवाडीखेडा गाँवो में पशु चिकित्सालय डिस्पैसरीज खोली जायें ताकि लोग अपने पशुधन की रक्षा कर सकें। इसी प्रकार से कुछ गाँवों में स्कूल के अपग्रेडेशन की भी जरूरत है जिनमें खरमाण कन्या उच्च विद्यालय को कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया जाये। धौड उच्च विधालय को भी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया जाये। भापड़ौदा हाई स्कूल को भी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ में आपका भी' और अध्यक्ष महोदय का भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं हरियाणा सरकार, माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और वित्त मंत्री जी को एक बार फिर से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूए कि इन्होने एक ऐसा बजट पेश किया है जो कि हरियाणा प्रदेश को नम्बर 1 की ओर ले जायेगा। धन्यवाद।

चौ० ओमप्रकाश चौटाला (उचाना कलां): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देश में हरियाणा एक अग्रणी प्रदेश है और जैसा कि अभी प्रस्तावक ने भी बताया और बजट में भी प्रावधान किया गया है कि पर कैपिटा इन्कम के हिसाब से भी हरियाणा की पहचान दूसरे नम्बर पर मानी गई है। वर्तमान सरकार ने तो बहुत लम्बे समय तक नम्बर 1 हरियाणा होने का ढोल पीटा परन्तु कल जब वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर राज्य के बजट के रूप में दिवालियापन के जो दस्तावेज रखे हैं एक हरियाणवी होने के नाते मुझे भी इस बात की बड़ी पीड़ा है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट में दुस्साहस करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ऐतिहासिक जनादेश लेकर सरकार बनी है। अध्यक्ष महोदय, यह जग जाहिर है कि यह सरकार माइनोरिटी की सरकार हे जनता ने तो पूरी तरह से नकार दिया था। 90 विधान सभा सदस्यो मे से..... (शोर एव व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर साहब, जब ये बोल रहे थे तो हमने बिलकुल एक बार भी किसी को नहीं टोका। (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, यह किस बात का प्यायंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान) ये किस तरह से बोलते हैं। (शोर एवं व्यवधान) हम इनको नहीं टोकते। अध्यक्ष महोदय, इनकी यह क्या आदत पड़ी हुई है। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से थोड़े ही हाऊस चलेगा। ये अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हें। (शोर एवं व्यवधान) इनके आदमी बोल रहे थे तो हमारी तरफ से कोई टोका टाकी नहीं की गई। (शोर एवं व्यवधान) अब ये बिना बात के बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इस तरह से यह बात नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः सर, कोई प्यायंट आफ आर्डर हो सकता है। आप मेरी बात सुनिए, सही न हो तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, I have a right as a Member of House to raise a point of order. (Interruptions). Sir, it is only point of order that 1 am raising. It is my right as a Member of this House to raise a point of order मैंने माननीय सदस्य को कुछ कहा ही नहीं। वे पता नहीं क्यों चिन्ता में हैं कि मैं कुछ कहने वाला हूं। (शोर एवं व्यवधान) इसमें डरने वाली कोई बात नहीं हे। मैं इनको कुछ नहीं कहने वाला।

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी ने बजट पेश करते हुए स्वयं यह बात कही है जिसको में दोहरा रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, on a point of order. माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने मौजूदा सरकार को माईनोरिटी गवर्नमैंट कहा है। कल भी इस माईनोरिटी गवर्नमैंट का इन्होंने इम्तिहान लिया और इनकी 36 वोट्स ही आई और हमारी 52 आई हैं। इन्होने यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी देखा – (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is not the way. This is not relevant. (interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: आप चाहें तो दोबारा फिर चुनाव करा लें। (शोर एवं व्यवधान),

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मोहतबाना अर्ज करूंगा कि बिना वजह से टोका–टाकी बर्दाश्त नहीं होगी। हाऊस को ठीक ढंग से चलाने की व्यवस्था की जाये। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात, यह किस हैसियत से खडा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Su rjewala: How he can say it is not a majority Government? (Noises & Interruptions) If it is not a majority Government how was he sitting here? (Noises & Interruptions).

श्री अशोक कुमार अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, कल कैप्टन अजय सिंह जी ने अपनी स्पीच पढ़ी कोई बोला नहीं और आज भी डाक्टर साहब बोले किसी ने टीका नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः एक आदमी ने भी टोका–टाकी नहीं की। इनका यह कोई तरीका है, उठाके लाट साहब बनकर खडे हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अपने आपको ज्यादा सयाना जाहिर करने की कोशिश करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी की बात मैं दोहरा रहा हूँ। वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते वक्त यह बात कही है कि यह सरकार नए सिरे से जनता का समर्थन लेकर के इस विधान सभा में आई है। अध्यक्ष महोदय, आप भी स्वयं इस पार्टी के मैम्बर हैं। 90 विधान सभा हल्कों में से 40 पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है। यह ठीक है कि.... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is not to be recorded. (Noise & Interruptions)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, I object to this thing. अध्यक्ष महोदय, हाऊस की गरिमा बनाई रखी जाये। इस प्रकार से इनको बोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी। आप कोई सुझाव दें, आपका स्वागत होगा। खरीद–फरोख्त करने वाले सामने बैठे हैं। ये भी वोट खरीदकर जीते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप इनको कंट्रोल करें। इस तरह से हाऊस नहीं चल सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, आप बजट पर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः आप असलियत को कैसे नकारोगे। (शोर एवं व्यवधान) ये बैठे–बैठे किस बात पर बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनसे पूछें ये कौन से सिम्बल पर जीत कर आया है। (शोर एवं व्यवधान) ये कोई तरीका नहीं है। आप पंजे के निशान पर 40 जीते हैं या ज्यादा जीते हैं। पंजे के निशान पर कितने जीते हैं क् (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इस तरह की बात ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) I will not allow it.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ये ठीक तरह से बात करें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये भी विपक्ष के नेता हें और इनको सदन की गरिमा बनाये रखनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः ये हाउस की गरिमा बनाये रखे। ये कांग्रेस पार्टी के 40 सदस्य जीतकर आये हैं। ये हाऊस की गरिमा बनाए रखेगे, क्या यहां पर कोई हाऊस की गरिमा की बात हो रही है?

श्री अध्यक्ष: फार्मर स्पीकर बोले, वे रैलेवैंट बोले, वे बजट पर बोले और वे टू दि प्वायंट बोले। आप टू दि प्वायंट आओ, क्रिटिसाईज करने की बजाए टू दि प्वायंट बजट पर आओ। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं टू दि प्वायंट बोलूंगा। मैं बजट से अलग कोई बात नहीं करना चाहूंगा लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यह टोका–टाकी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाएं। आज तो महिला शताब्दी दिवस है। बैठ जा, बैठ जा, महिला सैंचरी साल है। आप बीच मे मत बोलो। (शोर एवं व्यवधान) यह क्या तरीका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठ जा बीबा। (शोर एवं व्यवधान) No-No. आप भी बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह: सर, 1999 मे केवल 22 आदमी ही आए थे और उनके बल पर आप मुख्यमंत्री बने थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) इनको बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

12.00 बजे

चौ० प्रकाश चौटाला: धर्मबीर तेरे ही प्रयासों से मैं मुख्यमंत्री बना था। अगर उस समय कोई जोड़–तोड़ थी तो उस जोड़ तोड़ में आप भी शामिल थे।(विघ्न) बजट के अंदर दर्शाया गया है कि वर्ष 2005 में जब इनेलो ने सत्ता कांग्रेस पार्टी को सौंपी तो उस समय राजकोषीय कर्जा लगभग 23 हजार करोड़ रूपये का था। अध्यक्ष महोदय, यह फेक्ट्स की बात मैं बता रहा हूं। हम उस वक्त सरकारी खजाने में 1572 करोड़ रुपये की राशि नकद छोड़कर गए थे लेकिन कांग्रेस के पांच वर्षा के शासनकाल में यह कर्जा बढ़कर 44 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह भी फैक्ट्स की बात है इसमें नकारने की कोई बात नहीं है। यह कर्जा बढ़कर 44 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। अगर इसी गति से यह सिस्टम चलता रहा और अगर पूरे पांच साल तक इनको शासन करने का अवसर मिला तो इस प्रदेश के हर एक नागरिक का एक एक बाल कर्जदार हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कर्जा किस बात का होता है? कर्जा लिया जाता है लोगों के विकास के लिए लेकिन इन्होंने तो विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगायी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक छोटा सा इंस्टांस देना चाहूंगा। जैसा कि कादियान साहब ने हुडा के नये सैक्टर बनाने का जिक्र किया। पांच साल के अर्से में इस सरकार ने पूरे प्रदेश में एक भी हुडा का सैक्टर नहीं काटा है। अध्यक्ष महोदय, हुडा का सैक्टर सस्ता होता है और वहा पर लोगो को ज्यादा सुविधाएं मिलती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनका यह क्या तरीका है? मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं कि इस सरकार के पांच साल

के शासन में हुडा का एक भी नया सैक्टर नहीं काटा गया है। दफा चार के तहत नोटिस तो दिये गये हैं लेकिन अंदरखाने इनके अपने लोगो ने औने पीने दामों पर किसानों से जमीनें खरीदी हैं और बाद में उसको विदड्रा कर लिया जाता है और फिर उसी जमीन को प्राईवेट डीलर्ज को, प्रोपर्टी डीलर्ज को और बिल्डर्ज को दे दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है क्या ये इसको भी नकारेगे? अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जैड० के नाम से जमीन ली गयी थी और लोगो को कहा गया था कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एस०ई०जैड० के तहत जमीन लेने की एक शर्त थी कि 25 प्रतिशत जमीन सरकार तब देगी जब 75 प्रतिशत जमीन एस०ई०जैड० लगाने वाला अपनी लेगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले गुड़गांव की एच०एस०आई०आई०डी०सी० की लगभग 1500 एकड़ जमीन औने दोने दाम पर दी गयी। वह जमीन कितने रुपये में दी गयी उसके बारे मे मैं बताना चाहता हूं। वह जमीन सिर्फ 1500 करोड़ रुपये मे दी गयी थी और उसी के साथ लगती चार एकड़ जमीन ओपन ऑक्शन में जब एच०एस०आई०आई०डी०सी० ने नीलाम की तो वह 290 करोड़ में की गयी। अध्यक्ष महोदय, चार एकड़ जमीन 290 करोड़ रुपये में और 1500 एकड़ जमीन सिर्फ 1500 करोड़ रुपये में यह जमीन जो है वह किस हिसाब से दी गयी 7 अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इसमें लाखों करोड़ों रूपयो का नुक्सान है। इस तरह से हरियाणा प्रदेश की यह हालत है। प्राईवेट लोगों से जमीने खरीदी गयीं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने बार बार आश्वासन दिया कि किसान की जमीन अगर ली जाएगी तो उस पर दस हजार रूपये हर महीने दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का स्थगन

श्री नरेश कुमार बादलीः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इनकी फिर वही बात है, ये किरन बात का प्वायंट ऑफ ऑर्डर मांग रहे हैं। इसका और प्वायंट ऑफ ऑर्डर का क्या मेल है? (शोर एवं व्यवधान) मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि बजट पर ठीक बात होनी चाहिए। (विघ्न) ये कोई बात है स्पीकर साहब। (विघ्न) बैठ जा, ... न हो तो। इनका यह कोई तरीका है। इस तरह से तो हाऊस नहीं चल पाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आप यह .... वर्ड तो रिकार्ड से निकलवा दें।

श्री अध्यक्षः ठीक है, ... इस वर्ड को रिकार्ड न किया जाए।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः यह कोई अच्छी रिवायत थोड़े ही है। ये किस बात का प्वायंट ऑफ आर्डर मांग रहे हैं। यह

प्वायंट ऑफ आर्डर के मुतल्लक कुछ भी नहीं जानता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी हाउस को चलने भी दो। अगर ऐसे करोगे तो हाउस कैसे चलेगा?

श्री नरेश कुमार बादली: स्पीकर साहब, इन्होने 2 लाख 60 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एस०ई०जेड० की जमीन ली थी। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये तो .... आदमी है। इसको तो पता ही नहीं हैं कि क्या बना है और कहां बना हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लोग हाऊस का समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, ये झूठ बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: बैठ जा .... न हो तो। इसको तो पता ही नहीं कि यह क्या बोल रहा है और किस बात पर बोल रहा है। यह इनका बोलने का कोई तरीका है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: No, No. This is not the way. आप सब बैठ जाओ। Take your seats. (विघ्न) इस ...... वर्ड को रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) आप क्या करते हो?

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप हम सबको तो एक कलम से पूरे सदन के लिए निष्कासित कर देते हैं और जो ये लोग गैर जरूरी बातों पर सदन का समय बर्बाद करते हैं उन पर कोई ऐक्शन नहीं ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपुसे फिर मोहतबाना अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मुझे बोलने देना है तो मैं तथ्य पर आधारित बात करने जा रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आप जब भी शुरु होते हो, शोर मचता है। आप तथ्यों पर आओ।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः मैंने तथ्यों पर बात की तो उस पर नरेश बादली ने प्वायंट ऑफ ऑर्डर उठा दिया। यह क्या बात हुई? यह कोई ठीक बात नही है कि ये इस तरह बोलें।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, आप भी तथ्यों से इधर–उधर हो जाते हो। आप केवल बजट पर बोलो तो ठीक बात रहेगी। (शोर एवं व्यवधान) मैडम, आप बैठिये।

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, ये हमारे को कुछ भी बोलते रहेंगे और हम बैठ जाएंगे, यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्षः अनीता जी, आप प्लीज बैठ जाएं।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अनीता जी, क्या आप असलियत को नकारोगे? अध्यक्ष महोदय, ये किस बात पर बोल रही हैं और किसने इनको अलाऊ किया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Madam, please take your seat.

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। हमारी खुद की जमीन एस०ई०जैड० में गई हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये ..... आदमी क्या कह रहा है, ये कोई तरीका है इसका।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ये शब्द तो कार्यवाही से निकलवा दे।

श्री अध्यक्ष: यह शब्द जो चौटाला जी ने कहा है इसे रिकार्ड न किया जाए।

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, बेहूदगी वे कर रहे हैं और आप लांछन हम पर लगा रहे हैं। इनसे पूछो कि प्यायंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो कमाल हो गया है। इधर यह और उधर वह कुछ कहता है। कोई हाऊस चलने ही नहीं देता।

(इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सारे माननीय सदस्य एक साथ खडे हो गए और जोर जोर रो बोलने लगे।)

Mr. Speaker: I will not proceed like this. The House is adjourned for half-an- hour.

(The Sabha then adjourned at 12.06 P.M. and re-

assembled at 12.36 P.M.)

वर्ष 2010–2011 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्स, जैसा कि मैंने डिस्कशन शुरू होने से पहले एक बात कही थी कि सभी माननीय सदस्य बजट पर ही बोलें, किसी भी माननीय सदस्य ने बोलते हुए एक–दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। अब मैं फिर कहता हूं कि आप सभी कृपा करके केवल बजट पर ही बोलें, एक दूसरे के बारे में कुछ भी पर्सनल रिमार्क्स न करे क्योकि जब ऐसा माहोल हो जाता हे तो मेरे लिए हाऊस चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, में कांग्रेस विधायक दल के साथियों की तरफ से ओर इस सदन की तरफ से भी आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार भी और मुझे भी यह विश्वास है कि सत्ता पक्ष के साथ–साथ विपक्ष भी चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथी हों चाहे लोकदल पार्टी के साथी हों और चाहे दूसरे हमारे साथी हों, हम सब की मन्शा है कि यहां पर आपस में जो चर्चा हो वह एक हैल्दी, डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन के अन्दर हो। मेरा आपसे नम्र निवेदन भी है कि किसी सदस्य को दूसरे सदस्य का अनादर करने का, गाली देने का और गन्दी भाषा का प्रयोग करने का कोई अख्तियार नहीं है।

श्री अध्यक्षः ठीक बात है, कोई अधिकार नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः एक सम्मानित सदस्य ने दूसरे सम्मानित सदस्य को पागल कहा। एक महिला मंत्री को कहा कि तुम बेवकूफ हो, एक सम्मानित सदस्य को कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। सर, वह भाषा हरियाणा के लोगों ने बदल दी। वह समझना पड़ेगा। दो चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार को सत्ता में आए 6 साल हो चुके हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी क्या सुझाव दे रहे हैं, यह कोई स्पीच नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अरोड़ा साहब, मैं आपकी बात नहीं कह रहा आप फिर क्यों चिन्ता में पड़े हुए हैं?

Mr. Speaker: He had assured for your party.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, इन्हें अपना रवैया, अपना चरित्र, चेहरा और तरीका सारे ठीक करने पड़ेंगे।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की हे ओर अब में फिर कह रहा हूं कि हमारी तरफ से कभी भी इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं हुई है। कादियान साहब भी जब बोल रहे थे तो किसी ने टोका–टाकी नहीं की। ज्यों ही मैंने बोलना शुरू किया, विशेष रूप से जो हाऊस में सुझाव देने की बात करता है वह सबसे ज्यादा गड़बड़

करता हे। आपको में एक बात ओर कह दूं कि हम आपको पूरी तरह से कोआपरेट करते हैं। हमारी वजह से अगर आपको पीड़ा हुई है तो हम इसके लिए क्षमा मांगते हें। सदन का कोई भी सम्मानित सदस्य अगर किसी सदस्य पर किसी प्रकार का आक्षेप करने की कोशिश करता हे तो यह हम टोलरेट नहीं करेंगे। मैं बजट से बाहर जाकर बात नहीं करूंगा लेकिन जब ऐसे लोग खडे हो जाते हैं जिन्हें यही पता नहीं कि प्वायंट ऑफ आर्डर क्या होता है तो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बात आप देखेगे कि प्वायंट ऑफ आर्डर बनता है कि नहीं बनता। मेरे समय को खराब करके फिर प्वायंट ऑफ आर्डर की आडू लेकर ये लम्बे–लम्बे भाषण देने शुरू कर देते हैं। यह कोई अच्छी रवायत नहीं है। आप हाऊस के करटोडियन हें हाऊस को अच्छे ढंग से चलाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं एस०ई०जैड० का जिक्र कर रहा था। हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार ने यह एस०ई०जैड० सैंक्शन किए हैं लेकिन किसी एक में भी धुंआ निकलने वाली चिमनी कहीं नहीं लगी है। बात यह की गई थी कि लाखों युवकों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के नाम के ऊपर जैसे मैंने बताया कि रिलांयस को 1500 एकड़ भूमि 370 करोड़ रूपये में दे दी और वह भूमि जो एच०एस०आई०आई०डी०सी० की लोगों की भलाई के लिए अधिग्रहण की गई थी, उसी जमीन का एक हिस्सा 4 एकड़ का 290 करोड़ रूपये में नीलाम हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मपालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जब आप इनको अवसर देंगें तो ये अपनी बात बता देंगें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब देने का इनको अवसर मिलेगा। आप जिसको चाहे बुलवा लें लेकिन ये मुझे बीच मे न टोके। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please, let me hear.

श्री अशोक कुमार अरोडाः अध्यक्ष महोदय, जब सरकार रिप्लाई देगी उस समय ये अपनी बात बता लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ये कौन से रूल्ज के तहत प्वांयट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछिए कि ये प्वांयट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं या इनका कोई सुझाव है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मपालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अगर इनका प्वांयट ऑफ आर्डर है तो वैल एण्ड गुड लेकिन ये सुझाव नहीं दे सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये सुझाव देने नहीं बल्कि प्वांयट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए खड़े हुऐ हें।

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सुझाव के लिए जब आप अवसर देंगें तब ये बोल लेंगे। (शोर एवं व्यवधान) ये प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है। ये प्यांयट ऑफ आर्डर जानते ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मपाल: अध्यक्ष महोदय, बात को घुमाया जा रहा है और सदन को गुमराह किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) मेरा प्यांयट ऑफ आर्डर है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सदन में एस०ई०जैड० के बारे मे व्यान कर रहे थे और इस पर शोर शराबा भी हुआ। एस०ई०जैड० की पहली नोटिफिकेशन इन्हीं की सरकार में 29 जनवरी को हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है। ये प्वांयट आफ आर्डर जानते ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, यह प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है। यह तो स्टेटमैंट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मपालः अध्यक्ष महोदय, ये उस स्टेटमैंट को घुमाकर कह रहे थे लेकिन मैं वास्तविकता सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) I want to put the real record of SEZ by whom it was started. I do not know what was the intention of that Government?

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इनको समझाइए कि ये प्वांयट ऑफ आर्डर पर बोलें, सुझाव न दें। रिप्लाई और सुझाव देने का काम मुख्यमंत्री का है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मपालः अध्यक्ष महोदय, 29 जनवरी, 2003 को चौ० ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, इन्होंने सैक्शन 4 की नोटिफिकेशन की। उसके बाद 28 जनवरी, 2004 को सैक्शन 6 की नोटिफिकेशन हुई। हमारी सरकार ने सैक्शन 9 की और .... (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होने जो रेट फिक्स किए थे वे खांडसा गांव के? लाख रूपये प्रति एकड़ और निरसिहपुर गांव के 9 लाख रूपये प्रति एकड़ थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, यह पांयट आफ आर्डर कहां से आ गयी?

श्री धर्मपालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हमने जमीन कोड़ियो के भाव में दी। अध्यक्ष महोदय, जमीन कोड़ियों के भाव में तो इन्होंने दी थी। हमने तो इनसे तिगुने रेट जमीन के दिए थे। हमारी सरकार ने आर.आर यानि रिहैबलीटेशन और

रिसैटलमैंट की पोलिसी बनाई। उस पोलिसी के तहत बच्चों को रोजगार देना था। एस.ई.जैड के लिए जिन गांवों की जमीन जा रही थी उन गांवों के लोगो को सराउडिंग में एक–एक कमर्शियल शॉप भी देनी थी। इस तरह से हर तरह की सुविधा एसईजेड में होने जा रही थी।

Mr. Speaker: Thank you. ठीक है अब आप बैठिए।

श्री धर्मपाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो रेट फिकर किए थे हमारी सरकार ने उनसे तिगुने रेट जमीनों के दिए। किसी आदमी ने भी एक्वायर की गई जमीन के मुआवजे के लिए मना नहीं किया। सबने अपना मुआवजा ले लिया। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह बात को घुमाकर कहना कि एस.ई.जैड के लिए जमीन कोड़ियों के भाव दी गई, ठीक नहीं है। हमने जमीन कोड़ियों के भाव नहीं दी 1 कोड़ियो के भाव मे तो इनकी सरकार लेने जा रही थी। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही इस बारे में ऐलान किया था।

Mr. Speaker: your point is clear. अब आप बैठिए।

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे बोलने की अनुमति है क्योंकि मैं अभी तक बोल नहीं पाया? अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं फिर आप बीच में घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात को फिर दोहराना चाहता हूं जो रिकार्ड की बात है। एचएसआईआईडीसी. ने जो जमीन

अधिग्रहण की थी उसमें से लगभग 1500 एकड़ जमीन रिलांयस को दी गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह बात पहले हो गई है।

चौ० ओम प्रकाश चोटाला: अध्यक्ष महोदय, ये बात पहले नहीं हुई। जो बेकायदगियां हुई मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। राव धर्मपाल जी को भी तथ्यों का ज्ञान नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड की बात बताऊंगा उसमें से 25 परसैंट जो जमीन सरकार ने रिलांयस को देनी थी वह पहले ही दे दी। उन्होंने यह जमीन खरीदी नहीं थी वो जमीन जो थी केवल मात्र 370 करोड़ रुपये मे दी और उस जमीन का एक हिस्सा चार एकड़ का एच०एस०आई०आई०डी०सी० ने ओपन ऑक्शन में नीलाम किया तो 290 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ है। अब आप स्वयं देख लें कि इसमें कितना भारी घपला हुआ है जबकि एक भी कारखाना नहीं लगा है। उस जमीन की जो चारदीवारी की गई हे, फेसिंग की गई है, आज भी हरियाणा पुलिस उसका पहरा दे रही हे। जिन जमीदारों से यह जमीन ली गई थी उनको यह कहा गया था कि 10 हजार रुपये महीने के हिसाब से आपको हर महीने मिलेगा किसी एक जमीदार को भी नहीं मिला हे। (विघ्न) किसी एक को भी नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी इस पर श्वेत पत्र जारी कर दें ताकि पूरे प्रदेश के लोगों की तसल्ली हो जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का एक ओर केस है। अध्यक्ष महोदय, एक प्राईवेट बिल्डर को गुडगांव मे जनहित मे सरकारी खर्च पर वर्ष 2003– 04

मे अधिग्रहण की गई लगभग 300 एकड़ भूमि एक मात्र टेण्डर पर दे दी। कोई दूसरा टेण्डर नहीं था एक मात्र टेण्डर पर ही एक बिल्डर को 1500 करोड़ रुपये में वह जमीन वर्ष 2009 में दी गई। अध्यक्ष महोदय, आज उस जमीन की कीमत 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर है। अब आप स्वयं इसकी इन्क्वायरी करें कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ हे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के घपले अगर मैं गिनाने शुरू करूंगा तो सारे घपले गिनाने में बहुत लम्बा समय लग जायेगा। एस०ई०जैड० की आड़ मे किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई और किसान को यह आश्वासन दिया गया कि तुम्हें हर वर्ष दस हजार रुपये मिलेगा लेकिन किसी को एक दबन्नी नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, एच०एस०आई०आई०डी०सी० की तरफ से जो इण्डस्ट्रियल प्लाट दिए जाते हैं उन इण्डस्ट्रीज प्लाट्स के लिए दरखास्तें मांगी जाती हैं ओर उन दरखास्तों में ये सारी सूचना देनी पड़ती है कि इसका उद्योग में कितना अनुभव है, क्या इसके पास असासा है, कहां–कहां इसने 'उद्योग स्थापित किए हैं? अध्यक्ष महोदय, किसी भी एक इण्डस्ट्रिलिस्ट को कोई भी प्लाट इस प्रकार नहीं दिया गया बल्कि ऐसे लोगों को दिया गया जिनका उद्योग से कोई वास्ता ही नहीं है। इसमें कितना पैसा कमाया गया होगा, आप अंदाजा लगायें। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कही थी अब फिर दोहरा रहा हूं ये तो रिकार्ड की चीज है कि पांच साल के अर्से में एक भी हुडा का सेक्टर हरियाणा प्रदेश में नहीं कटा। (खांसी)

Chief Parliamentry Secretary (Shri Dharambir Singh): On a point of order, Speaker Sir, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2010 तक 15194 एकड़ जमीन पर रेजीडेंशियल सेक्टर काटे हैं। (विघ्न)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूंगा, धर्मबीर।

श्री धर्मबीर सिंहः नही, कम से कम हाउस को बरगलाना नहीं चाहिए स्पीकर सर, अकेला यह नहीं 2 लाख 29 हजार 500 प्लाट 100– 100 गज के महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती स्कीम के तहत दिये हैं। (विघ्न)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः यही मैं बताने जा रहा हूं।

Dr. Raghuvir Singh: Speaker Sir, it is a breach of privi lege of the House. Wrong facts are being given on the table of the House. (interruptions)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिसका उल्लेख किया है मैं आपके नोटिस में आपके द्वारा फिर आश्वास्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के वक्त में जो हुडा के प्लाट काटे गये थे उनमें जो– जो प्लाट बाकी रह गये थे वो प्लाट ही सरकार ने दिए है कोई नया सेक्टर नहीं काटा गया है।

P.W.D. (B & R) Minister (Shri Randeep Singh Su rjewala): Sir, on a point of order.

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः मैं floor of the House कह रहा हूं कोई नया सैक्टर नहीं कटा। सेक्टर काटने के लिए दफा 4 के नोटिस दिए जाते हैं (विध्न) प्राईवेट बिल्डर ....

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः सर। यहां पर लिखा है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और on the floor of the House मैंबर ने बात कही है कि कोई हुडा ने जमीन एक्वायर नहीं की है और कोई सैक्टर नहीं काटा। मेरी यह आपसे दरखास्त है जब कोई सदस्य हाऊस को बरगलाता है तो it's a breach of privilege. You constitute a House Committee. Sir, It's a clear breach of privilege on the part of Shri Om Parkash Chautala. मैं जमीन एक्यायर करने की डेट दे रहा हूं सर। 1.4.2005 से लेकर 31 मार्च, 2006 के बीच में हरियाणा सरकार ने, हुडा ने 6210 एकड जमीन एक्वायर की है। 1.4.2006 से लेकर 31 मार्च, 2007 के बीच में हुडा ने 1303 एकड जमीन एक्वायर की है। 1.4. 2007 रमे लेकर 31.3.2008 के बीच मे 2268 एकड़ भूमि हुडा ने एक्वायर की है। 1.4. 2008 से लेकर 31.3.2009 के बीच में हुडा ने 559.62 एकड भूमि एक्वायर की है और 1. 4.2009 से लेकर 23 फरवरी, 2010 इस साल तक 4853.1 एकड़ भूमि एक्वायर की है।

स्पीकर सर, पिछले पांच साल में हुडा ने 15,194 एकड़ भूमि एक्वायर की। जो माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है वह सरासर असत्य है। यह उन द्वारा एक प्रकार से सदन को बरगलाने की कोशिश की गई है। स्पीकर सर, हमने

कुल मिलाकर 29500 प्लाट्स दिये हैं। इनमें से हमने 28879 रेजीडेंशियल प्लाट्स दिये हैं, 169 इंस्टीक्रशनल प्लाट्स दिये हैं, 90 इण्डस्ट्रियल प्लाट्स दिये हैं। यह मैंने हुडा की एस्टेट के बारे में बताया है। इसके अलावा हमने ग्रुप हाऊसिंग साईट्स के 321 प्लाट्स दिये, हॉस्पिटल साईट्स के लिए 10 प्लाट्स दिये, 31 प्लाट्स पैट्रोल पम्प साईट्स के लिए दिये। स्पीकर सर, इस प्रकार से हमने कुल 29500 प्लाट्स दिये। Speaker Sir, I request let constitute a House Committee. I challenge Ch. Om Prakash Chautala. (Noise and Interruptions) It is a clear case of breach of privilege and misleading this House.

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहने जा रहा हूं कि जब से यह हुड्डा सरकार सत्ता मे आई उसके बाद से दफा 4 के नोटिसिज देकर भूमि तो अधिग्रहित की गई लेकिन हुडा का एक भी नया सैक्टर नहीं काटा गया। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, यह रिकार्ड की बात है। इसको कैसे नकारा जा सकता है। अगर फिर भी किसी को इरा बारे में कोई शक है तो आप सदन की कमेटी मुकर्रर करे वह इसकी इंक्वायरी कर लेगी। हम इससे सहमत हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह खुद कह रहा हूं कि दफा 4 के नोटिसिज तो दिये गये और जमीन का अधिग्रहण भी किया गया।

उसके बाद औने–पौने दामों में अंदरखाते किसानों से जमीन खरीदकर प्राईवेट बिल्डर्ज को दे दी गई। स्पीकर सर, इतना सब करने के बाद दफा 4 के नोटिस को विदड्रा कर लिया

गया और फिर उन प्राईवेट बिल्डर्ज को वहां पर प्लाट्स काटकर हाऊसिज की कंस्ट्रक्शन करने के लिए लाईसैंस दिये गये। स्पीकर सर, इस प्रकार से कितनी जमीनों पर हाऊसिज बनाने के लाईसैंस प्राईवेट बिल्डर्ज को दिये गये इससे सम्बंधित मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। स्पीकर सर, इतना ही नहीं कोर्ट की तरफ से हर रोज सरकार के खिलाफ स्ट्रीक्चर पास हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये इस बात को नकारते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहने जा रहा था कि किस प्रकार से किसान की बहुमूल्य जमीनें बेदर्दी से लूटी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैं बता रहा था कि एक दूसरी कम्पनी को फायदा पहुंचाने के कारण 10 हजार करोड़ रूपये का स्टेट का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज मौजूदा सरकार के लोग किसानों का हितैषी होने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमने किसान को बहुत राहते प्रदान की हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी एक किसान हैं और आप कृषि मंत्री भी रहे हैं। मैं इस बात के अंदर नहीं जाता कि हरियाणा प्रदेश के किसानों ने कितना उत्पादन किया? मैं इस बात में भी नहीं जाना चाहता कि हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से केन्द्रीय पूल में कितना अन्न दिया गया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन चार सालों के अरसे में अगर कहीं पर बारिश हो गई हो और अगर किसान ने अपने प्रयासो से डीजल फूंककर अपनी फसल पका ली हो लेकिन हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसको अपनी फसल को पकाने में कितनी दिक्कतो का सामना करना पड़ा होगा। अध्यक्ष महोदय, अभी एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री महोदय ने

यह कहा था कि हमारे पास खाद की कमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि एक–एक थैला खाद के लिए किसान को राशन कार्ड हाथ में लेकर बीडीओ. के दफ्तर के आगे लाईन में लगकर खड़ा होना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी रात को उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, बिजाई के मौके पर डी.ए.पी. खाद उपलव्य नहीं है और फसल को पकाने के लिए यूरिया उपलब्ध नहीं है। यूरिया खाद ब्लैक में मिलता है। स्पीकर सर, इस सबके बावजूद भी अगर प्रभु की कृपा से किसान की फसल पक जाये और किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मार्किट में लेकर जाये तो उस किसान को भी इन्होंने चोर बना दिया। इनकी सरकार ने यह फैसला किया कि किसान अगर अपनी फसल के उत्पादन को मण्डी मे बेचने के लिए जायेगा तो उसे अपनी जमीन की फर्द अपने साथ लेकर यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि यह मेरे खेत का ही उत्पादन है। अध्यक्ष महोदय, यह हालत आज हरियाणा प्रदेश की हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के अंदर सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे यह जानकर कि तीन–तीन महीने तक नहरों मे पानी नहीं आता। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एडहॉक बेसिज पर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट में पम्प ऑपरेटर नियुक्त किये गये और उन्हें महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी में ड्यूटी ज्वाईन करके बैठा दिया गया। वे लोग एक दिन के लिए वहां पर गये और अपनी ड्यूटी ज्वाईन करके आ गये। स्पीकर सर, उसके बाद उनमें से कोई भी अपनी ड्यूटी पर

नहीं जाता है। इसके बावजूद भी वे अपनी तनखाह घर पर बैठकर ले रहे हैं क्योंकि वे एक व्यक्ति विशेष के हल्के के लोग हैं। इसलिए वे वहां पर नौकरी करते हुए भी वे अपने घर बैठकर मौज लूट रहे हैं। हालत यह है कि कहीं पर भी कोई पम्प काम नहीं कर रहा है, नहरों मे पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि हरियाणा प्रदेश के लोगो को राजस्थान से पीने का पानी लेकर आना पड़ता है। इसके अलावा कहीं–कहीं पर लोग गंदा पानी पीने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। इस सबके बावजूद भी हमारे मंत्री महोदय लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई यही हे कि इन्होने स्वास्थ्य के नाम पर कहीं कुछ भी नहीं किया। कहीं पर भी एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया और जिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्ज के पद खाली पड़े हैं उनको भी नहीं भरा गया है। स्पीकर सर, हॉस्पिटल्ज में दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं। उचित ईलाज और दवाईयों के अभाव में लोग मर रहे हैं। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। स्पीकर सर, पीलिया जैसी नामुराद बीमारी जिसका कोई ईलाज नहीं है वह भी हरियाणा प्रदेश में फैल रही हे। अध्यक्ष महोदय, शायद आपको भी इसकी सारी इन्फर्मेशन होगी। आज ये लोग बिजली की बात भी बड़े गर्व के साथ करते हैं कि हमने बिजली का बहुत उत्पादन किया है। अध्यक्ष महोदय, मै ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन तथ्यों पर आधारित कुछ बाते मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में भी सरकार ने बड़े बुलंद दावे किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय मे राज्य में बिजली का उत्पादन बढा था यह रिकॉर्ड की बात है। इनकी सरकार बनने के बाद हरियाणा में कहीं एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं हुई। यमुनानगर मे दीनबंधु सर छोटूराम नाम का जो थर्मल पॉवर प्लांट लगा था उसका सारा श्रेय हमारी सरकार को जाता है। हमने उसको रिलायन्स को दिया था और प्रदेश के हितों की रक्षा करते हुए पैसा बचा कर दिया था। उनके साथ शर्त रखी थी। उनके साथ एग्रीमैंट किया था। मैंने बतौर मुख्य मंत्री उसकी आधारशिला रखी थी ताकि उसका काम चालू हो सके। अध्यक्ष महोदय, जो यूनिट उन्होने लगाई है उसमे चाईना की एक कम्पनी की हिस्सेदारी थी। हमारे एग्रीमैंट के मुताबिक वे उसको बदल नहीं सकते थे। हमारी सरकार के समय में उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि हमें इस कम्पनी को बदलने की अनुमति दी जाये लेकिन हमने उसको बदलने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने दोबारा से दरख्वास्त दी लेकिन कांग्रेस की सरकार ने भी उसको रिजैक्ट कर दिया। उसके बाद एक महीने में ही दोबारा नई दरख्वास्त लेकर उनको कम्पनी बदलने की अनुमति दे दी गई। कैसे दे दी गई यह तो आप पता कर सकते हैं या सरकार इस बारे में श्वेत पत्र जारी करे। अध्यक्ष महोदय, जो अंदेशा हमे था कि यह कम्पनी ठीक नहीं है, इसकी वजह से नुकसान होगा और वही हुआ। आज यह प्रमाणित हो गया है कि वह कम्पनी ठीक नहीं थी। यमुनानगर की जो यूनिट अब

बन्द पड़ी है वह बंद इसलिए पड़ी है क्योंकि जो मशीनरी वहाँ पर लगाई गई है वह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट मे जो एश हैंपर लगी हैं जो वेस्ट राख को पानी में मिलाकर बाहर फैंकते हैं यमुना पास लगती है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी लेकिन उन पर लोड पड़ गया और वह टूट गई और उसकी वजह से Electric State Prosection बेकार हो गई, सारी की सारी यूनिट बेकार पड़ी है। अखबारों में खबर छपती है जिसमें सरकार कहती है कि 15 दिन मे वह तैयार हो जायेगी लेकिन अध्यक्ष महोदय, वह 6 महीने में भी तैयार नहीं हो पायेगी। इससे प्रदेश का 5 करोड़ रुपये रोजाना का नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी और उनको यह कहा था कि जिस कम्पनी को आप यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट को देने जा रहे हैं उसको आपकी सरकार ने भी रिजैक्ट कर दिया था और हमने भी रिजैक्ट कर दिया था। अतः उनको आप मत दीजिए, उनसे बिजली का उत्पादन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार गई थी, उस समय मैंने रैजिगनेशन देने से पहले एक बात कही थी कि चूंकि जनता ने हमें समर्थन नहीं दिया इसलिए हम त्याग पत्र देते हैं तथा सरकार को आश्वासन देते हैं कि प्रदेश के हितार्थ अगर सरकार कोई अच्छे काम करेगी तो हम उसको पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे। उस सहयोग और समर्थन के बलबूते पर हमने सरकार को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का जो जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है आपकी अनुमति से मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जवाब दिये जाते हैं। जिस चिट्ठी में मैंने सुझाव दिया था उसका जो जवाब दिया उसमें मुख्य मंत्री जी लिखते हैं कि

"Dear Shri Chautala, I have received your letter No.---- dated 9.11.2006. The tone and tenor of your letter saddened and amused me as well." इनको दुखः भी हुआ तथा प्रसन्नता भी हुई।

`Saddened because as a former Chief Minister you ought to understand the procedures and process of open international competitive bidding which the HPGCL is following in a totally transparent manner.'

(noises & interruptions)

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, यह बजट से संबंधित बात नहीं है। एक चिट्ठी उन्होंने लिखी उसका जवाब तो आपको गोपनीय रखना चाहिए था। ऐतबार की बात तो यह थी कि उसका जवाब आप छाती से लगा कर रखते। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओमप्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप जरा सुनिए तो सही कि चिट्ठी का जवाब कैसे दिया गया है? आप थोड़ी सी पेशैंस रखें (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश के हित के लिए सुझाव दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नहीं, आप इसको रहने दो चौटाला साहब। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: एक मिनट सुनो, अध्यक्ष महोदय, जो वर्डिंग है वह आप सुनो।

"Therefore, your apprehensions of any favour or any deviation from the laid down system are totally misplaced and unfounded. Similarly, your allegations regarding SEZ and Yamunanagar Thermal Plant are germane to either your ignorance of the issues or deliberate attempt to mislead the people. Amused because it looks like the case of a blind man groping in a dark room to search for a black cat. which is not there.'

13.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्री की भाषा है और अध्यक्ष महोदय, वह ब्लैक कैट फिर रही है। वह चौराहे पर फिर रही है। अध्यक्ष महोदय, वह बंद पड़ा है और 5 करोड़ रूपये रोजाना सरकार का नुकसान है। किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है। उस चिट्ठी में आगे लिखा है कि

"I know that you within your heart are fully convinced that this Government's programmes, policies and actions are transparent and fair which were never before."

अध्यक्ष महोदय, क्या यह मुख्यमंत्री की भाषा है? हमने एक सुझाव दिया था और उसका इरा तरह से जवाब दिया जाता है। मैंने इस चिट्ठी को उजागर नहीं किया, प्रैस को यह चिट्ठी रिलीज नहीं की। मैंने सोचा कि जिस प्रकार की भाषा का ये

इस्तेमाल करते है, उसी कैटगरी में मैं शामिल न हो जाऊं। मैंने फिर भी इनकी बातों को निभाने का प्रयास किया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली उत्पादन का ताल्लुक है आज सारी की सारी बिजली की यूनिट्स खराब पड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, 600 मैगावाट वाले दीन बड सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट का सितम्बर, 2004 में हमारे शासन काल में रिलायंस कम्पनी को काम दिया गया था। एग्रीमैंट के मुताबिक इस प्रोजैक्ट को 27 से 30 माह के अन्दर पूरा किया जाना था और बिजली बननी चाहिए थी लेकिन सरकार की नीति केवल निजी कम्पनी को लाभ पहुंचाने की है। क्योंकि आज भी उसकी वही हालत है। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त थर्मल पावर प्लांट के 300–300 मैगावाट के दो यूनिट्स को मार्च, 2007 और जून, 2007 में एग्रीमैंट के मुताबिक चलना चाहिए था। इनकी सरकार ने अप्रैल, 2008 और जून 2008 में उनको शुरू किया था और अभी भी वे ठीक ढंग से नहीं चल पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस देरी की वजह से 428 यूनिट्स बिजली के उत्पादन का नुकसान हुआ है। आप इसी से अन्दाजा लगाएं कि कितना किसान का नुकसान हुआ होगा और कितना सरकार का नुकसान हुआ होगा। इसके अतिरिक्त रिलांयस कम्पनी द्वारा स्वीकृत पैमाने के अनुसार थर्मल पावर प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर 80 प्रतिशत होना था जो कि 69 प्रतिशत ही हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आपको बोलते हुए 30 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है। आप कन्क्रल्यूड करो। (विघ्न)

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म करता हूं।

P.W.D. (B.& R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): Sir, **I** want your ruling on one issue. Chautala Sahib can refer to papers when he delivers his speech. But can he read the written speech? Speaker Sir, I want your ruling about it.

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड बता रहा हूं। आज पानीपत थर्मल पावर प्लांट की तीन यूनिट्स बंद पड़ी हुई हैं। आज इस वक्त किसानों को बिजली की अति आवश्यकता है। आज किसान की फसल को लास्ट पानी चाहिए। बिजली की कमी की वजह से उसे कितना भारी नुकसान होगा, उसके क्या परिणाम निकलेंगे इस बात की चिन्ता सरकार को नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज आम आदमी को बिजली नहीं मिल रही हे। लोग ढाणियों में और डेरों मे इसलिए गए हैं कि उनको बिजली नहीं मिलती है। ट्रिपिंग की वजह से बिजली आते ही चली जाती थी। लोगों ने वहां पर जाकर डेरे इसलिए लगाए ताकि जब भी बिजली आए तो उसका वे इस्तेमाल करे। अध्यक्ष महोदय, आज उन डेरों के लोगों को डोमैस्टिक बिजली नहीं मिल रही है और कॉमर्शियल बिजली जो एग्रीकल्वर के हिसाब से मिलती है वह महंगी मिलती है। वह चार–पांच घंटे ही आती हे। उन लोगों की क्या हालत होगी इस पर किसी ने विचार नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष. टाईम हो गया है। आप प्लीज बैठ जाएं। (विघ्न)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः नहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी कहां टाईम हुआ है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्यायंट ऑफ आर्डर। मैं चौटाला जी को कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर की बिजली कामर्शियल नहीं होती है। एग्रीकल्चर बिजली 25 पैसे प्रति हार्स पावर के हिसाब से दी जाती हे। इन्होंने कहा कि डेरों में जो कमर्शियल बिजली होती है एग्रीकल्चर के हिसाब से दी जाती है। कमर्शियल बिजली फैक्टरियों को दी जाती है। एग्रीकल्चर बिजली का डिफरैंट रेट है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इस बारे में रिकार्ड निकलवाकर देख लें। (विघ्न)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा टाईम ये इसी तरह से खराब करते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये बिजली की खरीद की बात करते हैं तो बिजली की खरीद बहुत महंगे दामो पर हो रही है जिस वजह से स्टेट को बहुत नुकसान हो रहा है। हजारों करोड़ों रूपयों का बोझ उपभोक्ता पर पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक नया सिस्टम और बनाया है। टयूबवैल्ज के उपर लो टैंशन तारो को हाई टैंशन तारों मे बदल रहे हैं। इससे नुकसान हो रहा है और तारे भी ढीली पड़ रही है।

किसानों की जिंदगी खतरे मे है और इनको इस बात की चिन्ता ही नहीं है।

श्री अध्यक्षः चौटाला जी, थैंक यू।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः नहीं—नहीं, अभी नहीं। मेरा टाईम तो ये लोग ले गए हैं।

श्री अध्यक्षः आपका समय हो गया है।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, मुझे बोलते हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। मेरा अधिकत्तर समय तो ये ले गए हैं।

श्री अध्यक्षः चौटाला जी, आपको बोलते हुए 43 मिनट हो गए हैं। अब तो सभी शान्ति से बैठे हुए हैं। अब तो कोई बीच में बोल ही नहीं रहा है।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सवाल बोलने का या न बोलने का नहीं है। सवाल तो यह है कि मैं अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचा सकुंगा।

श्री अध्यक्षः आपकी बात तो शाम तक नहीं मुकेगी।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः बिलकुल नहीं मुकेगी। जब तक आप दूसरों को बीच में भाषण देने की अनुमति दोगे तो नहीं मुकेगी। (विघ्न) अगर आप इस तरह से इनको बीच में बोलने की

इजाजत दोगे तो कैसे चलेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये उद्योग की बात करते हैं, हरियाणा में बड़े दावे किए गए थे कि इतना बड़ा निवेश आया है। मुख्यमंत्री जी कई मर्तबा विदेशों में भी जाकर आए हैं। हरियाणा में एक भी नया निवेश नहीं हुआ हे। हरियाणा के उद्योग प्लायन करके जा रहे हैं क्योकि सारी सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं और सरकारी नौकरियों में धांधली मची हुई हैं कहीं रिलांयस के नाम पर, कहीं एस.ई. जैड के नाम पर और कहीं उद्योग के नाम पर।

लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जो लिबर्टी फैक्ट्री करनाल की थी उसके सामने न तो हमने गढ्ढे खुदवाए और न हम टर्न ओवर के हिसाब से टैक्स मांगा करते हैं। 38 सालों में हरियाणा मे 40 हजार करोड़ रूपये का निवेश हुआ जबकि हमारे समय में 40 हजार करोड़ रूपये का निवेश जमीन पर हो चुका है और 60 हजार करोड़ रूपये का निवेश पाईप लाईन में है।

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो नहीं चलेगा। ये कौन होते हैं, ये किस हैसियत से बार बार सुझाव देने के लिए खड़े हो जाते हैं? इनको कुछ सीमा रखनी चाहिए, थोड़ा सा हाउस का डैकोरम बनाए रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जिम्मेवारी भी है।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब,मेरे साथ आपकी भी जिम्मेवारी है।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से समझता हूं। आपकी जो पीड़ा है उसमें मैं स्वंय भी पीडित हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी पीड़ा समाप्त हो जाए। आपकी पीड़ा दूर करने का तो मेरे पास हक नही है लेकिन मेरी आपके साथ हमदर्दी जरूर है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार अपने आपको बहुत ज्यादा मजूदर हितैषी होने का दावा करती है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हमारी सरकार के वक्त 950 एकड़ जमीन पर मानेसर में मजदूरों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाने के लिए एक योजना बनायी गयी थी और उस जमीन का अधिग्रहण करने के लिए हम जब बिल लाए थे तो उस समय आज के मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता हुआ करते थे। इन्होंने उस समय उस पर बहुत शोर मचाया था और कहा था कि वह जमीन कौड़ियों के भाव दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार चली गयी ओर इनकी सरकार आ गयी। वही जमीन जो कर्मचारियो और मजदूरों के आवास बनाने के लिए मिलनी थी उसका अवार्ड मुकर्रर हो गया था ओर एक दिन पहले डिप्टी कमिश्नर को 50 करोड़ रुपये उनको तख्सीम के लिए भेज दिये गये थे लेकिन अगले ही दिन उन्होंने सारी की सारी जमीन का अधिग्रहण वापिस ले लिया और ऐसे लोगों को वह जमीन दे दी जिन्होंने उसमें बेइन्तहा पैसा कमाया। आप सोचिए कि कितना भारी घपला हुआ

होगा? अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसके बारे में भी एक कमेटी मुकर्रर कर दें ताकि इसकी भी इंक्वायरी हो जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक है चौटाला साहब, अब आप अपनी बात जल्दी खत्म करे।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। ये कहते हैं कि इन्होंने किसानों को गन्ने का भाव बहुत अच्छा दिया। इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय को भी गुमराह किया। गवर्नर साहब के अभिभाषण में एक बात कही गयी है कि सरकार ने हरियाणा के किसान को गन्ने के दाम सबसे ज्यादा दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज भी हरियाणा प्रदेश के गन्ने के दाम सबसे ज्यादा नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु मे हमारे से ज्यादा गन्ने के दाम मिलते हैं। हमारे प्रदेश के किसान को गन्ने के दाम ज्यादा नहीं मिलते हैं। किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 31 दिसम्बर को अपने जिले में एक शुगर मिल का उद्घाटन किया था और यह दावा किया था कि यह शुगर मिल एशिया में सबसे अच्छी शुगर मिल है। इससे सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होगा क्योकि इसमें सबसे अच्छी मशीनरी लगायी गयी है। अगले ही दिन वह शुगर मिल बंद हो गयी। उस मिल को वहा के कर्मचारियो और अधिकारियों ने यह कहकर बंद कर दिया कि उसकी मशीनरी नकारा है इसलिए यह मिल चल नहीं पाएगी। लोगों ने जब विरोध किया तो सरकार ने बचने के लिए उसको

चलाने का काम किया। एशिया की सबसे अच्छी मिल को चलाने के लिए ऐसा किया गया। अध्यक्ष महोदय, उसमें 4 लाख 18 हजार क्विंटल गन्ने की पिराई की गयी लेकिन उस पिराई में सादे चार परसैंट के हिसाब से चीनी की रिकवरी हुई जबकि हरियाणा मे दूसरी जगहों पर यह रिकवरी सादे नौ परसेंट से लेकर दस परसैंट तक है।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, अब आप बैठे।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से नहीं चल पाएगा। अभी तो मै आपके हित की बात करने जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, और सारी बातों को तो आप छोड़िए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। धान औने दोने दाम पर खरीदा गया। केन्द्र सरकार की तरफ से किसान को धान पर बोनस दिया गया और वह पैसा हरियाणा सरकार के पास आ भी गया। पंजाब के लोगों को या दूसरे प्रदेशों के लोगों को वह बोनस बांट भी दिया गया लेकिन हमारे किसान को उस बोनस का अब तक भी एक नया पैसा नहीं दिया गया। वह पैसा इसलिए उनको नहीं मिला क्योकि वह पैसा सरकार ने दूसरे मदो पर खर्च कर दिया।

Pandit Kuldip Sharma: Sir, Mr. Chautala is a very senior member of this House and his statement so far has been totally misleading and away from facts. (noise & interruptions)

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये कैसे बोल रहा है, आपकी अनुमति से बोल रहा है क्या?

Mr. Speaker: Chautala Sahib, you please sit down and improve your language (Noises & Interruptions)

Pandit Kuldip Sharma: Sir, I want to tell you that he read out the letter of the Chief Minister and he added the contents thereof. Probably English is a language of under-statement and he does not understand it firmly as to what it was written therein. He says that industries ran away from Haryana. I belong to a constituency like Gannuar where a BST unit was there which was giving rich remuneratives to the State. (Noise & interruptions). In his regime, due to their criminal attitude on their part, it was stopped from functioning since 25 years. (Noise & Interruptions) Speaker Sir, because the Hon'ble Member said that the industry was deserting from Haryana.

श्री अशोक कुमार अरोडा: ये बताएं कि क्या किसी को बोनस दिया है? (शोर एवं व्यवधान)

Pandit Kuldip Sharma: Sir, he has no right to speak.

श्री अशोक कुमार अरोडा: ये कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

ये हर बार ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पंडित जी, आप बैठ जाइए। अरोड़ा साहब, आप भी बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

Pandit Kuldip Sharma: Sir, He is not making the truth. Sir, total wrong statement of facts. सर, नरेश शर्मा ठीक ही था बस उसको यह नहीं बोलना चाहिए था कि चौटाला साहब झूठ बोल रहे हैं बल्कि ये कहना चाहिए था कि ये सच नहीं बोल रहे हैं।

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये कैसे बोल रहा है आपकी अनुमति लेकर बोल रहा है क्या? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, किसानों की जमीनों को किस प्रकार बेदर्दी से लूटा जा रहा है। हमारी सरकार के वक्त में हिसार में एक जमीन का टुकड़ा मार्किटिंग बोर्ड ने अधिग्रहित किया था, वहां हमने एक अच्छी सब्जी मंडी बनाने का निर्णय लिया था, उस जमीन को इन्होंने औने– पीने दाम पर एक ऐसे उद्योगपति जो संयोग से आजकल पार्लियामैंट का सदस्य है, को दे दिया। उसके लिए लोगों ने शोर भी मचाया था। आज के दिन ट्रेजरी बैंचिज में बैठे कांग्रेस पार्टी के चौ० संपत सिंह ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उभरकर उठाया था। उनसे पूरी जानकारी हासिल कर लेना कि किस तरह से लूट मचाई गई? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मुझे आप सिर्फ पांच मिनट का समय और दे दें। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः पांच मिनट नहीं, आप जल्दी खत्म करने की बात करो, जल्दी खत्म करो।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः ठीक है सर, यहां ग्रामीण विकास की बात की जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ये कुछ भी कहे जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आज इस सदन का सदस्य भी नहीं है उसके बारे में ये यहां कहने लग रहे हैं। इन्होंने बजट पर एक लाइन भी नहीं बोली है।

श्री अध्यक्षः थैंक यू चौटाला साहब, जो बजट आया है आप उस पर बोलें।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट से बाहर नहीं जा रहा हूं।

श्री अध्यक्षः बजट पर तो आप हैं ही नहीं।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच के पैरा नं. 55 पर ग्रामीण विकास की बात कही गई है। (शोर एवं व्यवधान) अब बताओ, क्या करूं में। (शोर एवं व्यवधान) ग्रामीण विकास के नाम पर हरियाणा प्रदेश में 96 विलेज सरकार ने मॉडल विलेज घोषित किए। आप सुनकर हैरान होंगे कि 98 को यूं

मानकर चल लें कि एक कांस्टीच्यूएंसी में से एक मॉडल विलेज हो गया, लगभग इतना ही हुआ। लेकिन हुआ क्या कि अम्बाला में 5 गांवों को मॉडल विलेज के लिए चुना गया, फरीदाबाद मे 1 ,फतेहाबाद में 1, गुड़गांव मे 1, हिसार में 9। झज्जर मे 15, जींद में,कैथल मे 6, करनाल मे 1. कुरुक्षेत्र में 3 ,मेवात मे 1, पलवल मे 2, पानीपत में 1, रिवाड़ी मे 4, रोहतक में 1 छ, सोनीपत मे 7 और यमुनानगर में 1 और 4 जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी मॉडल विलेज नहीं है। क्या दोष किया है उन्होंने 7 मैं जानना चाहता हूं कि उनका कौन सा गुनाह है कि एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में 33 विलेज मॉडल घोषित किए जाते हैं और समूचे हरियाणा प्रदेश में 4 जिले ऐसे हैं जिनमें 1 भी मॉडल विलेज नहीं है और वहां सबसे ज्यादा बेकवर्ड लोग हैं जैसे महेन्द्रगढ़ है, सिरसा है, पंचकूला है।

श्री राम किशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ ऑर्डर है।

चौ० ओम प्रकाश चौटाला. मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं वाइंड अप करना चाहता हूं, लेकिन कोई करने दे तब न।

श्री अध्यक्षः बस, चौटाला साहब, अब आप बैठ जाएं। (विध्न) Now, I am calling the other Member to speak.

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, दो बड़े जरूरी मसले हैं मैं उन पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। वैट के नाम

पर हमारी सरकार चली गई क्योकि हमने प्रदेश के हितार्थ वैट लागू किया था। यह हमारा सब्जैक्ट नहीं था। केन्द्र सरकार ने वैट के बारे में तय किया था और हमने उसको मान्यता प्रदान की, हमने वैट लगाया उसकी वजह से सरकार के रिर्सोसिज बढ़े, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार के वित्तमंत्री ने वित्त मंत्रियों की कान्फ्रेंस बुलाई। हमारे वित्त मंत्री प्रो० सम्पत सिंह जी उस मीटिंग में थे। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने भूरी–भूरी प्रशंसा की और ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस पार्लियामैंट में यह कहा कि अगर वैट का लाभ देखना है तो हरियाणा प्रदेश में देखो। उसके बाद जब विधान सभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाई ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह लिखा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो वैट को समाप्त कर दिया जायेगा। उसे भी सरकार ने एक परसेंट ओर बढ़ा दिया। जिन 101 चीजो पर हमने रियायत दी थी उन पर रियायतें और बढ़ा दी। अध्यक्ष महोदय, नमक पर भी वैट लगाया। राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी जी ने डांडी मार्च करके नमक का आन्दोलन किया था। कांग्रेस के नाम पर ओर गांधी जी के नाम पर राज करने वाले लोगों को थोड़ा बहुत भी संकोच नहीं हुआ कि नमक पर भी वैट बढ़ा दिया।

श्री अध्यक्षः अच्छा जी, थैंक यू चोटाला साहब।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अभी दो प्वायंट और रह गये हैं।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, Thank you very much. नहीं, अब नहीं।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से केसे काम चलेगा, आपने आधे घण्टे की बात कही है।

श्री अध्यक्षः आपको बोलते हुए ज्ञ मिनट हो गये हैं, अब आप बैठ जाइये।

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। बजट के ऊपर वित्त मंत्री जी ने है कि हम सरचार्ज लगायेंगे लेकिन यह नहीं बताया कि कितना सरचार्ज लगायेंगे और यहां रमे जाकर के ग्रेस गैलरी में जाकर कहते हैं कि हम 5 प्रतिशत लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, बजट सेशन में बजट प्रस्तुत किया जा रहा हे और वित्त मंत्री यह कहता है कि सरचार्ज लगायेंगे। कितना लगायेंगे यहां उसका उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने से पहले बजट को लीक कर दिया। आपने हमारी प्रिवीलेज मोशन को नहीं माना। आपका अधिकार है नहीं मानेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (केप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर हे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओम प्रकाश चौटालाः अरे, आप अपने रिप्लाई में कह देना। आपको तो वक्त मिलेगा। अगर में गलत कह रहा हूं तो बैठ जाऊंगा। आप अपने रिप्लाई में कह देना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: थैंक यू चौटाला साहब। प्लीज, आप समाप्त कीजिए।

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आज महिला सशक्तिकरण की शताब्दी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं जी, बस कीजिए।

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पास किया जा रहा हे। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के नाम पर एक नये पैसे की राशि इस बजट में नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा चौटाला साहब, Please wind up. No more.

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह असलियत है, इसको आप केरने नकारोगे? इसके लिए आप लोग कहोगे। महिला सशक्तिकरण वर्ष है। मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर इस बारे मे कहा था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इन्सान अतीत से सीखता है, भविष्य की कल्पना करता है। मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी अतीत से सीखकर कुछ करोगे। उसके बाद बजट पेश हुआ तब भी उसमें कोई उल्लेख नहीं।

Mr. Speaker: Any how, thank you very much.

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। युवाओं के लिए एक नये पैसे का बजट में प्रावधान नहीं है।

Mr. Speaker: Thank you very much Chautala Sahib. प्लीज, आप बैठिये। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया। I am calling frm BJP now. (interruptions) Mr. Gujjar to start. चौटाला साहब, आप पिछले पन्द्रह मिनट से कह रहे हैं कि पांच मिनट में बैठता हूं।

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आखरी मद पर अपनी बात कहना चाहूंगा। यह बड़ी इर्म्पोर्टेट है। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर जरूरी बात है।

Mr. Speaker: Mr. Gujjar to Start.

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, कानून–व्यवस्था प्रदेश का अहम मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की कानून–व्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ी हुई है। अगर मैं उसका लेखा–जोखा देने लग जाऊं तो लम्बा समय लग जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: From here onwards Shri Gujjar's speech is recorded only. चौटाला साहब, आप बैठ जाइये। अब श्री कृष्णपाल गुर्जर जी बोलेंगे। चौटाला साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए। (व्यवधान) Nothing to be recorded.

चौ० ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker: No, No, I have not permitted it. नहीं जी, मैं यह इजाजत नहीं दूंगा। Nothing is to be recorded. (Interruptions) Not to be recorded. Nothing is going to be recorded (Interruptions) No more, No more. (Interruptions) Mr. Gujjar may start now. (Interruptions) Everybody to take the seats please. Mr. Gujjar is on his legs. (Interruptions) No, no. It is not going to be recorded. I have given the instructions. It is not going to be recorded. (Interruptions) Thank you very much. मेरे लिए सब मेंबर्स एक जैसे है। All the Members are similar. ये बात नहीं है। (Interruptions) It is not going to be recorded. Mr. Gujjar may start now.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (तिगाव): अध्यक्ष महोदय, कल वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उस पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बजट में जो खामियां हैं मैं उन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह निराशाजनक और किसान विरोधी बजट है। इस बजट में हरियाणा के लिए कुछ नहीं रखा गया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने से पहले सभी सम्मानित साथियो से एक बात कहना चाहूंगा कि जो ब्राह्मण को खाते हुए टोकता है, गुर्जर को बोलते हुए टोकता है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है।(विध्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने का मकसद किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं है। इरा सरकार की जो नाकामयाबिया हैं मैं उनके बारे में कुछ अच्छे

सुझाव देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर इनको मेरे सुझाव अच्छे लगें तो मान लें और अगर अच्छे न लगें तो न मानें लेकिन मुझे बीच में न टोके। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि यह बजट बड़ा विकास वाला बजट है लेकिन बजट में देखेंगे तो पाएंगे कि बजट मे जो कुल राशि है उसका 25 फीसदी रिपेमैंट और इंट्रस्ट पर जा रहा हे। इंट्रस्ट और रिपेमैट कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं इस बारे मे सरकार बताए। अध्यक्ष महोदय, फिसकल डैफीसिट लगातार बढ़ रहा है। अर्थशास्त्र का सीधा सा सिद्धांत है कि जब भी फिसकल डैफीसिट बढ़ेगा, इकलेशन यानि मुद्रास्फीति कभी भी कम नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, इस हिन्दुस्तान का और हरियाणा का आम आदमी नहीं जानता कि मुद्रास्फीति क्या है, विकास दर क्या है। वह सिर्फ यही जानता है कि मुझे आटा किस रेट पर मिल रहा है, मुझे चीनी किस रेट पर मिल रही है और तेल किस रेट पर मिल रहा है। देश के सबरने बड़े अर्थशास्त्री माननीय मनमोहन सिंह जी जब इस देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान हुए थे तो लोगो को उनसे बड़ी उम्मीदें बंधी थी लेकिन उन्होंने इस देश और प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उनको निराश कर दिया। जब प्रदेश में मेरे मित्र कैप्टन अजय सिंह यादव जी वित्त मंत्री बने थे तो उनसे हमे कोई उम्मीदें थीं ही नहीं और इस बात को उन्होंने यह बजट पेश करके सिद्ध भी कर दिया है क्योंकि यह इनका विषय ही नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट में बहुत

सी चीजों को बढ़ावा देने की बात की गई हे। में उद्योगों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। बजट मे उद्योगो को भी बढावा देने की बात करते हुए कहा गया है कि सरकार नई उद्योग नीति लेकर आयेगी जिसके तहत बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन उद्योगो के लिए बजट में राशि कम कर दी गई है। बजट में उद्योगो के लिए राशि कम करने से प्रदेश मे उद्योग कहां से लगेगे? इसी प्रकार से बजट में दर्शाया गया है कि सोशल वेल्फेयर और एस.सीज., एसटीज. के उत्थान के लिए बहुत काम किए जायेगे लेकिन budget at a glance में देखेंगे तो पता चलता है कि उनके लिए भी राशि में कहाता की गई है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आप को–ओपरेशन मे देखिये, रोड्ज ओर बिल्डिंग में देखिये, हर फील्ड में राशि कम की गई हे। आज के दिन प्रदेश में सड्कों की हालत बहुत खराब है। मेरे काबिल दोस्त श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो कि पीडब्ल्यूडी. (बी. एंड आर) मिनिस्टर हैं, हरियाणा को नम्बर– 1 बनाने की बात करते हैं। ये यमुनानगर से खिजराबाद, यमुनानगर से देवधर वाली रोड्ज पर जायें तब पता चल जायेगा कि नम्बर– 1 किसको कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अच्छी सड़को के बिना किसी भी प्रदेश के विकास की बात करना बेमानी है लेकिन सड़कों की राशि में भी कटौती की गई है। अध्यक्ष महोदय, ये लोग उच्च शिक्षा की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी लाने की बात करते हैं लेकिन उसकी भी राशि बजट में कम कर दी गई है। इसी तरह से बुढ़ापा पैंशन सरकार ने 300 से 500 रुपये और 700 रुपये कर दी। बुढ़ापा पैंशन के लिए बजट मे

प्रावधान वर्ष 2009–10 के लिए करीबन 2190 करोड़ रुपये का था जिसमें केवल मात्र 110 करोड़ रुपये की बढौत्तरी करके 2300 करोड़ रुपये किया गया है इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि यह पैंशन किस तरह से बढ़ाई गई हेर इसमें राशि की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार बजट में विकास की बात कर रही हैं लेकिन आम आदमी पूछता हे कि विकास किसका हो रहा है। आज के दिन गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है तथा अमीर आदमी का बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। यह सरकार की आर्थिक नीतियो के कारण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले सरकार कहती थी कि उनका खजाना लबा–लब भरा हुआ है लेकिन अब पता नहीं कहां से खाली हो गया। रोशन दूर नहीं था नजदीक था इसलिए किसी चीज के रेट बढ़ाने थे तो सैशन मे बढ़ा देते लेकिन ये सारे काम चोर दरवाजे से करते हैं। मौजूदा सरकार ने सत्र से पहले चुनाव में वैट की समाप्ति की बात की थी लेकिन उसको 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया और कल बजट में सरचार्ज भी लगा दिया। इसी तरह से चुनाव से पहले पैट्रोल और डीजल के भाव घटाये और चुनाव होने के बाद फिर बढा दिये। में परसों सदन में नहीं था उस समय मेरे काबिल दोस्त सुरजेवाला जी कह रहे थे कि एनडी.ए. के राज मे डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़े थे। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि एनडी.ए. के राज में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे लेकिन उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पैट्रोल और डीजल की कीमते 160 रुपये प्रति बैरल हो गई

थी। कांग्रेस के राज में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे पेट्रोल और डीजल के भाव 40 रुपये प्रति बेरल तक आ गये थे। लेकिन पैट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किये गये हैं। आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे पैट्रोल और डीजल के दाम 70 से लेकर 75 डालर प्रति बैरल हैं लेकिन फिर भी डीजल और पैट्रोल के दाम 2.50 रूपये से लेकर 3 रूपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिये गये। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि केन्द्र सरकार का यह कदम न तो किसान के हित में है और न ही मजदूर के हित में हे क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बदाने से महंगाई किसी भी प्रकार से कम होने वाली नहीं हे बल्कि इससे महंगाई और बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 महीने के दौरान महंगाई मे 20 से 30 फीसदी का इजाफा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज आम आदमी त्राहि–त्राहि कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत से विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप देखिए आज सरकार के लैवल पर किसानों और मजदूरों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, किसान और मजदूर गुरबत में और बीमारी की हालत में भी अपनी जमीन और गहने दोनों चीजों को प्रत्येक प्रकार की बुरी परिस्थितियो मे इसलिए सम्भाल कर रखता है कि ये चीजे बुरे वक्त में उसके काम आयेंगी। अध्यक्ष महोदय, आज किसान और मजदूर को बड़ी बुरी तरह से लुटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने के लिए ही आरोप नहीं लगा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज आप देखिए कि फरीदाबाद में गांवों की जिन जमीनों का आज के

संदर्भ में मार्किट रेट 2.50 से लेकर 3 करोड़ रूपये प्रति एकड़ है लेकिन सरकार द्वारा आई.एमटी. के नाम पर वे जमीनें केवल 16 – 16 लाख रूपये में ले ली गई हैं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में जो सैक्टर काटे गये हैं उनके रोड्ज बनाने के लिए अभी फरीदाबाद में 1100 एकड़ जमीन और अधिगृहित होनी है। अध्यक्ष महोदय, इससे किसान बहुत परेशान है इसलिए सबकी नजरे हरियाणा प्रदेश के यहां बैठने वाले नुमाइंदों पर लगी हुई हैं। ये जमीने ढाई से तीन करोड़ रूपये कीमत की हैं। सारे रोड्ज उनमे बनाये जाने हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन जमीनो का मुआवजा ढाई से तीन करोड़ रूपये दे और अगर इतना मुआवजा वे नहीं दिला सकते तो कम से कम डेढ़ करोड़ रूपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिलवाने का बंदोबस्त तो वे अवश्य करे क्योकि इन जमीनों का जो कलैक्टर रेट है वह भी 50 लाख रूपये प्रति एकड़ है। सबकी नजरें सरकार पर लगी हुई हैं क्योंकि यहां पर सभी किसान के बेटे बैठे हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरे हाऊस में सर्वसम्मति से यह फैसला किया जाये कि जो भी एनसी. आर. में किसानों की जमीनें हैं सर्वप्रथम तो वे प्राईवेट बिल्डर्ज के लिए अधिगृहित न की जायें। चाहे वे खुली मार्केट में किसी तरह भी बिके और अगर उन्हें प्राईवेट बिल्डर्ज के लिए अधिगृहित किया भी जायेगा तो उनकी कीमत कम से कम ढाई से तीन करोड़ रूपये हो और सरकार उसको कम से कम डेढ़ करोड़ मुआवजा दे, यह किसान के हित मे होगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गुड़गांव में बहुत से गांव हैं। बहुत सी चीजें सरकार के ध्यान मे नहीं हो

सकती इसलिए मैं यह सब सरकार के ध्यान मे लाने के लिए कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों की जमीनों को किस तरह से लूटने की कोशिश हो रही है यह मैं बताना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए सस्ती जमीनों को महंगी जमीनों मे एक्सचेज किया जा रहा है। मैं यहां पर माननीय सदस्य राव धर्मपाल जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बादशाहपुर गांव में इसी प्रकार से एक्सचेंज की गई जमीन को पंचायत को वापिस करवाया था। यह काम उन्होंने पंचायत के हित के लिए किया था इसलिए वे निश्चित रूप से इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं यह चाहता हूं कि अगर आगे से कोइ इस प्रकार से 5 लाख रूपये की जमीन को 5 करोड़ रूपये से एक्सचेंज कर ले तो इसमें सरकार और पंचायत दोनो को बहुत बड़ा नुकसान है। हम चाहते हैं कि मार्केट रेट में सारी जमीने तबदील हो जाये इससे हमें कोई एतराज नहीं हे। सरकार के सामने यह मेरा सुझाव है कि उसको मार्केट रेट पर ही तबदील किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बहुत से केसिज हाईकोर्ट में लम्बित हैं। में उस विषय मे नहीं जाना चाहता लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक नीति बनाई जाये कि पूरे हरियाणा मे सैक्शन 4 और सैक्शन 6 के नोटिस हो जाने के बाद कोई जमीन नहीं छोड़ी जायेगी। आज क्या हो रहा है? मैं गुड़गाँव के बारे मे बताना चाहता हूँ। सैक्शन 4 लगने से पहले जिस जमीन की कीमत साढ़े 3 और 4 करोड़ रूपये थी लेकिन सैक्शन 4 लगा दिया गया तो किसान तो मजबूर और मजलूम है वह सोचता है कि यह तो अर्जित हो रही हे। फिर

उसके पास बिल्डर लॉबी के लोग पहुंचते जाते हैं। आज भी गुड़गाँव में 2 करोड़ रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन सैक्शन 4 का नोटिस हुई जमीनों के एग्रीमैट हो रहे हैं। एग्रीमैट किस तरह के हो रहे हैं उसकी एक प्रति मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस एग्रीमैंट के हिसाब से किसान बच नहीं सकता क्योंकि इसमें किसान पर बहुत शर्तें लगाई गई हैं। इसमे लिखा है कि अगर सैक्शन 4 हट गया तो आपकी पेमेंट कर देगे और अगर सैक्शन 4 लग गया तो मुआवजा हम लेंगे। इसी प्रकार से और भी बहुत सी शर्तें हैं मैं सभी शर्तो को यहाँ पर नहीं बता सकता क्योकि इतना समय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है और मैं बार–बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ज्यादातर लोग किसान कम्यूनिटी से आये हैं। इसलिए अगर 2 करोड़ रूपये मे 4 करोड़ रूपये की जमीन वे लोग खरीद रहे हैं तो ऐसे किसानो को लुटने से बचाया जाये। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो खेल हो रहा है इससे किसान को बचाने के लिये या तो किसानो को खुले बाजार में अपनी जमीन बेचने दी जाये और यदि सैक्शन 4 का नोटिस हो गया है तो उनको मार्केट रेट का मुआवजा देकर सरकार अपने सैक्टर बनाये, किसी को अलाट करे ताकि किसान को उसका लाभ मिल सके। इस बारे में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बजट की बात है, घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हम वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि घाटे को रोकने के सरकार क्या उपाय करेगी? अध्यक्ष महोदय, महंगाई पर बोलूंगा तो बहुत समय लग जायेगा लेकिन आज

किसान के लिए बिजली और पानी सबसे अहम हैं। आज बिजली की हालत ठीक नहीं है। मुझे आज भी याद हे कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहली बार सत्ता सम्भाली थी तो इन्होने कहा था कि 3 साल बाद हम 24 घंटे बिजली देंगे लेकिन 5 साल गुजर गये और आज भी बिजली मंत्री जी वही बात कह रहे हैं कि हम 2 साल बाद 24 घंटे बिजली देंगे।

श्री अध्यक्षः आप जल्दी कीजिए आपको 20 मिनट हो गये हैं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप तो नहीं लगा रहा और न ही मेरा कोई ऐसा मकसद है। अध्यक्ष महोदय, 2000 से 2005 तक हम और माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी भी हमारे साथ ओपोजीशन में बैठते थे तो उस वक्त कांग्रेस के टाईम में से मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए कहा करते थे अगर आज मुझे थोड़ा सा समय और दे दिया जायेगा तो कोई हर्ज नहीं है क्योकि मैं सुझाव ही दे रहा हूँ। स्पीकर सर, हम यह जानना चाहते हैं कि बिजली का कोई महीना, कोई तारीख या कोई साल तो तय कर दिया जाये कि ये दो साल या तीन साल उक्त तारीख को पूरे हो जायेगे। अध्यक्ष महोदय, 2 साल कहने से बिजली मिलने वाली तो है नहीं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा मे क्या होता है? आप अब देखिये लोग कहीं पर महीने में सेलीब्रेट करते हैं और कहीं पर दो महीने मे

सैलीब्रेट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब गर्मियाँ शुरू हो जायेगी तो हरियाणा मे लोग 2 घंटे में सैलीब्रेट करना शुरू कर देगे।

श्री आनन्द सिंह दांगीः कैसे सेलीब्रेट करेगे?

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः वे ऐसे सैलीब्रेट करेगे दौगी साहब। बिजली तो आती नहीं और दो घंटे बाद जब अचानक बिजली आयेगी तो लोग कहेगे ''बिजली आ गई ओए' ''बिजली आ गई ओए''। अध्यक्ष महोदय, यह सेलीब्रेशन हरियाणा में अलग मिसाल है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, हर दो घंटे बाद जो सेलीब्रेशन होता है, इससे लोगो को छुटकारा मिलना चाहिए। आज वर्ल्ड बैंक की मदद से हरियाणा में बिजली के सुधारीकरण स्कीम के तहत सुधार करने की बात की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सुधारीकरण के बाद लाईन लोसिज बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अगर लाईन लौसिज बढ़ रहे हैं तो सुधारीकरण का कोई फायदा नहीं है। आज रैजीडैशियल सैक्टर और एग्रीकल्चर सैक्टर को बिजली के मामले में अलग–अलग करने की बात की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे लाईन लोसिज बढ़े हैं या घटे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो केबल की जगह कंडक्टर्ज लगाए जा रहे हैं वे पहले से तीन–चार गुणा महंगे हैं और उनकी जगह से जो कंडक्टर्ज उतारे जा रहे हैं उनको कबाड़ में डाला जा रहा हे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह कहना चाहूंगा कि जितने ज्यादा ट्रौसफार्मर्ज बढ़ेंगे, लाईन लौसिज उतने ही ज्यादा होंगे।

श्री अध्यक्षः प्लीज, वाईंड—अप करे। आपको बोलते हुए 24 मिनट हो गए हैं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की समस्या पर आ रहा हूं। किसान आज अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, खाद पर 10 प्रतिशत सबसिडी समाप्त कर दी गई है, पैट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जमीनों को सस्ते दामों पर अधिगृहित किया जा रहा है। आज ये वाह—वाही लूट रहे हैं कि इन्होने ब्याज की दर कम करी है, लेकिन उसमे भी शर्त लगा दी कि जो समय पर किस्त जमा करेगा उसको ही उस छूट का फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, किसान कभी भी समय पर किस्त जमा नहीं कर सकता है। फसल पक जाएगी तो मण्डी मे जाएगी और उससे जो पैसा घर मे आएगा, उससे ही कर्ज की अदायगी करेगा। रनर, मेरा सरकार रवे निवेदन है कि इस शर्त को हटा लिया जाना चाहिए इस शर्त से उनको ब्याज कम करने का कोई फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आज अत्र पैदा करने वाले उत्पादक और अत्र को प्रयोग करने वाले उपभोक्ता दोनो को लूटा जा रहा है। किसान को उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता है और उपभोक्ता को महंगे दामो पर चीजें मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, 2009 मे चीनी 22 रुपए किलो से 50 रुपए किलो हो गई। अरहर की दाल जो अटल जी के राज में 24 रुपए किलो थी वह आज 100 रुपए किलो हो गई है। खाने का तेल 40 रुपए लीटर से 100 रुपए लीटर हो गया है। किस किरन

चीज की बात करूँ, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके दाम न बढ़े हों।

श्री अध्यक्षः प्लीज, वाईड–अप करें। सम्पत सिंह जी अब आप बोले।

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनट और दे दीजिए। मैं दो मिनट मे अपनी बात कहकर समाप्त कर देता हूं। सर, आज हालात क्या हैं? पूरे प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, किसान और मजदूर लाचार हैं, बिजली पानी के लिए हा–हाकार है, मंहगाई की मार है यह कैसी सरकार है? इसलिए सर, सरकार में बैठे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सफलता एक चुनोती हे इसे स्वीकार करो और जहा कमी रह गयी है उसे देखो और सुधार करो। धन्यवाद।

प्रो० सम्पत सिंह (नलवा): स्पीकर सर, मैं आपकी परमीशन से बजट पर बोलना चाहता हूं। सर, माननीय कैप्टन अजय सिंह, वित्त मंत्री जी ने कल 2010–2011 के बजट अनुमान सदन में रखे। उससे पहले तो हर कोई सोच रहा था कि इन पर कितना ज्यादा बोझ है। इस टाईम सारी दुनिया में, हिन्दुस्तान में और स्टेट्स मे जिस तरह के हालात हैं उन हालातों में कैसे स्टेट का वित्त मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी की गाईडैंस और बैलैंसिंग लेकर बजट पेश करेगा? ग्लोबल मार्किट में जो रिसैशन आयी हुई है वह भी इनके सामने थी। इसी तरह से डाक्टर मनमोहन सिंह जी ने

और केन्द्र के वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया तो उनके सामने भी वही बात थी। आज इंडस्ट्रीज, ट्रेड, रैवेन्यू, एफ्लायमैंट, इन्चौरत्तमैंट, रियल एस्टेट्स, स्टैम्प डयूटी और माईज में गिरावट आ रही हैं। जो रिसैशन आया उससे स्वाभाविक है कि स्टाम्प डयूटी से आमदनी गिरती है, कारोबार में भी कमी आती है। मुझे खुशी है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल रिसैशन आया हुआ था उसका असर नहीं पड़ा। अमरीका जैसे देश की इकोनामी हिल गयी, उनके बैंक फेल हो गए लेकिन हिन्दुस्तान के काबिल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और काबिल वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने इस देश को उस बात से अलग रखा जबकि पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन रिसैशन से अलग नही रह सकी है। इसी तरह से हरियाणा के काबिल मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने अपने प्रदेश को दूसरे स्टेट्स से बिलकुल अलग रखा है। उनकी मार तो पड़ी है लेकिन मार के बावजूद प्रदेश को उन्होने बचाया हे और एक प्रोग्रैसिव बजट पेश किया है। मैं इसके लिए उनको बहुत–बहुत बधाई देता हूं। सर, आपको पता ही है कि हमारे हरियाणा के साथ हिमाचल लगता है, उत्तराखंड लगता है। ये स्टेट्स स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। इनको केन्द्र सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा कंसैशंज दी गयी हैं और इन कंसैशंज को आगे भी बढ़ा दिया गया है। सर, यह भी हरियाणा प्रदेश की. आमदनी के लिए एक चौलेंज की बात होती है। वह तो हमारे प्रदेश का एन्वायरमेंट अच्छा है इसलिए लोग यहा पर इंडस्ट्रीज लगाते हैं अदरवाइज कोई आदमी यहां पर इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकता। जिस

तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए टैक्सिज मे सुविधाएं दी गयी हैं और अब उनको और आगे बढा दिया गया है तो वह प्रैशर भी वित्त मंत्री जी के ऊपर जरूर रहा होगा। सर, हमारे प्रदेश का 100 साल का रिकार्ड टूटा है। कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ है। वह प्रैशर भी स्वाभाविक है कि उनके ऊपर जरूर रहा होगा। सर, जो मंहगाई आयी थी उसका भी गवर्नमैंट एक्सपैंडीचर पर असर पड़ रहा था। जब मंहगाई होती है तो अगर आप सड़क बनाएंगे तो वह महंगी बनेगी, यदि आप व्हीकल्ज खरीदेंगे तो वह भी मंहगे पड़ेंगे, यदि आप और कोई निर्माण के कार्य करेगे या इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टेट गवर्नमैंट जितना खर्च करती है उन सब पर मंहगाई का असर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वे बच निकले हैं जिसके लिए मैं इनको बार–बार बधाई देता हूं। स्पीकर सर, इसी तरह से 6th पे कमीशन की रिपोर्ट भी हरियाणा सरकार ने लागू की है। सर, यह अपने आप में एक इतिहास रचा गया है कि तात पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के साथ साथ पहली बार जो कर्मचारियो के एरियर्ज थे, उनको उन्हें कैश देने का काम किया जा रहा है न कि उनको उनके जी०पी०एफ० मे जमा करवाया जा रहा है। सर, एरियर्ज का चालीस परसैंट वर्ष 2006–09 में कर्मचारियों को नकद मे दे दिया गया है और वर्ष 2009– 10 का तीस परसैंट भी 31 मार्च तक उनको कैश में ही दिया जा रहा है और बाकी 30 परसैंट भी वर्ष 2010– 11 में उनको कैश ही दिया जाएगा। स्पीकर सर, यह हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि

6th पे कमीशन की रिपोर्ट का एरियर कर्मचारियो को नकद दिया जा रहा है नहीं तो पहले उनके जी०पी०एफ० मे एडजैस्ट कर दिया जाता था। यह भी एक बहुत सराहनीय कदम है लेकिन इससे स्टेट की इकोनोमी पर असर आना ही था। आप खुद देख रहे हैं कि इससे 4130 करोड़ रुपये का असर आ रहा है। आप जो तनख्वाह देगे, पैंशन देगे, एरियर्ज देंगे, उन सब को मिलाकर 4 हजार करोड़ रुपये रो ऊपर असर आ रहा है, इसलिए ये चीजें बहुत मुश्किल थीं लेकिन वित्तमंत्री जी ने यह करके दिखाया है इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। जो पब्लिक ने दोबारा मेंडेट दिया है उसका प्रैशर भी उन पर स्वाभाविक है। लोगों की आकाक्षाये और अपेक्षायें बढती हैं कि हमने सरकार को दोबारा मत दिया है और वह भी सरकार की कार्यशैली पर और काम करने के तरीके के आधार पर दोबारा मेंडेट दिया है इसलिए उसका भी दिमाग मे प्रैशर रहता है। फर्स्ट टाइम हरियाणा प्रदेश मे ऐसा हुआ है कि दोबारा से वही सरकार आई है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 13वे वित्त आयोग की रिपोर्ट आई, डयूरेशन ऑफ फंड्ज जो कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट से आते हैं वह हमारे पहले 1.075 परसैंट होते थे लेकिन इस बार 1.048 परसेंट हो गये हैं, उससे भी असर पड़ा है। वैसे यह परफौरमैंस बेस्ट होना चाहिए लेकिन पैरामीटर्स ही ऐसे बना रखे हैं। मुझे इस बारे में इसलिए पता है कि मुझे भी प्रदेश में पांच साल वित्त मंत्री रहने का और बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला था। उस समय मैं बार– बार केन्द्र सरकार में कहता था कि इसका मतलब तो हमें काम करने की सजा मिलती है। Haryana is

a performing State. लेकिन यहां भी पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ है। पॉपुलेशन आपकी ज्यादा होगी तो वह फंड देगे। इस हिसाब से जो काम ज्यादा करते हैं, विकास ज्यादा करते हैं, उनको प्रताड़ना मिलती है इसलिए उस चीज से निकलना भी आसान बात नहीं थी। स्पीकर रनर, इसके अलावा दो बातें जो बहुत अच्छी हुई हैं उनके लिए मैं गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री डी. मनमोहन सिंह जी और उनके वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि जो डिवीजिबल मूल है उसमें सैन्ट्रल टैक्सिज मे पहले हमारी स्टेट को 30.5 परसैंट देते थे लेकिन अब उसके स्थान पर 82 परसैंट दिया है, यह डेव प्रतिशत की बढ़ोतरी ही हमारे काम आएगी। वित्तमंत्री जी, मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा क्योंकि कई बार मिसप्लेस हो जाता है कि Share of Central revenue receipts जो पहले 38 परसैंट हमे मिलता था अब वह एक परसैंट बढ़ा दिया गया है यानी अब यह 39 परसैंट मिलेगा। आप इसे थोडी सी बढ़त कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये आसू पोछने वाली बात है बाकी तो सारी तरफ मार ही मार पड़ रही है, उसके बावजूद भी हम बचकर निकलकर आ रहे हैं। अब मैं यह बताना चाहूंगा कि अच्छा बजट क्या होता हे, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। केवल ये कहना कि ये बजट नीरस है, फलाना है ढिकडा है इससे बात नहीं बनती। बजट के मामले में फिगर्ज शो करते हैं कि बजट कैसा है। प्लान एक्सपैंडीचर बढ़ा रहे हैं, नॉन प्लान एक्सपैंडीचर as compared to last year or previous year, अगर आप उसको कम कर रहे हें तो

उसको हम कहेंगे कि बैस्ट बजट है। एक्सपैंडीचर किस प्रकार से कर रहे हैं, अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, रोड्स पर और ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहे हैं, इरीगेशन पर खर्च कर रहे हैं, पावर पर खर्च कर रहे हैं, सोशल बैल्फेयर के लिए खर्च कर रहे हैं, ली एंड ऑर्डर या इम्प्लायमैंट पर खर्च कर रहे हैं तो उसे बैस्ट बजट कहा जाएगा। यूं ही कहने से तो कोई बात नही बनती। कहना बहुत आसान होता है, शब्दो में कोई कुछ भी कह सकता है। हमारे माननीय नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनका मैं आज भी सम्मान करता हूं उनके द्वारा 2 –3 फिग्गर्ज भी दी गई हैं। मैं पहले उन फिगर्ज पर आता हूं। उन्होने कहा था कि हम बजट सरप्लस छोड़ गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय हम सरप्लस छोड़ गए थे। क्योकि मैं वित्त मंत्री था इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2004 –05 में हमने 1572. 18 लाख रुपया सरप्लस छोड़ा था। वर्ष 2005 –06, 2006–07, 2007 –08, 2008–09 मे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी जो कि यहां आज वी. आई.पी. गैलरी में बैठे हैं, ने बजट प्रस्तुत किया था। मैं उनको बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया फाइनेंशियल मैनेजमैंट संभाला जिसकी मिसाल नहीं है। यह जो सरप्लस मनी है वह वर्ष 2005–06 में 31 मार्च को जो पोजीशन होती है, उसके हिसाब से प्लस 3362 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2006–07 में वह प्लस 6399 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2007–08 में प्लस 6346 करोड़ रुपये थी और वर्ष 2008–09 को 2757 करोड़ रुपये थी। अब भी 25 फरवरी की बात है उस दिन वह 1 778.74

करोड़ रुपये थी। यह भी और ज्यादा होती लेकिन छठे पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के कारण एकदम बर्डन आने के कारण स्वाभाविक है कि उसका' असर पड़ा। लेकिन फिर भी 1778 करोड़ रुपये सरप्लस मनी है। मैं यह भी मानता हूं कि मैं कितने फाईनैंशिएल कन्सट्रेंटस में से निकला था। मैं कोई इकोनोमिक्स या कामर्स का विद्यार्थी नहीं था। मैं तो पोलिटिकल साईंस का विद्यार्थी था। चौटाला साहब ने मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी थी उसको पूरा करने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया लेकिन जो रिसोर्सिज आपके पास हैं, उन्हीं में से ही आप एडजैस्ट करोगे। उन लिमिटेड रिसोर्सिज में से काम चलाने का पूरा प्रयास किया गया, मैनेजमैंट करने का पूरा प्रयास किया गया। सीख–सीख कर हमने यह प्रयास किया। आप जैसे जितने ज्ञानी लोग रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग रहे हैं, अनुभवी लोग रहे हैं, राजनीति के लोग, जिनका असैम्बली और पार्लियामैंट का अनुभव रहा है, उन लोगों से सीखकर मैंने यह कार्य किया। मुझे अगर किसी क्लर्क से भी सीखना पड़े तो उसमे कोई संकोच नहीं होता। अगर कोई टर्मिनोलोजी ऐसी आ जाती हे जिसका आपको पता नहीं है तो उसके बारे में अगर आप क्लर्क से भी पूछ लेंगे तो आपको पता लग जायेगा वरना आप हमेशा अज्ञानी रहोगे। मेरी तो यह थ्यौरी रही है इसलिए मैंने लर्निग के लिए हमेशा सीखने का प्रयास किया है। स्पीकर सर, इतना करने के बावजूद भी मुझे कहने मे कोई संकोच नहीं है कि यह बजट बहुत अच्छा है। जैसे कैप्टन साहब ने कहा कि आकड़े मैं भी छिपा सकता था, सुपरैस कर सकता था।

वैसे ही मैं भी उस समय आकड़ो की जगलैरी कर सकता था, लेकिन नहीं। यह वर्ष 2001 –2002 की बात है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 31 मार्च को उस समय माईनस 2333 करोड़ रुपये का बजट वेज एण्ड मीन्ज का था। वर्ष 2002–2003 के आखिर में 31 मार्च को माईनस 178 करोड़ रुपये थे और वर्ष 2004–05 में 1572 करोड़ रुपये हम सरप्लस मे छोड़कर चले गये थे। प्रैजैंट गवर्नमैंट मे जो मैनेजमैंट है इसके लिए मैं कहूंगा कि कैप्टन साहब ने जिस तरीके का रिफोर्म और जिस तरीके का एक अनुशासन बजट में रखा है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। Being an Army Officer and being a seasoned politiciation इन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। ये पोलीटिशिएन के संस्कारों में ही रहे हैं। मैं तो साधारण से एक अनपढ़ मां–बाप का बेटा था, ये तो एक विधायक और बड़े सीजन्ड पोलीटिशिएन के बेटे रहे हैं। राव अभय सिंह जी से भी इनको संस्कार मिले हैं। मैंने प्राईमरी और हाई–स्कूल गाँव से पास किया है जबकि ये तो कन्वैन्ट स्कूल में पढ़े हैं। इस बात का असर तो रहता ही है। स्पीकर सर, इसमे कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने बहुत बढ़िया मैनेजमैंट संभाला है। इससे पहले भी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बहुत बढ़िया मैनेजमैंट संभाला था। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई थी। यह मार तो बाद में आई है जब रिसैशन आया है। इसके बाद पे–कमीशन की रिपोर्ट आई, ये दो मेजर आईटम आई हें इनकी वजह से यह कमी आई है। सर, लोन की बात मैं कहना चाहता हूँ। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश

चौटाला जी ने लोन के बारे मे बात कही कि लोन एमाउंट इतना बढ़ रहा है। स्पीकर सर, मैं आपके सामने दो आकड़े रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रो० साहब, आप कितना टाईम और लेंगे?

प्रो० सम्पत सिंहः सर, जितना टाईम आप देगे। आधा–पौन घण्टा तो और लग जायेगा। स्पीकर सर, 24 जुलाई, 1999 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने उस समय मैं वित्त मंत्री बना था। वर्ष 1999–2000 में जो लोन की लायब्लिटी थी वह 12043 करोड़ रुपये की थी और वर्ष 2004 – 2003 में उस समय तत्कालीन सरकार जाने के बाद 23319 करोड़ रुपये की लायक्तिटी थी। यह लायब्लिटी 93. 63 प्रतिशत बद गई थी। अगर आप वर्ष 2000 या 2001 एक साल बाद से श्री काउंट करते हैं तो यह 66 प्रतिशत बढ़ गई थी। आज यह लायब्लिटी 23319 करोड़ से बढ़कर 38092 करोड़ रुपये हो गयी है। यह वर्ष 2009 – 2010 की है क्योंकि 2010 – 11 की तो आगे आयेगी। मैं फाईव ईयर्ज की बात करता हूं। पांच साल बाद तो यह लायब्लिटी 39092 करोड़ रुपये है। इसका मतलब यह है कि 63 प्रतिशत इन्क्रीज हुई है। इसका मतलब लायब्लिटी पहले से ज्यादा बढ़ी थी क्योकि अब यह लायब्लिटी कम बढ़ी है। इसी तरीके से अभी साल्ट का जिक्र आया था।

Mr. Speaker: The House is adjourned till tomorrow 10.00 A.M. on Friday, the 12th March, 2010.

***14.00 hrs**

(The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. on Friday, the 12th March, 2010)